R.N.I. No.HIN/2002/8718 www.aksnews.com M.P./BHOPAL/642/2024-26

In Pursuit of Truth

पाक्षिक

अक्स

वर्ष : 22 । अंक : 09
01 से 15 फरवरी 2024
पृष्ठ : 48
मूल्य : 25 रु.

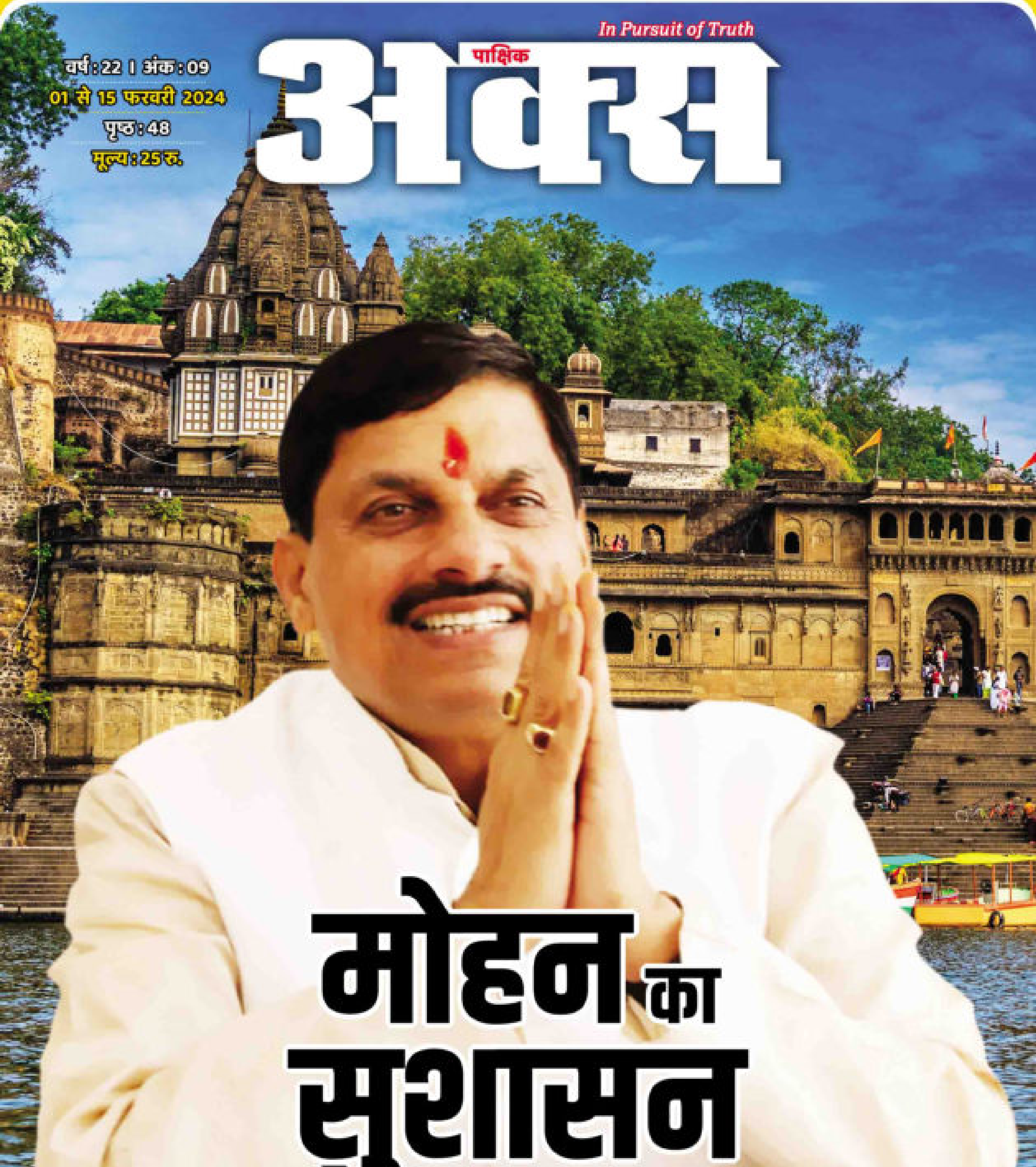

मोहन का सुशासन

प्रदेशवासियों के स्वास्थ्य से लेकर आत्मनिर्भर बनाने तक की पहल

युवाओं, महिलाओं, किसानों, मजदूरों पर सरकार का अधिक फोकस

रामराज्य बनेगा हमारी पहचान

मोदी जी की गारंटी का परिणाम

नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

डॉ. मोहन यादव, मुख्यमंत्री

"प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। 21वीं सदी के भारत में अपार संभावनाएं छुपी हुई है। हम प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में मध्यप्रदेश को जनहित और विकास में सबसे अग्रणी राज्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।"

-डॉ. मोहन यादव, मुख्यमंत्री

एक माह के प्रयास

दो गुना हुआ विश्वास

- लाउडस्पीकर/डीजे का अनियंत्रित प्रयोग प्रतिबंधित
- खुले में मांस, मछली की बिक्री पर प्रतिबंध
- हुकुमचंद मिल के 4800 श्रमिक परिवारों को रू. 224 करोड़ का बकाया भुगतान
- तेंदूपत्ता संग्राहकों का मानदेय रू. 3 हजार प्रति बोरा से बढ़ाकर किया रू. 4 हजार, 35 लाख तेंदूपत्ता संग्राहकों को लगभग रू.165 करोड़ का लाभ
- यातायात सुगमता के लिए भोपाल में बीआरटीएस हटाने का निर्णय
- श्रीअन्न को बढ़ावा देने के लिए रानी दुर्गावती श्रीअन्न प्रोत्साहन योजना में किसानों को प्रति किलो रू. 10 का अतिरिक्त प्रोत्साहन
- दो लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई के विस्तार के लिए रू. 5 हजार करोड़ की परियोजनाएं मंजूर
- नागरिकों की सुविधा के लिए प्रदेश में संभाग, जिले, तहसील एवं पुलिस थानों की सीमाओं के पुनर्निर्धारण की प्रक्रिया प्रारंभ
- एक हजार से अधिक पुलिसकर्मियों को पदोन्नति
- उज्जैन, इंदौर और धार जिले में जहां-जहां भगवान श्रीकृष्ण के चरण पड़े हैं वहां तीर्थ स्थलों का विकास होगा
- प्रदेश में श्रीराम वन पथ गमन के विकास की कार्य योजना को चरणबद्ध तरीके से लागू करने का निर्णय
- नई शिक्षा नीति के अंतर्गत विद्यालयों एवं महाविद्यालयों के पाठ्यक्रम में वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी और रानी दुर्गावती की प्रेरणादायी वीरगाथा के विषय को शामिल करने का निर्णय
- हर जिले में एक शासकीय महाविद्यालय का पीएम उत्कृष्टता महाविद्यालय के रूप में उन्नयन
- रू. 350 करोड़ लागत से 6.67 किमी का इंदौर में बनेगा एलिवेटेड कॉरिडोर
- ग्रीन बॉन्ड जारी कर जुटाए गए रू. 308 करोड़ की राशि से खरगोन जिले के जलूद गांव में ऊर्जा संयंत्र की स्थापना
- स्वच्छ सर्वेक्षण अवॉर्ड 2023 में मध्यप्रदेश फिर आगे, इंदौर को लगातार सातवीं बार देश की स्वच्छतम सिटी का अवॉर्ड, भोपाल बना देश की स्वच्छतम राजधानी

मध्यप्रदेश शासन

इस अंक में

प्रशासनिक

9 | **पूर्व सीएम-सीएस के करीबियों से...**

मप्र के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की जीरो टॉलरेंस नीति और सुशासन की चर्चा मप्र ही नहीं देशभर में होने लगी है। जिस तरह वे ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं, उससे उनकी प्रशासनिक क्षमता भी दिखने लगी है। यही नहीं...

राजपथ

10-11 | **जिताऊ चेहरे की खोज**

लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा और कांग्रेस ने प्रत्याशियों की खोज शुरू कर दी है। भाजपा की तरफ से जहां केंद्रीय नेतृत्व और संघ जिताऊ उम्मीदवार के लिए सर्वे करा रहा है, वहीं कांग्रेस की तरफ से ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी...

राजकाज

13 | **दर्जनभर सांसदों का टिकट...**

मिशन 2023 को फतह करने के बाद भाजपा मिशन 2024 में जुट गई है। पार्टी विधानसभा चुनाव की ही तरह लोकसभा चुनाव लड़ेगी। इसके तहत पार्टी आचार संहिता लगने से पहले ही टिकटों की घोषणा करने की तैयारी कर रही है। सूत्रों का कहना है...

विडंबना

14 | **मनपसंद स्टाफ नहीं रख...**

अभी तक सत्ता, संगठन और संघ के दिशा निर्देशों को दरकिनार कर मनपसंद अधिकारियों-कर्मचारियों को अपने स्टाफ में रखने के आदी मंत्रियों को बड़ा झटका लगा है। सुशासन को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेश के 15 मंत्रियों की सिफारिश नोटशीट लौटा दी है। अपने-अपने चहेतों के...

आवरण कथा 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28

जैसा नाम वैसा शासन का आगाज कर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेश की साढ़े आठ करोड़ आबादी का मन मोह लिया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का अब तक का कार्यकाल ऐसा रहा है जिसमें सुशासन की पूरी झलक देखने को मिली है। जहां उन्होंने विकास कार्यों को गति दी है, वहीं नए कार्यों का भूमिपूजन और लोकार्पण भी किया है। साथ ही जनता के मन में अपनी सरकार होने का भाव भरा है। जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रहे मुख्यमंत्री यादव तत्काल फैसले ले रहे हैं।

15

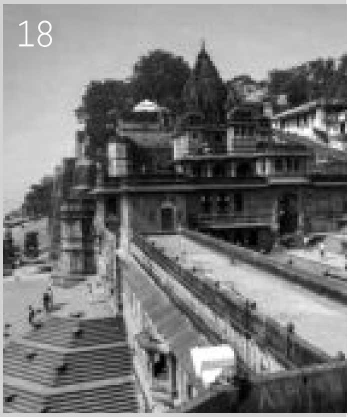
18

37

39

राजनीति

32-33 | **राम मंदिर का चुनावों...**

श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा के बाद की राजनीति कैसी होगी, उसकी झलक दो घटनाओं से मिलती है। कांग्रेस के नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने अयोध्या पहुंचकर कहा कि भले ही जन्मभूमि मंदिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बना है, लेकिन अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री...

चर्चा में

36 | **पाताल की ओर जा...**

भारतीय टेक्टोनिक प्लेट दो टुकड़ों में बंट रही है। एक हिस्सा चीन के नीचे जा रहा है। दूसरा हिस्सा पाताल में। इस वजह से हिमालय में और हिमालय से बड़ा भूकंप आने की पूरी आशंका है। अगर ऐसा होता है तो भारी तबाही होगी। भारत, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, तिब्बत और भूटान जैसे देशों...

उप्र

38 | **धार्मिक पर्यटन की धुरी...**

उप्र ने बीते दो सालों में जिस तेजी से धार्मिक पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित किया है, उससे साफ जाहिर है कि धार्मिक पर्यटन के लिहाज से आने वाला दशक उप्र का है। जिस राज्य की पहचान मुगल धरोहरों से होती थी, उस राज्य की नई पहचान अब...

6-7	अंदर की बात
40	पड़ोस
41	विदेश
43	कहानी
44	खेल
45	फिल्म
46	व्यंग्य

अपनी बात

विभाग ऐसे जिन्हें खोजते रह जाओगे...

शायर ग़ौस ख़्वाह मख़्वाह हैदराबादी का एक शेर है...

लोग भूलें न कभी, ऐसा तख़ल्लुस रखिए।
नाम तो नाम है बस, नाम में क्या रखा है।।

यह शेर मप्र को इस कदर भा गया है कि उसने भी अपने विभागों के नाम कुछ इस तरह रख दिए हैं कि वे खोजने पर भी नहीं मिलते हैं। आलम यह है कि कुछ विभागों के नाम तो ऐसे हैं कि जो गूगल पर भी नहीं हैं। इसका असर यह हो रहा है कि इन विभागों में काम करवाने के लिए आने वाले लोग विभाग की लोकेशन ढूंढ-ढूंढकर परेशान होते रहते हैं। यही नहीं सरकारें समय-समय पर विभागों के नाम भी बदलती रहती है। इस कारण आम लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है। विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जनजाति कल्याण विभाग, पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन, राज्य नगर नियोजन संस्थान, मप्र राज्य होम्योपैथी परिषद, मप्र राज्य दंत परिषद, संत रविदास मप्र हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम लिमिटेड, प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति, मप्र एजेंसी फॉर प्रमोशन ऑफ इन्फारमेशन टेक्नॉलॉजी आदि, ऐसे न जाने कितने विभाग मप्र में चल रहे हैं, जिनकी जानकारी अफसरों को भी नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ये विभाग सिर्फ अधिकारियों, कर्मचारियों की पदस्थापना के लिए ही है। गौरतलब है कि शेक्सपियर ने कहा था- नाम में क्या रखा है। लगता है मप्र में इसे गंभीरता से ले लिया है। उसे इस बात का एहसास नहीं है कि अगर गुलाब को किसी अन्य नाम से पुकारें तो क्या, खुशबू तो उतनी ही देगा। यदि किसी व्यक्ति का नाम दारासिंह है तो जरूरी नहीं कि वह पहलवान दारासिंह जैसा ही बलशाली होगा। सुभाष चंद्र नाम रखने से कोई सुभाष चंद्र बोस तो नहीं हो सकता। अतः किसी व्यक्ति के कार्य महत्वपूर्ण हैं। परंतु यह भी सही है कि नाम बिना भी काम नहीं चलेगा। हर व्यक्ति या विभाग की पहचान तो उसका नाम ही है। अतः नाम और काम दोनों अपने-अपने स्थान पर सही हैं। यही नहीं मप्र में कब किस विभाग का नाम बदल जाए, कोई नहीं जानता। गौरतलब है कि कमलनाथ सरकार ने आनंद और धर्मस्व को मिलाकर आध्यात्म विभाग बनाया था। जिसे शिवराज सरकार ने बदल दिया था। अब इसे आध्यात्म विभाग धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग के नाम से जाना जाता है। शिवराज सरकार ने आनंद विभाग का गठन और आध्यात्म विभाग का नाम बदलकर धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग कर दिया है। आनंद विभाग वर्ष 2016 में शिवराज सरकार ने बनाया था। कमलनाथ सरकार ने आनंद विभाग को धर्मस्व विभाग के साथ मिलाकर आध्यात्म विभाग बना दिया था। वहीं विगत दिनों मप्र के मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला लेते हुए लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग और चिकित्सा शिक्षा विभाग का विलय करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग और चिकित्सा शिक्षा विभाग का विलय कर लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के रूप में पुनर्गठित किया जाएगा। सरकार का कहना है कि इस विलय के साथ विभागों के कार्य करने की क्षमता भी बढ़ेगी। इसमें मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल के बीच अब तक जो समन्वय की स्थिति नहीं रहती थी, अब वो हो सकेगी। जिससे निश्चित तौर पर प्रदेश की जनता को इसका लाभ मिलेगा। यहां यह बात मान भी लें तो लोगों की परेशानी के बारे में कौन सोचेगा, क्योंकि वर्षों से लोगों के दिमाग में पुराने नाम पूरी तरह बस गए हैं।

- राजेन्द्र आगाल

पाक्षिक अक्स

वर्ष 22, अंक 9, पृष्ठ-48, 1 से 15 फरवरी, 2024

प्रकाशक एवं संपादक : राजेन्द्र आगाल

सम्पादकीय कार्यालय :
प्लाट नम्बर 150, जोन-1 मनोरमा कॉम्पलेक्स,
एफ-03, 04, प्रथम तल, एम.पी. नगर
भोपाल- 462011 (म.प्र.),
फोन नं. 0755-2557777, टेलीफेक्स - 0755-4017788
email : akshmagazine@gmail.com
W ebsite : www.akshnews.com
RNI NO. HIN/2002/8718 MPBPL/642/2021-23

ब्यूरो
कोलकाता:- इंद्रकुमार, **छत्तीसगढ़:**- संजय शुक्ला, मार्कण्डेय तिवारी, **जयपुर:**- आर.के. बिन्नानी, **लखनऊ :**- मधु आलोक निगम।

प्रदेश संवाददाता
094251 25096 (इंदौर) विकास दुबे
098276 18400 (जबलपुर) धर्मेन्द्र कथूरिया
094259 85070, (उज्जैन) श्यामसिंह सिकरवार
089823 27267, (रतलाम) सुभाष सोमानी
075666 71111, (विदिशा) मोहित बंसल

क्षेत्रीय कार्यालय
नई दिल्ली : ईसी 294 माया इंक्लेव मायापुरी फोन : 9811017939
जयपुर : सी-37, शांतिपथ, श्याम नगर (राजस्थान) मोबाइल-09829 010331
रायपुर : एमआईजी 1 सेक्टर-3 शंकर नगर, फोन : 0771 2282517
भिलाई : नेहरू भवन के सामने, सुपेला, रामनगर, भिलाई, मोबाइल 094241 08015
इंदौर : नवीन रघुवंशी, रघुवंशी कॉलोनी, इंदौर, मो.-9827227000
देवास : जय सिंह, देवास मो.-7000526104, 9907353976

स्वात्वाधिकारी, मुद्रक व प्रकाशक, राजेन्द्र आगाल द्वारा आगाल प्रिंटर्स, प्लाट नं. 150, जोन-1, प्रथम तल, एफ-03, मनोरमा काम्पलेक्स, एम.पी. नगर भोपाल 462011 (म.प्र.), से मुद्रित एवं प्रकाशित

इस अंक में प्रकाशित सामग्री लेखकों के अपने विचार हैं इनसे सम्पादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं हैं समस्त विवादों के लिए न्याय क्षेत्र भोपाल होगा।

इंदौर फिर नंबर-1

शहरी स्वच्छता का यह आठवां संस्करण है, जिसमें सात बार लगातार इंदौर नंबर वन आया। मगर गत वर्ष की तरह इस बार भी सूरत ने न सिर्फ कड़ी टक्कर दी, बल्कि इंदौर की बराबरी में आ खड़ा हुआ। लेकिन इंदौर ने एक बार फिर बाजी मारकर खिताब अपने नाम कर लिया है।

● **अनिल दुबे,** इंदौर (म.प्र.)

चुनावी तैयारी

लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल जीतने के बाद भाजपा की नजरें अब फाइनल यानी लोकसभा चुनाव पर हैं। भाजपा मिशन 2024 की तैयारी में पूरी तरह जुट गई है। इसके लिए भाजपा विधानसभा चुनाव वाली रणनीति पर ही काम कर रही है। वहीं कांग्रेस भी तैयारी में जुट चुकी है।

● **राहुल वर्मा,** भोपाल (म.प्र.)

मध्यमवर्ग पर भार!

प्रदेश में मध्यमवर्ग ईमानदारी से अपने बिजली बिलों का भुगतान करता है। इसको देखते हुए बिजली कंपनियां उपभोक्ताओं को एक और करंट लगाने की तैयारी कर रही हैं। इससे न सिर्फ बिजली कंपनियों को फायदा पहुंचेगा, बल्कि उपभोक्ताओं की जेब पर भी असर पड़ेगा।

● **रूपाली सिंह,** रायसेन (म.प्र.)

राम मंदिर से जुड़ी है करोड़ों लोगों की आस्था

राम मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा मुद्दा है। यह मुद्दा दशकों तक देश की सियासत की धुरी रहा है। 22 जनवरी को रामलला की अयोध्या के भव्य राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा ऐतिहासिक पल रहा। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के साथ ही विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ समेत तमाम संगठन इस आयोजन को ऐतिहासिक बनाने, दिव्य-भव्य रूप देने में जुटे थे। वहीं, इस आयोजन के सियासी निहितार्थ और 2024 के चुनाव से कनेक्शन पर भी बात हो रही है। राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम से देशभर में जो माहौल भी बना। इस माहौल को भाजपा के लिहाज से लोकसभा चुनाव में जीत की हैट्रिक लगाने के अनुकूल बताया जा रहा है।

● **विवेक मिश्रा,** जबलपुर (म.प्र.)

यात्रा का फायदा क्या?

भारत जोड़ो की तरह राहुल की न्याय यात्रा भी मप्र से होकर भी गुजरेगी। अब कहने को तो कांग्रेस कह रही है कि राहुल गांधी की ये यात्रा आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय के लिए होगी, लेकिन असल सवाल तो ये है कि क्या राहुल गांधी अपनी इस यात्रा के जरिए अपनी खुद की पार्टी कांग्रेस के साथ न्याय कर पाएंगे। राहुल अपनी पिछली यात्रा के दौरान राहुल गांधी जहां से निकले, उन क्षेत्रों मैं पार्टी के उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई।

● **प्रिया साहू,** सीहोर (म.प्र.)

चुनावी मुद्दों में उलझीं पार्टियां

आगामी चुनावों को देखते हुए सभी पार्टियां तैयारियों में जुट चुकी हैं। सत्तापक्ष को हराने के लिए जातिगत जनगणना और ओबीसी आरक्षण विपक्ष का सबसे बड़ा चुनावी हथियार हो सकता है। भाजपा ने इस मुद्दे को बेअसर करने के लिए पहले ही योजना तैयार कर ली है। वह हर राज्य की सरकार, पार्टी संगठन में हर वर्ग के लोगों की भागीदारी सुनिश्चित कर रही है। हाल ही में बनी राजस्थान, मप्र और छत्तीसगढ़ की सरकारों में ओबीसी, दलित, आदिवासी और ब्राह्मण सबको उचित भागीदारी देकर उन्हें साथ लेने की कोशिश की गई है।

● **देवेंद्र ठाकुर,** नई दिल्ली

पाठकों से निवेदन

कृपया अपनी प्रतिक्रियाएं पक्ष या विपक्ष जो भी संभव हो इस पते पर भेजें

अक्स

150 जोन-1, मनोरमा काम्पलेक्स,
एफ-02, 03, एमपी नगर, भोपाल

दल बदल सकते हैं दानिश अली

हाल ही में बहुजन समाज पार्टी से निष्कासित किए गए दानिश अली एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। उन्होंने कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने का ऐलान कर कहा है कि ये फैसला मेरे लिए एक बहुत ही अहम है। इसे मैंने बहुत सोच समझकर लिया है। कांग्रेस की यात्रा में इसलिए शामिल हो रहा हूं, क्योंकि यह अन्याय के खिलाफ आंदोलन है। न्याय के लिए लड़ना गलत बात नहीं है। दानिश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि जिस समय देश की सत्ताधारी दल के नेता ने उन पर संसद में टिप्पणी की थी उस समय मुझे और मेरे परिवार को हौंसला देने वाले राहुल गांधी ही देश के पहले नेता थे। उनके इस पोस्ट के बाद अटकलें लगाई जा रही हैं कि वे कांग्रेस का हाथ थाम सकते हैं। हालांकि कांग्रेस में शामिल होने की बात पर उन्होंने कहा कि मैं बसपा का सिपाही हूं, लेकिन अन्याय के खिलाफ कांग्रेस की इस यात्रा से जुड़ रहा हूं। अमरोहा से सांसद दानिश अली अक्सर चर्चाओं में बने रहते हैं। कभी भाजपाइयों से नोंक-झोंक का मामला हो या फिर संसद में भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी द्वारा की टिप्पणी का मामला। दरअसल, पिछले दिनों बसपा ने दाशिन अली को पार्टी से निष्कासित कर दिया था। जिसके बाद कयास लगाए जा रहे थे कि वह कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं।

एकला चलो की राह पर बसपा

आगामी आम चुनाव की तैयारियों में जुटे उप्र के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा प्रमुख अखिलेश यादव के सुर इन दिनों बदले-बदले से नजर आ रहे हैं। बीते दिनों हुई एक बैठक में उन्होंने पार्टी नेताओं को नसीहत दी कि बहुजन समाज पार्टी पर विवादित बयानबाजी करने से बचें और उनका सम्मान करें। उनके इस अंदाज के बाद अटकलें लगाई जा रही थी कि उन्होंने बसपा के इंडिया अलायंस में शामिल होने पर अपना रुख बदल लिया है और बसपा की इंडिया में एंट्री पर लगाई अपनी नामंजूरी को हटा दिया है। ऐसे में सवाल उठ रहे थे कि क्या अब उप्र में गठबंधन की नई तस्वीर देखने को मिल सकती है। इस बात को बल हाल में दिए गए बसपा सुप्रीमो के बयानों से मिल भी

रहा था। बसपा प्रमुख मायावती ने पिछले दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि विपक्ष के गठबंधन में बसपा सहित अन्य जो भी पार्टियां शामिल नहीं हैं, उनके बारे में किसी का भी टिप्पणी करना उचित नहीं है। मेरी उन्हें सलाह है कि वह इससे बचें, क्योंकि भविष्य में कब किसको, किसकी जरूरत पड़ जाए कुछ भी कहा नहीं जा सकता। मायावती के इस बयान के बाद माना जा रहा था कि उनका यह बयान अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को केंद्रित करके दिया गया है।

किनारा करेंगे कटारिया!

राजस्थान की कांग्रेस सरकार में कृषि मंत्री रह चुके लालचंद कटारिया को लेकर पिछले दिनों चर्चा थी कि वे कांग्रेस छोड़ सकते हैं। इसको लेकर अब सियासी संकेत भी सामने आने लगे हैं। लालचंद कटारिया का उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के साथ मुलाकात का एक फोटो सामने आया है जिसके बाद एक बार फिर चर्चा जोरों पर है कि कटारिया भाजपा का दामन थाम सकते हैं। उपराष्ट्रपति से कटारिया की मुलाकात को इसी संकेत से जोड़कर देखा जा रहा है। लालचंद कटारिया का निर्वाचन क्षेत्र झोटवाड़ा विधानसभा था। लेकिन इस बार उनके क्षेत्र में उनका काफी विरोध रहा। उसको देखते हुए उन्होंने चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया और यह तर्क दिया कि वह राजनीति की जगह अध्यात्म की ओर ध्यान देंगे। तब कटारिया ने कहा कि न तो वे खुद चुनाव लड़ेंगे और न ही उनका कोई करीबी विधानसभा चुनाव लड़ेगा। इसी तरह वन एवं पर्यावरण मंत्री हेमाराम चौधरी ने विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा की थी। मगर बीते दिनों उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ के साथ उनकी मुलाकात के बाद कुछ और ही संकेत देखने को मिल रहे हैं। खास बात यह है कि इस मुलाकात के दौरान आरएसएस से जुड़े हुए पदाधिकारी भी मौजूद थे जो नए रणनीतिक समीकरणों की तरफ इशारा कर रहे हैं।

आसान नहीं शर्मिला की राह

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे वाईएसआर रेड्डी की बेटी वाईएस शर्मिला ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। जगन मोहन रेड्डी की बहन शर्मिला को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। इसके बाद शर्मिला ने कहा, आज में वाईएस तेलंगाना पार्टी का कांग्रेस पार्टी में विलय करते हुए बहुत खुश हूं। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि वाईएस तेलंगाना पार्टी आज से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हिस्सा बनने जा रही है। कांग्रेस पार्टी अभी भी हमारे देश की सबसे बड़ी धर्मनिरपेक्ष पार्टी है। सियासी जानकारों का मानना है कि आंध्र प्रदेश में कांग्रेस शर्मिला के जरिए अपने लिए राजनीतिक जमीन जरूर तैयार करेगी लेकिन शर्मिला को अपने लिए जगह तलाश पाना आसान नहीं होगा। क्योंकि वाईएसआर की विरासत पर आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी अच्छी तरह से काबिज हो चुके हैं। शर्मिला ने कुछ साल पहले अपनी अलग पार्टी बनाकर तेलंगाना में अपनी राजनीति की शुरुआत की थी।

सिरसा से चुनाव लड़ेंगे तंवर

हरियाणा विधानसभा चुनाव में भले ही अभी एक साल का समय शेष है लेकिन नेताओं का दलबदल अभी से शुरू हो गया है। आया राम-गयाराम की राजनीति वाले प्रदेश हरियाणा में पैर जमाने की कोशिश में जुटी आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। आप के चुनाव अभियान कमेटी के चेयरमैन अशोक तंवर पार्टी से इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल हो गए हैं। माना जा रहा है कि भाजपा उन्हें आगामी लोकसभा चुनाव में सिरसा से मैदान में उतार सकती है। गौरतलब है कि अशोक तंवर ने पिछले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद उन्होंने तृणमूल कांग्रेस का दामन थामा था। जब अशोक तंवर कांग्रेस में थे तो उनकी गिनती राहुल गांधी के करीबी नेताओं में होती थी। कांग्रेस छोड़ने के बाद माना जा रहा था कि वे हरियाणा में अपनी पार्टी बनाने का ऐलान कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अप्रैल 2022 में उन्होंने आम आदमी पार्टी को अपना लिया था।

...तो खानी पड़ी ग्वालियर की हवा

मप्र की नौकरशाही की पहचान सरकारी आदेशों-निर्देशों को दरकिनार करने के लिए है। पूर्ववर्ती सरकारों में अक्सर देखा जाता रहा है कि शासन के मुखिया कोई निर्देश देते हैं और अफसर उसे हवा-हवाई फरमान मानकर भूल जाते थे। लेकिन अब सत्ता का चरित्र बदल गया है। अफसरों की थोड़ी सी लापरवाही भी बर्दाश्त नहीं की जा रही है। इस लापरवाही के कारण कई अफसर अभी तक सरकार के कोप का भाजन बन चुके हैं। इन्हीं में से एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी भी हैं। ये साहब 1996 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। सूत्रों का कहना है कि विगत दिनों सरकार के मुखिया की तरफ से उन्हें एक अधिकारी के लिए आदेश निकालने का निर्देश दिया गया था। पूर्ववर्ती सरकारों के चाल-चलन को देख चुके साहब को लगा कि इस बार भी ऐसा ही कुछ होने वाला है। उन्होंने सरकार के मुखिया की बातों पर ध्यान न देते हुए उक्त अधिकारी के लिए आदेश नहीं निकाला। फिर क्या था। जैसे ही सरकार के मुखिया को इसकी भनक लगी उन्होंने आव देखा न ताव वरिष्ठ आईएएस अधिकारी का तबादला करवा दिया। वह भी ऐसी वैसी-जगह नहीं बल्कि ग्वालियर अंचल में। अभी तक राजधानी की प्रशासनिक वीथिका में बैठकर हवाई किले बनाते रहने वाले साहब को अब बीहड़ की हवा से रूबरू होना पड़ रहा है। साहब के करीबियों का कहना है कि उन्हें पुरानी व्यवस्था में काम करने की लत लग चुकी है।

आखिरकार छूट गया पिंड...

डिप्टी कलेक्टर से आईएएस बने एक साहब को इस बात का गुरूर था कि कोई उनका बाल भी बांका नहीं कर सकता। लेकिन साहब जिसके दम पर यह गुरूर दिखा रहे थे, उन्हीं ने उसे चूर-चूर करते हुए उनसे अपना पिंड छुड़ा लिया है। सूत्रों का कहना है कि ये साहब 2016 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। दरअसल, वर्तमान सरकार के मुखिया जब मंत्री थे, तभी से उपरोक्त साहब उनके ओएसडी बने थे। उस दौरान साहब ने कई ऐसी हरकतें कीं, जिससे वे लोगों की आंख की किरकिरी बन गए थे। इन्हीं में से एक मामला तो इतना विवादित था कि जो कोई सुनता था, वही लज्जित हो जाता था। जानकारी के अनुसार मंत्रीजी के यहां जब भी कोई आता तो साहब उससे न्यौछावर लेना नहीं भूलते थे। इसी क्रम में उन्होंने एक प्रोफेसर से मोबाइल फोन ले लिया था। यहां तक तो कुछ हद तक ठीक था, लेकिन साहब का ओछापन देखिए कि उन्होंने उस मोबाइल को राजधानी के एक प्रसिद्ध मार्केट में जाकर बेच दिया। अब वही मंत्रीजी सरकार के मुखिया बन गए हैं और साहब उनके ओएसडी बने रहे। लेकिन एक दिन अचानक माननीय ने उन्हें अपने यहां से चलता कर दिया और उनसे अपना पिंड छुड़ा लिया।

जैसे को तैसा मिला

उपरोक्त कहावत तो आप सभी ने सुनी होगी, लेकिन इसका अहसास गत दिनों 2013 बैच के आईएएस अधिकारी को अच्छी तरह हो गया है। दरअसल, साहब हाल ही में ग्वालियर-चंबल अंचल के एक जिले के कलेक्टर के पद पर पदस्थ हुए हैं। एक तो कलेक्टर उस पर पूर्व प्रशासनिक मुखिया का सुपुत्र होने के कारण साहब का रसूख सातवें आसमान पर रहता है। इसी रसूख के चक्कर में विगत दिनों जब केंद्र सरकार के एक मंत्री जिले के दौरे पर आए तो उनसे मिलने के लिए उनके खास लोग भी पहुंचे। कार्यक्रम स्थल पर व्यवस्था संभाल रहे कलेक्टर साहब ने केंद्रीय मंत्री के कुछ खास लोगों को बड़ी देर तक कतार में खड़ा किए रखा। यही नहीं वे लोग साहब से गुहार लगाते रहे कि हम लोग केंद्रीय मंत्री के खासमखास हैं और उनके बुलावे पर ही आए हैं। लेकिन साहब ने उनकी एक नहीं सुनी। साहब के अड़ियल रुख को देखकर केंद्रीय मंत्री से मुलाकात के लिए वे सभी नेता शांतिपूर्ण लाइन में लगे रहे, फिर जब नेताजी से उनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने कलेक्टर साहब की जमकर शिकायत की। केंद्रीय मंत्री को भी यह बात नागवार गुजरी और उन्होंने मंच से ही कलेक्टर साहब पर जमकर भड़ास निकाली। यही नहीं उन्होंने यहां तक कहा कि सुन लो कलेक्टर, जब तक यहां सभा चलेगी, तुम यहीं खड़े रहोगे। केंद्रीय मंत्री के इस कड़क रुख के बाद साहब आयोजन स्थल पर खड़े रहे और उन्हें अहसास हो गया कि जैसे को तैसा मिल ही जाता है।

बड़े साहब की छोटी करतूत

एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी प्रदेश के मुख्य सचिव बनने की कतार में गिने जा रहे हैं। जब भी मुख्य सचिव की नियुक्ति की हवा चलती है, साहब का भी नाम चर्चा में आ जाता है। वर्षों तक केंद्र में पदस्थ रहे साहब की जब प्रदेश वापसी हुई तो यह चर्चा भी जोरों पर शुरू हो गई कि शायद यही प्रदेश के अगले मुख्य सचिव बनेंगे। लेकिन जब साहब की अचानक प्रदेश वापसी की पड़ताल की गई तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। सूत्रों का कहना है कि साहब की केंद्र से विदाई एक बड़े घोटाले के कारण की गई है। बताया जाता है कि दक्षिण भारत में स्थित एक केंद्र शासित राज्य में हुए एक बड़े घोटाले में साहब की संलिप्तता पाई गई। इस बात की भनक जैसे ही सरकार के मुखिया को लगी, उन्होंने तत्काल उनकी रवानगी के निर्देश दे दिए। कुछ समय तक मुख्य सचिव बनने का सपना देख रहे साहब अब अपने रिटायरमेंट के दिन गिन रहे हैं। हालांकि साहब का रिटायरमेंट अभी दूर है, लेकिन एक घोटाले ने उनकी प्रोफाइल को इस कदर कलंकित कर दिया है कि अब उनके लिए आगे का रास्ता बंद हो गया है।

जांच पर जांच, उलझी पुलिस

राजधानी की पुलिस इन दिनों प्रदेश में सबसे अधिक परेशान है। इसकी वजह है हाईप्रोफाइल मामलों की जांच। दरअसल, राजधानी में हाईप्रोफाइल लोग यानि मंत्री, विधायक, सांसद और अफसर रहते हैं। ऐसे में हर दिन कोई न कोई ऐसा मामला आते ही रहता है, जिसमें पुलिस उलझती ही रहती है। वर्तमान समय में दो मामले ऐसे सामने आए हैं, जिसने पुलिस को परेशानी में डाल दिया है। एक मामला भारी भरकम विभाग से जुड़े मंत्री का है। दरअसल, कोई व्यक्ति मंत्रीजी के बेटे और उनके ओएसडी के नाम पर अफसरों को फोन कर रकम मांगता है। वहीं एक मामला एक आईएएस अधिकारी की चैट का भी है। इन मामलों की जांच में पुलिस तो जुटी हुई है, लेकिन इसके अलावा शहर में कोई न कोई ऐसी वारदात होती रहती है, जिसमें पुलिस उलझकर रह गई है। आलम यह है कि पुलिस वालों को यह समझ में नहीं आ रहा है कि वह किस तरह कानून व्यवस्था को संभाले। एक पकड़ो तो दूसरा छूट जाता है की तर्ज पर राजधानी की पुलिस परेशानी के दौर से गुजर रही है।

हनी ट्रैप की फिर होगी जांच

ब्यूरोक्रेट्स और नेताओं के नाम होंगे उजागर

ब्यूरोक्रेट्स और नेताओं के वीडियो क्लिप बाहर आने के बाद एसआईटी ने इस मामले में नाम कभी उजागर नहीं किए। तत्कालीन एसआईटी चीफ ने स्वीकार किया था कि उच्चतम वेतनमान वाले आईएएस और आईपीएस के अलावा भाजपा-कांग्रेस के अनेक नेता भी आरोपी महिलाओं के बेहद नजदीक थे। लेकिन उनके नाम दस्तावेजों पर नहीं लिए गए। भाजपा सरकार के एक पूर्व मंत्री और मुख्यमंत्री के नजदीकी सीनियर आईएएस अधिकारी के ऑडियो-वीडियो तो मीडिया में भी आ चुके थे। मानव तस्करी केस में पीड़िता ने अरुण निगम, हरीश खरे सहित छतरपुर के स्थानीय नेता मनोज त्रिवेदी, चुलबुल पांडे, टिल्लू और जयपुर के राजेश गंगेले का नाम लिया था। अरुण निगम कांग्रेस सरकार में खनिज मंत्री प्रदीप जायसवाल के विशेष सहायक थे। पीड़िता ने अपने बयान में बताया था कि अरुण निगम के भी वीडियो बने हैं, लेकिन एसआईटी ने इन बिंदुओं की जांच में क्या पाया, ये सामने ही नहीं आया। हनीट्रैप की आरोपी महिलाओं के एनजीओ को सीनियर ब्यूरोक्रेट्स ने कितना फायदा पहुंचाया, इसकी भी अब तक जांच नहीं हो पाई। मानव तस्करी केस की पीड़िता ने आरोपी के एनजीओ दृष्टि और जागृति का भी जिक्र किया था। इनके पास से अफसरों की मुहर भी बरामद हुई थी। तत्कालीन एसआईटी चीफ संजीव शमी ने कहा था कि ये जांच का विषय होगा कि अफसरों ने आरोपी महिलाओं के एनजीओ को किस तरह और कितना फायदा पहुंचाया था। यदि उनकी भूमिका पाई जाएगी तो उनके खिलाफ पद के दुरुपयोग और सरकारी धन के आवंटन में गड़बड़ी का केस दर्ज किया जाएगा। ये तीनों बिंदु इसलिए भी अहम हैं क्योंकि एसआईटी ने कोर्ट में खुद कहा था कि अभी मामले में आगे जांच चल रही है। लेकिन 4 साल बाद भी एसआईटी ने नए नामों का खुलासा नहीं किया।

मप्र का सबसे चर्चित सेक्स स्कैंडल हनीट्रैप केस चार साल बाद फिर सुर्खियों में है। इस बार चर्चा इसलिए क्योंकि सरकार ने एसआईटी चीफ के रूप में एडीजी इंटेलीजेंस रहे आदर्श कटियार को नियुक्त किया है। आदर्श कटियार साफ-सुथरी छवि के अधिकारी माने जाते हैं। ये भी कहा जाता है कि वे किसी के दबाव-प्रभाव में नहीं आते। कटियार द्वारा एसआईटी की कमान संभालने के बाद 29 जनवरी को इंदौर कोर्ट में हनीट्रैप मामले में सुनवाई हुई, जिसमें कहा गया कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ कोई सहयोग नहीं कर रहे हैं। गौरतलब है कि हनीट्रैप मामले का खुलासा सितंबर 2019 को तब हुआ था, जब प्रदेश में कांग्रेस की कमलनाथ सरकार थी। इंदौर नगर निगम के इंजीनियर हरभजन ने पलासिया थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि अश्लील वीडियो भेजकर उनसे 3 करोड़ रुपए मांगे जा रहे हैं।

17 सितंबर 2019 को इंदौर नगर निगम के इंजीनियर हरभजन सिंह ने शिकायत की थी कि उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है। इस शिकायत पर पुलिस ने 19 सितंबर को हनीट्रैप का खुलासा किया था। हनीट्रैप और ब्लैकमेल कर हरभजन सिंह से 3 करोड़ रुपए मांगने के आरोप में पुलिस ने इंदौर और भोपाल से पांच युवतियों आरती दयाल, मोनिका यादव, श्वेता जैन (पति विजय जैन) श्वेता जैन (पति स्वप्निल जैन), बरखा सोनी को गिरफ्तार किया था। इनके एक वाहन चालक ओमप्रकाश कोरी को भी गिरफ्तार किया गया था। वर्तमान में सभी जमानत पर बाहर हैं। 24 सितंबर 2019 को मानव तस्करी के दूसरे केस में भोपाल के सीआईडी थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। इसमें पीड़िता ने बताया था कि आरोपी महिलाओं ने उसे रसूखदार लोगों के पास भेजकर उनके आपत्तिजनक वीडियो बनवाए। इन वीडियो के बदले उन लोगों को ब्लैकमेल कर उनसे वसूली की गई। पीड़िता ने कई अफसरों व प्रभावशाली लोगों के नाम भी पुलिस को बताए थे। इसी आधार पर ये एफआईआर दर्ज की गई थी। इंदौर और भोपाल कोर्ट में बीते 4 सालों से इस केस की सुनवाई चल रही है।

हनीट्रैप केस में 29 जनवरी को इंदौर कोर्ट में पेशी हुई। इस पेशी में सरकार को जवाब देना था कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को जो नोटिस भेजा था, उस पर क्या एक्शन हुआ? दरअसल, कमलनाथ ने 21 मई 2021 को प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया से कहा था कि उनके पास हनीट्रैप की पूरी सीडी और पेन ड्राइव है। इस पर आरोपियों के वकील यावर खान ने आपत्ति लगाकर पूछा था कि ये पेन ड्राइव कमलनाथ के पास कैसे पहुंची? इस पर एसआईटी के इंस्पेक्टर शशिकांत चौरसिया ने कोर्ट को दिए अपने बयान में कहा था कि पेन ड्राइव हासिल करने के लिए कमलनाथ को नोटिस दिया गया है। नवंबर 2023 में एसआईटी ने अपने जवाब में कहा था कि एसआईटी चीफ विपिन माहेश्वरी रिटायर हो चुके हैं, नए चीफ बनने के बाद ही इस पर जवाब दाखिल किया जाएगा। 29 जनवरी को हुई सुनवाई में एसआईटी को जवाब देना था कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के पास पेन ड्राइव कैसे पहुंची? क्या वो पेन ड्राइव उनसे ली गई? नोटिस मिलने के बाद कमलनाथ ने नया बयान दिया था उन्होंने सिर्फ 29 सेकंड की क्लिप देखी है। इसके अलावा मूल केस में अब आरोपों पर बहस होनी बाकी है। सरकारी पक्ष ने तर्क रखा कि अब तक की जांच में आरोपियों के खिलाफ जो सबूत मिले हैं, उस आधार पर उनके खिलाफ केस चलाया जाए। इसके बाद केस की सुनवाई शुरू होगी। इस मामले में 16 लोगों की गवाही हो चुकी है। एसआईटी ने जनवरी महीने में हुई पेशी में कहा था कि वे टेलीकॉम अधिकारी की गवाही कराना चाहते हैं, ताकि ये प्रमाणित हो सके कि फरियादी की किन लोगों से बात हुई। आरोपियों के वकील ने तर्क दिया कि सरकारी पक्ष ने टेलीकॉम अधिकारी की गवाही 3 साल में क्यों नहीं कराई? इस केस में दिलचस्प बात ये है कि पीड़िता ने पहले कोर्ट को दिए बयान में ये कबूल किया था कि उसे जबरन कुछ लोगों के पास भेजा गया। इसके बदले उसे पैसे मिले थे। लेकिन प्रति-परीक्षण में पीड़िता ने आरोपियों को पहचानने से इनकार कर दिया। फरवरी महीने में इस मामले की अगली सुनवाई होगी।

● राकेश ग्रोवर

मप्र के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की जीरो टॉलरेंस नीति और सुशासन की चर्चा मप्र ही नहीं देशभर में होने लगी है। जिस तरह वे ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं, उससे उनकी प्रशासनिक क्षमता भी दिखने लगी है। यही नहीं उनमें लीक से हटकर शासन करने की झलक भी दिख रही है। खासकर प्रशासनिक अफसरों की जमावट में उन्होंने परंपरा से हटकर काम किया है। यही नहीं पूर्ववर्ती शिवराज सिंह चौहान की सरकार में मुख्यमंत्री के सबसे करीबी और चहेते अफसरों से परहेज किया जा रहा है। यानी मुख्यमंत्री ने अभी तक मुख्य धारा में उन अफसरों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है, जो अभी तक हाशिए पर रहते थे। मुख्यमंत्री ने अब तक जो कदम उठाए हैं, उससे यही संदेश गया है कि उनकी नजर में जनता सर्वोपरि है। सुशासन की लाइन पर काम करने वाले अफसर ही मुख्यधारा में रहेंगे।

हालांकि करीब 43 दिनों तक हाशिए पर रहने के बाद नई सरकार में दर्जनभर अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई, लेकिन वह भी बड़ी नहीं। मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव पद से हटाए गए मनीष रस्तोगी के साथ ही डॉ. मोहन यादव सरकार में अलग-अलग पदों से हटाए गए 6 आईएएस अधिकारियों मनीष सिंह, तरुण राठी, सौरव कुमार सुमन, कुमार पुरुषोत्तम, नीरज कुमार वशिष्ठ और किशोर कुमार कन्याल को भी पोस्टिंग दे दी गई है। लेकिन इन्हें बड़े विभागों की जवाबदारी नहीं मिली। ये सभी पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस के करीबी अधिकारी रहे हैं। 16 साल तक शिवराज के बेहद करीबियों में शुमार रहे नीरज को विमुक्त घुमंतू एवं अर्ध घुमंतू जनजाति विभाग का संचालक बनाया गया है। हाल ही में जब उन्हें सीएमओ से हटाया गया था, तब वे उप सचिव, मुख्यमंत्री रहे। मनीष सिंह को भी आयुक्त जनसंपर्क से हटाया गया था, उन्हें अब रजिस्ट्रार मप्र राज्य उपभोक्ता प्रतितोषण विवाद आयोग भेज दिया गया है। महिला एवं बाल विकास विभाग में अगस्त 2021 में संचालक बने और यहीं आयुक्त का प्रमोशन लेने वाले रामराव भोंसले को भी हटा दिया गया। भोंसले करीब ढाई साल इस विभाग में रहे। वहीं किशोर कुमार कन्याल ने कलेक्टर शाजापुर पोस्टिंग के दौरान ड्राइवरों की हड़ताल में एक आंदोलनकारी से कह दिया था कि तुम्हारी औकात क्या है। वीडियो वायरल होने के बाद उन्हें कलेक्टर पद हटा दिया गया था। उन्हें फॉरेस्ट का डिप्टी सेक्रेटरी बनाया गया है।

गौरतलब है कि 13 दिसंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद डॉ. मोहन यादव ने 15 दिसंबर को अधिकारियों के तबादले की पहली सूची जारी की थी। सबसे पहला नाम मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव और लोक सेवा प्रबंधन विभाग के प्रमुख सचिव मनीष रस्तोगी का था। 1994 बैच के वरिष्ठ आईएएस मनीष रस्तोगी को हटाकर मंत्रालय में बिना विभाग का प्रमुख सचिव बनाया गया था। मनीष रस्तोगी शिवराज सिंह चौहान के सबसे खास अधिकारियों में शुमार थे। 19 दिसंबर को मनीष सिंह का तबादला किया गया था। जनसंपर्क आयुक्त, एमडी माध्यम और एमडी मेट्रो रेल कारपोरेशन भोपाल के पद से हटाए गए। शिवराज सरकार में मनीष सिंह का गजब जलवा था। पूरा जनसंपर्क उनकी मुट्ठी में था। मेट्रो रेल सहित कई विभागों में मनीष सिंह दखल रखते थे। कहते हैं कि मनीष सिंह के सिर पर शिवराज सिंह चौहान का हाथ था। 21 दिसंबर को हुए तबादले में नीरज वशिष्ठ को हटा दिया गया था। 2013 बैच के आईएएस नीरज वशिष्ठ शिवराज सिंह चौहान के आंख, नाक और कान माने जाते थे। उन्हें भी बिना विभाग का उपसचिव बनाया गया था।

प्रदेश भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि मुख्यमंत्री जानते हैं कि व्यापक शिकायत थी कि नौकरशाह शिवराज सिंह चौहान की सरकार चलाते थे। उन्होंने बताया कि कैलाश विजयवर्गीय जैसे कई नेताओं ने सार्वजनिक रूप से शिवराज से पार्टी कार्यकर्ताओं को शांत करने के लिए नौकरशाही को नियंत्रित करने के लिए कहा। बाद में शिवराज को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने नौकरशाहों को डांटना शुरू कर दिया। यादव को शिवराज की गलती पता है, जो पिछले 18 साल से सत्ता के शीर्ष पर थे, वह न केवल नौकरशाही की जवाबदेही तय करना चाहते हैं, बल्कि यह संदेश भी देना चाहते हैं कि नौकरशाहों से निपटने में लोगों की धारणा अधिक मायने रखती है।

● विकास दुबे

पूर्व सीएम-सीएस के करीबियों से परहेज

न रुतबा बचा, न नाम

पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्य सचिव के कार्यकाल के दौरान जिन अफसरों का दबदबा रहता था, अब सचिवालय वल्लभ भवन में न उनका कोई रुतबा बचा है, न नाम और न ही कोई बड़ा काम है। दिलचस्प बात यह है कि यह सभी अधिकारी पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सबसे खास अधिकारियों में शामिल थे। शिवराज सिंह चौहान ने इन्हें मप्र के प्रमुख विभागों के काम दे रखे थे। यह अधिकारी सीधे ही शिवराज सिंह चौहान को रिपोर्ट करते थे। अब मप्र के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव अपने तरह से नए अधिकारियों की जमावट कर रहे हैं। डॉ. मोहन यादव उन अधिकारियों को मौका देना चाहते हैं जो पिछले 17 वर्ष की शिवराज सरकार में हाशिए पर भेज दिए गए थे। दरअसल, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पूर्ववर्ती सरकार की तरह कुछ ही अफसरों के भरोसे चलने की परिपाटी को समाप्त करते हुए युवा और जोशीले अफसरों पर दांव लगाना शुरू किया है। यानी उन्हें बड़ी-बड़ी जिम्मेदारी सौंप रहे हैं। उधर, प्रदेश में बड़े तबादले की तैयारी चल रही है। आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की सूची बना ली गई है।8 फरवरी के बाद ताबड़तोड़ तबादले होंगे। माना जा रहा है कि चुनाव आयोग की गाइडलाइन के अनुसार दो दर्जन से अधिक जिलों के कलेक्टर और एसपी तो बदले ही जाएंगे, साथ ही जिलों में पदस्थ अधिकारियों को भी इधर से उधर किया जाएगा। इस जमावट में सरकार के भावी कदम की झलक देखने को मिल सकती है।

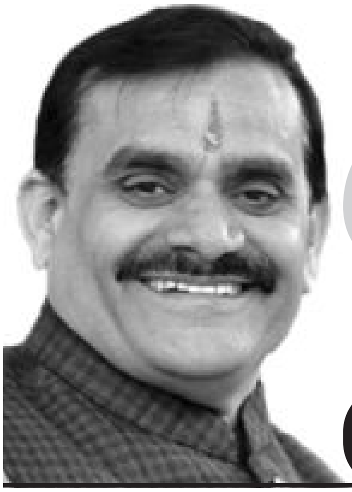

विधानसभा चुनाव के बाद अब मप्र में लोकसभा चुनाव का घमासान शुरू हो गया है। भाजपा सभी 29 सीटों को जीतने की रणनीति में जुट गई है, वहीं कांग्रेस भी 10 के पार जाने के लक्ष्य पर काम कर रही है। इसके लिए दोनों पार्टियों की रणनीति है कि अधिक से अधिक सीटों से नए चेहरों पर दांव लगाया जाए।

जिताऊ चेहरे की खोज

लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा और कांग्रेस ने प्रत्याशियों की खोज शुरू कर दी है। भाजपा की तरफ से जहां केंद्रीय नेतृत्व और संघ जिताऊ उम्मीदवार के लिए सर्वे करा रहा है, वहीं कांग्रेस की तरफ से ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के लोग सर्वे कर रहे हैं। भाजपा सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पार्टी तकरीबन एक दर्जन से अधिक सीटों पर नए चेहरे उतारेगी, वहीं कांग्रेस भी नए चेहरों के साथ ही दिग्गजों पर भी दांव लगाएगी। मप्र में करीब ढाई महीने बाद लोकसभा चुनाव होने हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा-कांग्रेस ने अपनी-अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। भाजपा के आला नेता 29 लोकसभा क्षेत्र में अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए गांव चलो अभियान चलाने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता बैठक कर प्रत्याशियों का नाम फाइनल करने की जुगत में लगे हैं। पार्टी सूत्रों के अनुसार, कांग्रेस और भाजपा दोनों पार्टियां फरवरी के मध्य या अंत में प्रत्याशियों के नाम सार्वजनिक करेंगी।

प्रदेश में यूथ वोटर्स को साधने के लिए भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियां यूथ को टारगेट कर प्रत्याशी उतारेंगी। यूथ के साथ ही ग्रामीण मतदाताओं को भी इस बार पार्टियों ने अपने टारगेट पर रखा है। ग्रामीण मतदाता और यूथ ही पार्टियों के लिए जीत के रास्ते खोलते हैं। इन दोनों को साधने के लिए कांग्रेस-भाजपा के नेता अपनी-अपनी रणनीति तैयार कर रहे हैं। भाजपा नेताओं के अनुसार, प्रदेश के मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए भाजपा द्वारा गांव चलो अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों को फोकस में रखकर पूरी योजना बनाई गई है। इस योजना के तहत बड़े नेता पंचायतों तक पहुंचेंगे और पार्टी की योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी देंगे। इसके साथ ही भाजपा के नेता रामलला की प्राण-प्रतिष्ठा कैंपेन का प्रचार-प्रसार भी करेंगे।

दिग्गजों पर दांव

लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस में मंथन का दौर शुरू हो गया है। 31 जनवरी तक लोकसभा प्रभारी से संभावित उम्मीदवारों की सूची मांगी गई है। दिल्ली के सूत्रों के अनुसार पार्टी हाईकमान ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को छिंदवाड़ा और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को राजगढ़ लोकसभा सीट से चुनाव लड़ाने का मन बनाया है। इसके अलावा सीडब्ल्यूसी के सदस्य और विधानसभा चुनाव में पराजित उम्मीदवार कमलेश्वर पटेल को सीधी लोकसभा सीट से लड़ने की चर्चा कांग्रेस की राजनीतिक गलियारों में सुर्खियों में है। दिल्ली में चर्चा है कि कांग्रेस कुछ विधायकों को भी लोकसभा चुनाव में उतार सकती है। कांग्रेस के क्षेत्रीय नेताओं और कार्यकर्ताओं की आम राय है कि कांग्रेस के दिग्गजों को लोकसभा चुनाव के मैदान में उतरना चाहिए। आठवीं विधानसभा चुनाव लगातार जीतने वाले डॉ. गोविंद सिंह पिछला विधानसभा चुनाव लहार से हार गए हैं और अब उन्हें मुरैना लोकसभा सीट से लड़ाने की तैयारी चल रही है। डॉ. गोविंद सिंह मुरैना संसदीय क्षेत्र में तेजी से सक्रिय भी हैं। भिंड लोकसभा सीट से विधायक फूल सिंह बरैया अथवा मेवाराम जाटव, ग्वालियर लोकसभा सीट से महापुरुष शोभा सिकरवार के उतारे जाने की चर्चा सुर्खियों में है। वैसे युवा ब्राह्मण नेता और विधानसभा चुनाव में पराजित प्रवीण पाठक के चुनाव लड़ने की चर्चा चल रही है। पाठक नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के खास सिपहसालार माने जाते हैं। इसी प्रकार गुना संसदीय क्षेत्र से केपी सिंह को चुनाव लड़ाया जा सकता है। सागर लोकसभा सीट क्षेत्र त्रिलोकीनाथ कटारे सबसे प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। ढाई लाख ब्राह्मण मतदाताओं का वर्चस्व वाली इस लोकसभा सीट में कटारे की पकड़ काफी मजबूत है।

विधानसभा में हारे हुए बूथ और सीटों पर प्रभारियों को तैनात किया जाएगा और वहां पहले प्रचार-प्रसार शुरू होगा। बड़े नेताओं को अंचल और मंत्रियों को जिले व सीट की जिम्मेदारी दी जाएगी। विधानसभा चुनाव की तर्ज पर भाजपा नए प्रत्याशियों को लोकसभा चुनाव में भी मौका दे सकती है। विधानसभा की तरह लोकसभा चुनाव में भी भाजपा के पक्ष में परिणाम आएं, इसके लिए केंद्र के नेताओं का प्रवास भी प्रदेश में लगातार रहेगा। मप्र में 29 लोकसभा सीट हैं। इनमें से 1 कांग्रेस और 28 भाजपा के पास हैं। लोकसभा की सभी 29 सीटें भाजपा के खाते में आएं, इसके लिए भाजपा ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के नेता मैराथन बैठकें कर रहे हैं। बैठकों में लोकसभावार रणनीति तैयारी पर चर्चा हो रही है। कांग्रेस जल्द से जल्द प्रत्याशी घोषित करना चाहती है। कांग्रेस के आला नेताओं की सहमति से जीतने वाले प्रत्याशियों का नाम फाइनल किया जाएगा। कांग्रेस के सूत्रों के अनुसार इस बार पार्टी युवा चेहरों को ज्यादा महत्व दे सकती है। कार्यकर्ताओं की तरफ से मांग उठी है कि पूर्व में जो नेता विधानसभा या लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, उन्हें इस बार मौका नहीं दिया जाए। आने वाले दिनों में कांग्रेस के बड़े नेता जिला प्रभारियों से बूथ लेवल एजेंट की सक्रियता को लेकर भी रिपोर्ट लेंगे।

कांग्रेस-भाजपा के सूत्रों के अनुसार, विधानसभा चुनाव की तर्ज पर लोकसभा चुनाव में भी प्रत्याशी के रूप में युवा और अनुभवी प्रत्याशियों का कॉम्बिनेशन मिलेगा। भाजपा नेताओं ने क्लस्टर प्रभारियों को प्रत्याशियों का नाम फाइनल करने और कोर बैठक में अपने सुझाव देने के लिए कहा है। इसी तरह से कांग्रेस में भी कार्यकर्ताओं ने युवा प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतारने की मांग की है। साथ ही विधानसभा चुनाव लड़ चुके नेताओं को टिकट ना देने की अपील की है। लोकसभा चुनाव में पार्टियां सब नेताओं को साथ रखने के लिए

युवा-अनुभवी नेताओं का कॉम्बिनेशन तैयार करने की तैयारी कर रही है। जानकारों का कहना है कि जिन सीटों पर मौजूदा उम्मीदवार बदले जा सकते हैं, वहां पार्टी ऐसे नए चेहरे, खास तौर से उन युवाओं को चुनाव मैदान में उतार सकती है, जो संघ की विचारधारा से जुड़े हैं। दरअसल, पार्टी युवा और नए चेहरे मैदान में उतारकर विधानसभा चुनाव की तरह पीढ़ी परिवर्तन का संदेश देना चाहती है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने मप्र की 29 सीटों में से 28 सीटें हासिल की थीं। छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर उसे हार मिली थी। छिंदवाड़ा ऐसी सीट है जहां भाजपा को लंबे समय से जीत नसीब नहीं हुई है। 1997 में छिंदवाड़ा सीट पर हुए उपचुनाव में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा ने जीत दर्ज करवाई थी। इसके अगले ही साल 1998 में हुए लोकसभा चुनाव में एक बार फिर कमलनाथ ने ये सीट छीन ली। इस बार इस सीट को जीतने के लिए पार्टी काफी पहले से तैयारियां शुरू करने के मूड में है।

पार्टी के एक वरिष्ठ पदाधिकारी के मुताबिक 2024 का चुनाव भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ेगी। इसके अलावा पार्टी कई प्रयोग भी करने जा रही है। पार्टी चुनावी मैदान में बड़े नेताओं को उतार सकती है। इस फेहरिस्त में कई राज्यों के पूर्व मुख्यमंत्री व मंत्री और राज्यसभा के लिए चुने गए सांसद भी शामिल हैं। मप्र से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, पूर्व मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा, गोपाल भार्गव और भूपेंद्र सिंह को लोकसभा चुनाव का टिकट दिया जा सकता है। शिवराज सिंह चौहान को विदिशा या भोपाल लोकसभा सीट से टिकट दिया जा सकता है। ऐसा ही प्रयोग भाजपा महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक में भी करने की तैयारी में है। 2024 के लोकसभा चुनाव में ऐसे मंत्रियों को भी टिकट दिया जा सकता है, जो फिलहाल राज्यसभा में हैं। इसके संकेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसदीय दल की बैठक में दे दिए थे। ऐसे में मप्र से राज्यसभा पहुंचे मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को उनके गृह राज्य ओडिशा से चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। जबकि ज्योतिरादित्य सिंधिया को ग्वालियर या गुना-शिवपुरी सीट से उम्मीदवार बनाया जा सकता है।

मिशन 2023 को फतह करने के बाद भाजपा मिशन 2024 में जुट गई है। पार्टी विधानसभा चुनाव की ही तरह लोकसभा चुनाव लड़ेगी। इसके तहत पार्टी आचार संहिता लगने से पहले ही टिकटों की घोषणा करने की तैयारी कर रही है। सूत्रों का कहना है कि पार्टी के सर्वे में अब तक करीब दर्जनभर सांसदों का टिकट खतरे में है। ऐसे में पार्टी उनकी जगह नए चेहरों को मैदान में उतार सकती है। भाजपा सूत्रों का कहना है कि विधानसभा चुनाव की तरह ही आलाकमान लोकसभा चुनाव में चौंका सकता है। फरवरी में होने वाली केंद्रीय चुनाव समिति में कई ऐसे निर्णय लिए जाएंगे, जो चौंकाने वाले होंगे। भाजपा के एक वरिष्ठ नेता का कहना है कि जो नेता तीन या उससे ज्यादा बार सांसद रह चुके हैं, उन्हें इस बार लोकसभा चुनाव में टिकट नहीं दिया जाएगा। इसके साथ ही उन सांसदों का टिकट भी काटा जा सकता है, जिनका परफॉर्मेंस कमजोर है। सूत्रों का दावा है कि उम्मीदवार के चयन के लिए जो क्राइटेरिया बनाया है, उसके मुताबिक पार्टी नेतृत्व मौजूदा 11 सांसदों का टिकट काट सकता है। इनमें से पांच सांसद, विधायक बन चुके हैं। ऐसे में भाजपा 16 नए चेहरे मैदान में उतार सकती है।

सूत्रों का कहना है कि भाजपा की लोकसभा चुनाव को लेकर हुई बैठक में वे सीटें सबसे ज्यादा चर्चा के केंद्र में रहीं, जहां भाजपा का विधानसभा चुनाव में कमजोर प्रदर्शन रहा है। पार्टी ने तीन केंद्रीय मंत्रियों समेत सात सांसदों को विधानसभा चुनाव में टिकट दिया था। इनमें से 5 सीटों पर जीत मिली जबकि सतना सांसद गणेश सिंह और मंडला सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते चुनाव हार गए। 29 में से 10 लोकसभा सीटें ऐसी हैं, जहां विधानसभा चुनाव में भाजपा को कांग्रेस से कम वोट मिले। इसमें से 5 सीटों को डेंजर जोन में रखा गया है। जबकि अन्य 5 सीटें मौजूदा सांसदों के लिए खतरे की घंटी हैं। विधानसभा चुनाव में पार्टी का परफॉर्मेंस देखें तो आज की स्थिति में उसे चार लोकसभा सीटों का नुकसान हो रहा है। इनमें तीन पर भाजपा के मौजूदा सांसद हैं। एक कांग्रेस के पास है और एक पर भाजपा के नरेंद्र सिंह तोमर इस्तीफा दे चुके हैं। इसके अलावा पांच और सीटों पर भाजपा की बढ़त लोकसभा की तुलना में कम हुई हैं। ये सीटें ग्वालियर-चंबल, महाकौशल और मालवा अंचल की हैं। भाजपा की रणनीति के अनुसार जिन लोकसभा सीटों पर अधिक फोकस करना है उनमें छिंदवाड़ा, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, मंडला, टीकमगढ़, बालाघाट, धार, खरगौन और रतलाम शामिल हैं। दरअसल, विधानसभा चुनाव के दौरान इन संसदीय क्षेत्रों में भाजपा का प्रदर्शन चिंताजनक रहा है। सूत्रों का कहना है कि मप्र विधानसभा चुनाव की तरह लोकसभा चुनाव में भी भाजपा पुराने चेहरों को उतारने से परहेज करेगी।

● **कुमार राजेन्द्र**

कांग्रेस करा रही सभी सीटों पर सर्वे

विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस लोकसभा चुनाव में स्थिति बेहतर करना चाहती है। हालांकि पिछले कुछ चुनावों से कांग्रेस लोकसभा चुनाव में भी बड़ी जीत की जद्दोजहद में जुटी है। 2019 में कांग्रेस प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में से एक ही सीट जीत पाई थी। ऐसे में इस बार कांग्रेस अपना प्रदर्शन बेहतर करना चाहती है। इसके लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) सभी सीटों पर जिताऊ चेहरों की तलाश के लिए सर्वे करवा रही है। एआईसीसी ने कुछ सर्वे एजेंसियों को भी इस काम में लगाया है। सूत्रों की मानें तो प्रदेश की किस लोकसभा सीट पर कौन सा नेता जीत सकता है। इसे लेकर स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ निकायों, पंचायतों के जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों, सिविल सोसायटी और लघु उद्यमियों और रिटायर्ड नौकरशाहों से एजेंसियां फोन व अन्य साधनों के जरिए संपर्क कर उनकी राय ले रही हैं। सर्वे रिपोर्ट कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंपी जाएगी। जानकारी के अनुसार यह सर्वे दो चरणों में होगा। पहले चरण का सर्वे शुरू हो चुका है। दूसरे चरण का सर्वे फरवरी के आखिरी सप्ताह से शुरू होगा। ये सर्वे राहुल गांधी के करीबी माने जाने वाले एक सेवानिवृत नौकरशाह और रणनीतिकार की देखरेख में हो रहे हैं।

विभागों को मिले 8,623 करोड़

7 फरवरी से शुरू होगा मप्र विधानसभा का बजट सत्र

मप्र की मोहन सरकार का बजट इस बार मार्च माह में नहीं आएगा, लोकसभा चुनाव को देखते हुए बजट के लिए चार माह इंतजार करना होगा। हालांकि सरकार बजट सत्र में लेखानुदान ला रही है। इस लेखानुदान में मिले बजट से विभाग चार माह तक काम चलाएंगे। लेकिन इससे पहले जनवरी, फरवरी और मार्च में विभागों के खर्च के लिए सरकार ने 8,623 करोड़ रुपए की राशि तय किया है। लेकिन विडंबना यह है कि इन तीन महीनों के दौरान नगरीय विकास, पर्यटन और ओबीसी के लिए कोई फंड जारी नहीं किया गया है। यानी इन तीन महीनों के दौरान इन तीनों विभागों में कोई नया काम नहीं होगा।

दरअसल, आर्थिक तंगी के इस दौर में सरकार फूंक-फूंककर कदम बढ़ा रही है। इसलिए सरकार ने विभागों की खर्च की सीमा तय कर दी है। वित्त विभाग द्वारा जारी बजट के मुताबिक कई विभागों को सिर्फ पीआईयू (प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट) के पेमेंट के लिए ही राशि जारी की गई है। इनमें स्कूल शिक्षा, जनजातीय कार्य विभाग, चिकित्सा शिक्षा, हेल्थ, तकनीकी शिक्षा-कौशल विकास और रोजगार विभाग, उच्च शिक्षा, राजस्व और अनुसूचित जाति कल्याण विभाग शामिल हैं। पीआईयू द्वारा इन विभागों के अधोसंरचना के काम किए जा रहे हैं। इसमें अस्पताल, लैब, प्रशिक्षण स्थल, छात्रावास, स्कूल आदि भवनों का निर्माण शामिल है। गौरतलब है कि पहले से ही वित्तीय संकट के चलते 38 विभागों को वित्त विभाग की परमिशन के बगैर भुगतान करने पर रोक लगा चुकी सरकार द्वारा अब 26 विभागों की लिमिट तय करने को वित्तीय मैनेजमेंट से जोड़ा जा रहा है। इसमें सबसे अधिक 2055 करोड़ रुपए लोक निर्माण विभाग और 1255 करोड़ रुपए जल संसाधन विभाग के लिए तय किए गए हैं। सबसे खराब स्थिति तो नगरीय निकायों के मामले में है। नगरीय विकास के लिए तीन माह में व्यय सीमा जीरो रखी गई है। इसके चलते शहरी इलाकों में सड़कों व अन्य अधोसंरचना के काम पर असर पड़ना तय है। इसी तरह पर्यटन और पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के लिए भी तीन माह में पूंजीगत मद में व्यय सीमा जीरो रखी गई है। पूंजीगत व्यय वह राशि है जिसका उपयोग व्यवसाय लंबी अवधि की संपत्ति खरीदने, बनाए रखने या बढ़ाने के लिए करते हैं। वित्त विभाग ने विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिवों को खर्च की सीमा में ही भुगतान करने को कहा है। वित्त विभाग ने निर्माण कार्य से जुड़े 8 विभागों के लिए तो यह लिमिट तय की गई है कि वे सिर्फ पीआईयू के द्वारा बनाए जाने वाले भवनों का भुगतान ही कर सकेंगे।

पीएचई को 991 करोड़, लोनिवि को 2055 करोड़, जल संसाधन को 1255 करोड़, ऊर्जा विभाग को 235 करोड़, नर्मदा घाटी को 807 करोड़, स्कूल शिक्षा विभाग को 300 करोड़, नगरीय विकास को जीरो, पंचायत एवं ग्रामीण विकास को 1591 करोड़, जनजातीय कार्य 80 करोड़, वन विभाग 439 करोड़, चिकित्सा शिक्षा विभाग 109 करोड़, स्वास्थ्य विभाग 309 करोड़, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग 276 करोड़, तकनीकी शिक्षा 157 करोड़, उच्च शिक्षा 206 करोड़, गृह विभाग 203 करोड़, खेल एवं युवक कल्याण विभाग 162 करोड, संस्कृति विभाग 112 करोड़, राजस्व विभाग 86 करोड़, अजा कल्याण विभाग 77 करोड़, महिला एवं बाल विकास 50 करोड़, विज्ञान एवं तकनीकी 49 करोड़, सूक्ष्य एवं लघु उद्योग विभाग 43 करोड़ रुपए, खाद्य विभाग 31 करोड़ खर्च कर पाएंगे। जबकि पर्यटन, पिछड़ा वर्ग कल्याण, को एक पैसा भी नहीं मिला है। इन विभागों को मार्च तक 8623 करोड़ रुपए लिमिट में खर्च करने होंगे।

लोकसभा चुनाव के बाद मप्र का बजट जुलाई माह में लाया जाएगा, हालांकि प्रदेश की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए मोहन सरकार फरवरी माह में लेखानुदान लेकर आएगी। इसमें शुरुआत चार माह के लिए विभागों को जरूरी खर्च के लिए राशि उपलब्ध कराई जाएगी, इसके लिए वित्त विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। चार माह का खर्च चलाने के लिए वित्त विभाग ने सभी विभागों को निर्देश दिया है कि 2023-24 के लिए पुनरीक्षित अनुमान और 2024-25 के बजट अनुमान के आंकड़ों को ऑनलाइन भेजा जाए। साथ ही विभाग द्वारा अप्रैल 2024 से जुलाई 2024 तक के लेखानुदान के लिए आय और खर्च का ब्यौरा भी भेजा जाए। वित्त विभाग ने साफ कहा है कि विभागों को पुराने खर्चों के लिए ही राशि उपलब्ध कराई जाएगी, किसी नए खर्च के लिए राशि नहीं दी जाएगी। लेखानुदान में कोई नया मद शामिल नहीं किया जाएगा, इसलिए विभाग की ओर से किसी योजना या योजनाओं को खत्म करने या संविलयन करने की जरूरत हो तो इसके लिए विभाग वित्त विभाग के अधिकारियों से चर्चा कर सकेंगे।

● प्रवीण सक्सेना

मप्र विधानसभा का बजट सत्र 7 फरवरी से प्रारंभ होगा। इसमें सरकार अप्रैल से जुलाई 2024 तक के लिए लेखानुदान प्रस्तुत करेगी। वर्ष 2024-25 का बजट मानसून सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा। इसके साथ ही वर्ष 2023-24 के लिए द्वितीय अनुपूरक बजट भी प्रस्तुत किया जाएगा। 13 दिन के इस सत्र में कुल 9 बैठकें होंगी। इस संबंध में विधानसभा सचिवालय ने अधिसूचना जारी कर दी है। विधानसभा के प्रमुख सचिव ने का कहना है कि बजट सत्र में कुल नौ बैठकें होंगी। राज्यपाल का अभिभाषण पहले दिन यानी 7 फरवरी को होगा और इस पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन पर दो दिन चर्चा होगी। मोहन सरकार का यह पहला बजट सत्र होगा। वित्त विभाग के अधिकारियों का कहना है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 की शेष अवधि के लिए द्वितीय अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया जाएगा। इसमें लाड़ली बहना सहित अन्य योजनाओं के लिए विभागों को आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराई जाएगी। लोकसभा चुनाव को देखते हुए इस बार बजट अभी प्रस्तुत नहीं होगा। इसके स्थान पर लेखानुदान प्रस्तुत किया जाएगा। यह एक लाख करोड़ रुपए का हो सकता है। इसके लिए विभागीय प्रस्तावों को इसी माह अंतिम रूप दे दिया जाएगा। सत्र में कुछ संशोधन विधेयक भी प्रस्तुत किए जा सकते हैं। इसके लिए विभागों को तैयारी करने के निर्देश दिए गए हैं।

मिशन 2023 को फतह करने के बाद भाजपा मिशन 2024 में जुट गई है। पार्टी विधानसभा चुनाव की ही तरह लोकसभा चुनाव लड़ेगी। इसके तहत पार्टी आचार संहिता लगने से पहले ही टिकटों की घोषणा करने की तैयारी कर रही है। सूत्रों का कहना है कि पार्टी के सर्वे में अब तक करीब दर्जनभर सांसदों का टिकट खतरे में है। ऐसे में पार्टी उनकी जगह नए चेहरों को मैदान में उतार सकती है। भाजपा सूत्रों का कहना है कि विधानसभा चुनाव की तरह आलाकमान लोकसभा चुनाव में भी चौंका सकता है। फरवरी में होने वाली केंद्रीय चुनाव समिति में कई ऐसे निर्णय लिए जाएंगे, जो चौंकाने वाले होंगे। भाजपा के एक वरिष्ठ नेता का कहना है कि जो नेता तीन या उससे ज्यादा बार सांसद रह चुके हैं, उन्हें इस बार लोकसभा चुनाव में टिकट नहीं दिया जाएगा। इसके साथ ही उन सांसदों का टिकट भी काटा जा सकता है, जिनका परफॉर्मेंस कमजोर है। सूत्रों का दावा है कि उम्मीदवार के चयन के लिए जो क्राइटेरिया बनाया है, उसके मुताबिक पार्टी नेतृत्व मौजूदा 11 सांसदों का टिकट काट सकता है। इनमें से पांच सांसद, विधायक बन चुके हैं। ऐसे में भाजपा 16 नए चेहरे मैदान में उतार सकती है।

सूत्रों का कहना है कि भाजपा की लोकसभा चुनाव को लेकर हुई बैठक में वे सीटें सबसे ज्यादा चर्चा के केंद्र में रहीं, जहां भाजपा का विधानसभा चुनाव में कमजोर प्रदर्शन रहा है। पार्टी ने तीन केंद्रीय मंत्रियों समेत सात सांसदों को विधानसभा चुनाव में टिकट दिया था। इनमें से 5 सीटों पर जीत मिली जबकि सतना सांसद गणेश सिंह और मंडला सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते चुनाव हार गए। 29 में से 10 लोकसभा सीटें ऐसी हैं, जहां विधानसभा चुनाव में भाजपा को कांग्रेस से कम वोट मिले। इसमें से 5 सीटों को डेंजर जोन में रखा गया है। जबकि अन्य 5 सीटें मौजूदा सांसदों के लिए खतरे की घंटी हैं। विधानसभा चुनाव में पार्टी का परफॉर्मेंस देखें तो आज की स्थिति में उसे चार लोकसभा सीटों का नुकसान हो रहा है। इनमें तीन पर भाजपा के मौजूदा सांसद हैं। एक कांग्रेस के पास है और एक पर भाजपा के नरेंद्र सिंह तोमर इस्तीफा दे चुके हैं। इसके अलावा पांच और सीटों पर भाजपा की बढ़त लोकसभा की तुलना में कम हुई हैं। ये सीटें ग्वालियर-चंबल, महाकौशल और मालवा अंचल की हैं।

भाजपा की रणनीति के अनुसार जिन लोकसभा सीटों पर अधिक फोकस करना है, उनमें छिंदवाड़ा, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, मंडला, टीकमगढ़, बालाघाट, धार, खरगौन और रतलाम शामिल हैं। दरअसल, विधानसभा चुनाव के दौरान इन संसदीय क्षेत्रों में भाजपा का प्रदर्शन चिंताजनक रहा है। सूत्रों का कहना है कि मप्र विधानसभा चुनाव की तरह लोकसभा चुनाव में भी भाजपा पुराने चेहरों को उतारने से परहेज करेगी। पार्टी की रणनीति के अनुसार जो नेता तीन या उससे अधिक बार सांसद रह चुके हैं, उन्हें आगामी लोकसभा चुनाव में टिकट नहीं दिया जाएगा। इसके साथ ही उन सांसदों के टिकट पर भी तलवार लटकी है, जिनका प्रदर्शन कमजोर है। विधानसभा चुनाव में पार्टी ने जिन हारी हुई सीटों पर चुनाव से काफी पहले प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया था, वहां पार्टी की कामयाबी का प्रतिशत 61 प्रतिशत रहा है। मप्र में विधानसभा चुनाव की घोषणा 8 अक्टूबर को हुई थी। जबकि पार्टी ने 39 सीटों पर उम्मीदवार की पहली सूची 17 अगस्त को जारी कर दी थी। ये वो सीटें थीं, जहां भाजपा को पिछले विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन इस बार 39 में से 24 सीटें भाजपा ने जीत लीं। सूत्रों का कहना है कि विधानसभा के इस सक्सेस रेट को पार्टी लोकसभा में दोहराना चाहती है। उम्मीदवार का नाम चुनाव से पहले घोषित करने से न केवल पार्टी को फायदा मिला, बल्कि कमजोर सीटों पर उम्मीदवार को अपना फोकस बढ़ाने का भी मौका मिला।

दर्जनभर सांसदों का टिकट खतरे में

विधायकों सहित हारे नेताओं पर भी दांव

पार्टी के एक वरिष्ठ पदाधिकारी के मुताबिक 2024 का चुनाव भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ेगी। इसके अलावा पार्टी कई प्रयोग भी करने जा रही है। पार्टी चुनावी मैदान में बड़े नेताओं को उतार सकती है। इस फेहरिस्त में कई राज्यों के पूर्व मुख्यमंत्री व मंत्री और राज्यसभा के लिए चुने गए सांसद भी शामिल हैं। मप्र से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, पूर्व मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा, गोपाल भार्गव और भूपेंद्र सिंह को लोकसभा चुनाव का टिकट दिया जा सकता है। शिवराज सिंह चौहान को विदिशा या भोपाल लोकसभा सीट से टिकट दिया जा सकता है। ऐसा ही प्रयोग भाजपा महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक में भी करने की तैयारी में है। 2024 के लोकसभा चुनाव में ऐसे मंत्रियों को भी टिकट दिया जा सकता है, जो फिलहाल राज्यसभा में हैं। इसके संकेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसदीय दल की बैठक में दे दिए थे। ऐसे में मप्र से राज्यसभा पहुंचे धर्मेंद्र प्रधान को उनके गृह राज्य ओडिशा से चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। जबकि ज्योतिरादित्य सिंधिया को ग्वालियर या गुना-शिवपुरी सीट से उम्मीदवार बनाया जा सकता है।

जानकारों का कहना है कि जिन सीटों पर मौजूदा उम्मीदवार बदले जा सकते हैं, वहां पार्टी ऐसे नए चेहरे, खासतौर से उन युवाओं को चुनाव मैदान में उतार सकती है, जो संघ की विचारधारा से जुड़े हैं। दरअसल, पार्टी युवा और नए चेहरे मैदान में उतारकर विधानसभा चुनाव की तरह पीढ़ी परिवर्तन का संदेश देना चाहती है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने मप्र की 29 सीटों में से 28 सीटें हासिल की थीं। छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर उसे हार मिली थी। छिंदवाड़ा ऐसी सीट है जहां भाजपा को लंबे समय से जीत नसीब नहीं हुई है। 1997 में छिंदवाड़ा सीट पर हुए उपचुनाव में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा ने जीत दर्ज करवाई थी। इसके अगले ही साल 1998 में हुए लोकसभा चुनाव में एक बार फिर कमलनाथ ने ये सीट छीन ली। इस बार इस सीट को जीतने के लिए पार्टी काफी पहले से तैयारियां शुरू करने के मूड में है।

● अरविंद नारद

मनपसंद स्टाफ नहीं रख सकेंगे माननीय

अभी तक सत्ता, संगठन और संघ के दिशा निर्देशों को दरकिनार कर मनपसंद अधिकारियों-कर्मचारियों को अपने स्टाफ में रखने के आदी मंत्रियों को बड़ा झटका लगा है। सुशासन को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेश के 15 मंत्रियों की सिफारिश नोटशीट लौटा दी है। अपने-अपने चहेतों के लिए मंत्रियों ने सिफारिश नोटशीट भेजी थी। दरअसल, प्रदेश के मंत्री मूल विभाग की वजह सालों से जमे निजी सहायक, निजी सचिव, विशेष सहायक के पद पर चहेतों को लाना चाहते थे। मुख्यमंत्री ने मंत्री दिलीप जायसवाल, संपतिया उइके, राकेश सिंह, एंदल सिंह कंसाना, नारायण सिंह कुशवाहा, राकेश शुक्ला, नरेंद्र शिवाजी पटेल, लखन पटेल, इंदर सिंह परमार, चैतन्य काश्यप, प्रतिमा बागरी, प्रहलाद पटेल, कृष्णा गौर और विश्वास सारंग की फाइल लौटा दी है।

दरअसल, मोहन सरकार के मंत्रियों को पिछली सरकारों में मंत्री स्टाफ में रहे अधिकारियों-कर्मचारियों का मोह छोड़ना होगा। गत दिनों कैबिनेट बैठक के बाद सिर्फ पांच मंत्रियों के स्टाफ में नियुक्ति के आदेश निकले हैं। खास बात यह है कि इनमें से कोई भी कर्मचारी पहले कभी किसी मंत्री के स्टाफ में नहीं रहा है। जानकारों का कहना है कि मुख्यमंत्री चाहते हैं कि पिछली सरकारों में मंत्रियों के स्टाफ में रहे कर्मचारियों को इस बार मंत्री अपने स्टाफ में नहीं रखें। ज्यादातर मंत्रियों के साथ निज सचिव से लेकर विशेष सहायक तक वे अधिकारी-कर्मचारी काम कर रहे हैं, जिनके नियुक्ति आदेश नहीं हुए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की कार्यप्रणाली से यह स्पष्ट हो गया है कि अब मुख्यमंत्री कार्यालय में नए अधिकारी एवं कर्मचारियों की पदस्थापना होगी। मौजूदा स्थिति में सालों से जमे जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, उन्हें सीएमओ से बाहर किया जा सकता है, या फिर जो कर्मचारी लंबे समय से एक ही दायित्व संभाल रहे थे, उन्हें भी दूसरी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। अधिकारियों की भी सीएमओ में नए सिरे से पदस्थापना होगी। निजी स्टाफ में सरकारी कर्मियों की नियुक्ति के लिए मंत्रियों का सिफारिश भेजने का सिलसिला जारी है। हाल में दो मंत्रियों ने दो सरकारी कम्पाउंडरों, गिरीश चतुर्वेदी और लक्ष्मीकांत दुबे की नियुक्ति अपने निजी स्टाफ में करने के लिए सिफारिश भेजी है। चतुर्वेदी की सिफारिश पर्यटन राज्यमंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी जबकि दुबे के लिए सिफारिश उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार की तरफ से आई है। अभी तक उप मुख्यमंत्रियों के पास ही दो पुराने निज सचिव हैं। राजेंद्र शुक्ला के यहां आनंद भट्ट और जगदीश देवड़ा के यहां अशोक डहारे। इनके आदेश पूर्व में ही हो गए।

मंत्रियों के यहां पदस्थ स्टाफ को लेकर लगातार मिल रही शिकायतों के बाद डॉ. मोहन यादव सरकार ने पहली बार सख्त एक्शन लिया है। अब किसी भी मंत्री के यहां उनका पुराना स्टाफ पदस्थ नहीं हो पाएगा। इस संबंध में मंत्रियों द्वारा भेजी गई नस्ती को सीएम हाऊस ने निरस्त कर उनसे नए नाम भेजने को कहा था। मंत्रियों से कहा गया कि वे अब ऐसे लोगों के नाम भेजें जो कभी मंत्रियों के यहां पदस्थ न रहे हों। इसके साथ ही जीएडी को आदेश दिए हैं कि वह ऐसे लोगों की मंत्री स्टाफ में पदस्थापना करें जो पहले कभी मंत्रियों के वहां नहीं रहे हों। ऐसा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की मंशा पर किया गया है। इस फैसले से मंत्रियों में हड़कंप की स्थिति है। गौरतलब है कि मंत्रियों के यहां पदस्थ स्टाफ को लेकर लंबे समय से संगठन और संघ को शिकायतें मिल रही थीं। संगठन ने कई बार मंत्रियों से आग्रह किया था कि वे अपने वहां उस स्टाफ को न रखें जिनके खिलाफ पार्टी कार्यकर्ताओं या पदाधिकारियों की शिकायतें है, पर इस पर कभी मंत्रियों ने ध्यान नहीं दिया। डॉ. मोहन यादव सरकार में गोविंद सिंह राजपूत, प्रद्युम्न सिंह तोमर, तुलसीराम सिलावट, इंदर सिंह परमार, विश्वास सारंग और विजय शाह पिछली सरकार में भी मंत्री थे। इन मंत्रियों ने अपने पुराने स्टाफ को ही फिर से पदस्थ करने के लिए जीएडी को नोटशीट भेजी थी पर इन मंत्रियों के यहां से भी पुराना स्टाफ रवाना करने की तैयारी है। यहां भी नए लोगों को पदस्थ किया जाएगा। इस मामले में फिलवक्त उपमुख्यमंत्रियों को छोड़ दिया गया है। उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला के यहां अभी भी कुछ ऐसे अधिकारी-कर्मचारी काम कर रहे है जो पूर्व में भी उनके यहां पदस्थ थे। सूत्रों ने बताया कि जल्द ही इन्हें भी बदला जाएगा। दिलचस्प यह है कि सरकार बदली, मंत्री बदलते रहे पर मंत्रियों के यहा पदस्थ स्टाफ नहीं बदला। कुछ अधिकारी और कर्मचारी तो ऐसे हैं जिनकी पूरी नौकरी मंत्रियों के स्टाफ में ही काम करते निकल गई।

● **लोकेंद्र शर्मा**

15 मंत्रियों की सिफारिशी नोटशीट लौटाई

मूल विभाग के बजाय सालों से मंत्रियों के स्टाफ में जमे निज सहायक (पीए), निजी सचिव (पीएस) और विशेष सहायकों (एसए) को इस बार बड़ा झटका लगा है। जिन 15 मंत्रियों ने चहेतों की पदस्थापना के लिए सिफारिशी नोटशीट मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को भेजी थी, सभी को सामान्य प्रशासन विभाग ने लौटा दिया। संकेत भी दे दिए गए कि बहुत जरूरी हुआ, तभी संबंधित व्यक्ति का पूरा फीडबैक लेने के बाद मंत्री स्टाफ में पदस्थापना होगी। मंत्रियों ने जिनकी नोटशीट भेजी, वे अभी बिना पोस्टिंग आदेश के ही काम कर रहे हैं। मंत्रियों की सारी सिफारिशी नोटशीट बिना असर दिखाए ही सीएमओ से जीएडी में आ गईं। अब तक सिर्फ पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह और जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह के लिए ही विशेष सहायकों की नियुक्ति के आदेश जारी हो सके हैं। ये भी नए हैं। राहुल सिंह, कमिश्नर छिंदवाड़ा नगर निगम को पीडब्ल्यूडी मंत्री और लक्ष्मीकांत खरे को जनजातीय कार्य मंत्री के विशेष सहायक के आदेश ही जारी हो सके हैं। इसके अलावा सात मंत्रियों के नए स्टॉफ के आदेश हुए हैं। इस बीच, अब सवाल है कि जो करीब एक महीने से मंत्रियों के यहां बिना आदेश के ही काम कर रहे हैं, उनका वेतन कहां से आएगा। गौरतलब है कि जीएडी से विशेष सहायक, मंत्रालयीन सेवा से निजी सहायकों की नियुक्ति होती है।

फिर सवालों में ईवीएम

पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर ईवीएम, वीवीपैट और चुनाव आयोग पर सवाल उठाए हैं। दिग्विजय सिंह का कहना है कि मेरा आरोप है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है, दबाव में है। आयोग से हम निष्पक्षता की उम्मीद करते हैं। ईवीएम का सारा काम प्राइवेट लोगों के हाथ में है। जब सॉफ्टवेयर ही सब करता है तो वही तय करेगा सरकार किसकी बनेगी। दिग्विजय ने ईवीएम में गड़बड़ी का डेमो भी दिया।

दिग्विजय सिंह ने आईआईटी दिल्ली के अतुल पटेल से पूरी मतदान प्रक्रिया का डैमो दिलाया। इस दौरान एक ईवीएम में 10 वोट डाले गए। उन्होंने बताया कि 2017 में वीवीपैट का ग्लास बदल दिया गया था। वोट डालने के बाद 7 सेकंड के लिए वीवीपैट में लाइट जलती है। वोटर पर्ची देखकर चला जाता है। आईआईटीयन अतुल पटेल ने मशीन की गड़बड़ी को दिखाने के लिए एक चिन्ह तरबूज को दो वोट डाले। पहला तरबूज की पर्ची वीवीपैट में दिखी। दूसरा वोट तरबूज का बटन दबाने के बावजूद सेब की पर्ची प्रिंट हुई। अतुल ने कहा, 2013 से चुनावी प्रक्रिया पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। हम बैलेट पेपर से वोटिंग की लड़ाई लड़ रहे हैं। दिग्विजय ने कहा, चुनाव आयोग से इंडी एलायंस की 24 पार्टियों ने समय मांगा, लेकिन हमें समय नहीं दे रहे। आयोग भाजपा के दबाव में है। मतदान मेरा अधिकार है। मेरा वोट वहीं जाए जहां मैं चाहता हूं। जो छपेगा वो काउंट होगा। जब 10 वोट डाले तो ज्यादा कैसे हो गए। ये केवल हम इसलिए आपके सामने लाए हैं कि जो दिखता है वो छपता है। वीवीपैट की पर्ची हमें मिले और उस पर्ची को बैलेट बॉक्स में डालें। इसमें क्या दिक्कत है। दिग्विजय ने बेल्जियम के वोटिंग सिस्टम की जानकारी देते हुए कहा, वीवीपैट की पर्ची मतदाता के हाथ में दी जाती है। ये डिजाइन हैकिंग के लिए आसान है। हमारे पास कई लोग आते हैं कि इतना पैसा दे दो हम आपके लिए काम कर देंगे। ये सब बोगस है। ईवीएम बाहर से हैक नहीं की जा सकती। इसमें सिर्फ सॉफ्टवेयर की प्रोग्रामिंग से प्रक्रिया बदली जा सकती है।

भोपाल में श्यामला हिल्स स्थित अपने निवास पर दिग्विजय ने कहा, 140 करोड़ आबादी वाले देश में जहां 90 करोड़ मतदाता हैं तो क्या हम ऐसे लोगों के हाथ में ये सब तय करने का अधिकार दे दें। पूरी इलेक्शन प्रोसेस का मालिक न मतदाता है, न अधिकारी-कर्मचारी हैं। इसका मालिक सॉफ्टवेयर बनाने और डालने वाला है। उन्होंने कहा, सवालों के जवाब चुनाव आयोग नहीं दे रहा है। हमसे कहते हैं कि 7 सेकंड के लिए वीवीपैट दिख जाता है, लेकिन वो जो दिखता है वही छपता है इसकी क्या गारंटी है?

आडवाणी ने भी सवाल उठाए थे...

2003 से लेकर 2012 तक ईवीएम चलती रही। इस दौरान लालकृष्ण आडवाणी से लेकर कई नेताओं ने इसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाए। मूल रूप से जनता को विश्वास होना चाहिए। इसके बाद वीवीपैट मशीन आई। उसमें दिखाने की प्रक्रिया थी कि मतदाता वोट कहां डाल रहा है। 2017 में वीवीपैट का ग्लास बदल दिया गया था। वीवीपैट में डाले जाने वाले सॉफ्टवेयर का सर्वर सेंट्रल इलेक्शन के सर्वर से जुड़ा है। इसका कंट्रोल यूनिट प्री-प्रोग्राम होती है। ईवीएम में जहां चिप डला है, वहां डला सॉफ्टवेयर ही सर्वेसर्वा होता है। चिप को लेकर दिग्विजय ने सवाल किया कि यह वन टाइम प्रोग्रामेबल चिप है या मल्टीलेवल प्रोग्रामेबल।

दिग्विजय सिंह का कहना है कि मैंने मुख्यमंत्री काल में टीएन सेशन साहब का जमाना देखा है। हम लोग कुछ कह दें तो ईसीआई (इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया) नोटिस दे देता है। नरेंद्र मोदी कर्नाटक में कहें कि बजरंग बली की जय बोलो और कमल का बटन दबाओ तो उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता। कई बार मेरी बात पर आप लोग और मेरी पार्टी भी भरोसा नहीं करती है। हमें ईवीएम के वीवीपैट और चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर भरोसा नहीं। केवल सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है। 2024 के बाद लोकतंत्र नहीं रहेगा। चुनाव बैलेट पेपर से हों। चुनाव आयोग को ईवीएम से इतना ही प्रेम है तो वीवीपैट की पर्ची वोटर के हाथ में दें।

आस्ट्रेलिया की तर्ज पर वीवीपैट पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं डालते। आज विश्व में 5 देश ऐसे हैं, जहां ईवीएम से वोट डाला जाता है। यहां सॉफ्टवेयर पब्लिक डोमेन में है। हमारे यहां 2003 से ही ऐसा नहीं है। कहते हैं इसमें समय लगेगा। अगर 5 साल के लिए सरकार तय करने के लिए 24-48 घंटे का समय भी नहीं दे सकते, हमसे हफ्तेभर ईवीएम की रखवाली कराते हैं, तो ईमानदारी से वोटिंग और काउंटिंग क्यों न हो। चुनाव आयोग का कहना है कि सॉफ्टवेयर को पब्लिक डोमेन में नहीं रख सकते क्योंकि इसका दुरुपयोग हो सकता है। ये तो और भी खतरनाक है कि चुनाव आयोग मानता है इसका दुरुपयोग हो सकता है। कर्नाटक में हमारी सरकार बनी। भाजपा को जहां पता है कि उनकी पार्टी वहां है ही नहीं, ऐसी जगह में ईवीएम में गड़बड़ी नहीं करेंगे। मप्र में 230 सीटों पर गड़बड़ी की। 120-130 सीटों पर नहीं। 10 प्रतिशत का स्विंग किया, इसलिए हम कुछ सीटें 60-70 हजार एक लाख से हार गए।

दिग्विजय सिंह का कहना है कि 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में चुनिंदा सीटों पर खेल किया था। केंद्र के दो-दो मंत्री यहां तैनात किए गए। जब शिवराज सिंह के नेतृत्व में भाजपा 60-70 सीटों पर जीती थी, तब अमित शाह दर-दर भटके और फिर ये पूरा खेल किया गया। ईवीएम प्रामाणिकता को लेकर कोई भी जानकारी नहीं है। सॉफ्टवेयर कौन डाल रहा है, इसकी कोई जानकारी भी नहीं है। सॉफ्टवेयर बनाने वाला, डालने वाला और सॉफ्टवेयर ही तय करेगा कि सरकार किसकी बनेगी। वोट डालने के बाद 7 सेकंड के लिए वीवीपैट में लाइट जलती है। वोटर सिर्फ इसमें पर्ची देखकर चला जाता है। दिग्विजय ने कहा, नरेंद्र मोदी-अमित शाह का जो आत्मविश्वास है, 2014 में कहा- 272 सीटें मिलेंगी 284 मिलीं। 2019 में कहा- 300 के पार होगी, सीटें मिलीं 303 और अब कह रहे हैं 400 पार। हम इस फासिस्ट सिस्टम को नहीं चलने देंगे। मोदी ने पुलवामा के नाम पर वोट मांगे, मामा ने लाड़ली बहना को लेकर वोट मांगे। अब कह रहे हैं रामलला हम आएंगे। ये नरेटिव सेट कर रहे हैं।

● डॉ. जय सिंह सेंधव

अंग्रेजी में एक कहावत है- वेल बिगेन इज हाफ डन... कुछ इसी तर्ज पर मप्र के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का शासन चल रहा है। उन्होंने जिस तरह अपने शासन की शुरुआत की है, उससे प्रदेश में पहली बार सरकार की धमक दिखाई और सुनाई दे रही है। मोहन 'राज' की जीरो टॉलरेंस नीति का असर देखने को मिल रहा है, जिससे जनता खुश और अफसर दुरुस्त नजर आ रहे हैं।

जीरो टॉलरेंस नीति से हड़कंप

डॉ. मोहन यादव ने जब मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, तो हर कोई यही मान रहा था कि लंबा अनुभव नहीं होने के कारण उनको शासन करने में कई समस्याओं को झेलना होगा। लेकिन मोहन यादव ने अपने अब तक के शासनकाल में यह दिखा दिया है कि वे शासन और प्रशासन के असली डॉक्टर हैं। उन्होंने जिस तरह सुशासन का राज्य स्थापित करने के लिए ताबड़तोड़ कदम उठाया है, उसकी हर तरफ सराहना हो रही है। उनकी जीरो टॉलरेंस नीति भाषणों में नहीं बल्कि हकीकत में नजर आ रही है। अभी तक जितने भी अफसरों ने जनता के साथ दुर्व्यवहार या अन्य तरह के गलत कार्य किए हैं, उन्हें हटाने में मुख्यमंत्री ने तनिक भी देरी नहीं की है। इसका परिणाम यह देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस के नेता भी उनकी वाहवाही कर रहे हैं।

गौरतलब है कि मप्र की नौकरशाही और अफसरों की भर्राशाही की शिकायतें लगातार सामने आती रही हैं। पूर्ववर्ती सरकारों में संघ और संगठन के नेता सरकार से अफसरों की शिकायत कर-करके थक जाते थे, लेकिन एक-दो के खिलाफ ही कार्यवाही होती थी। फील्ड में पदस्थ अफसर जनता से दुर्व्यवहार करते थे, तो उन पर नकेल कसने की हिम्मत कोई नहीं करता था। इसी व्यवस्था में रच-बस गए अफसर अब जब मोहन 'राज' में अपनी लालफीताशाही का दंभ दिखा रहे हैं तो सरकार उन पर कार्यवाही करने में तनिक भी देरी नहीं कर रही है। इसका असर यह हो रहा है कि जनता के मन में मुख्यमंत्री रच-बस गए हैं।

प्रदेश में अधिकारियों के आपा खोने के मामले बढ़ते जा रहे हैं। सबसे पहले शाजापुर के कलेक्टर किशोर कान्याल का मामला सामने आया था। उन्होंने हड़ताल समाप्त कराने को लेकर बैठक में एक ड्राइवर से कहा था, तुम्हारी औकात क्या है। इसके बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर उन्हें हटाकर मंत्रालय में उप सचिव बनाया गया था। मुख्यमंत्री ने सख्त शब्दों में कहा था कि आमजन से ऐसी भाषा बर्दाश्त नहीं होगी। यह गरीबों की सरकार है। इसके बाद देवास जिले के सोनकच्छ की तहसीलदार का मामला सामने आ गया, जिसमें वह किसानों पर भड़क गईं। उमरिया जिले के बांधवगढ़ के एसडीएम अमित सिंह ने तो कुछ युवकों से सड़क पर मारपीट कर दी। मुख्यमंत्री ने इंटरनेट मीडिया (एक्स) पर भेजी पोस्ट में कहा कि, बांधवगढ़ एसडीएम द्वारा दो युवकों से मारपीट की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। एसडीएम को निलंबित करने के निर्देश दिए हैं। मप्र में सुशासन की सरकार है। आमजन से इस तरह का अमानवीय व्यवहार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री के निर्देश पर एसडीएम को निलंबित कर दिया गया है।

पूर्व मुख्य सचिव केएस शर्मा का कहना है कि अधिकारियों को यह पता नहीं है कि उनकी भूमिका क्या है। उन्हें जो अधिकार मिलते हैं उसे लेकर उन्हें गलतफहमी हो जाती है। उन्हें लगता है वह जनता से ऊपर हैं। अधिकारों के साथ जिम्मेदारियां भी आती हैं, जिन्हें अधिकारियों को समझना चाहिए। मैं समझता हूं वरिष्ठ अधिकारी जिस तरह से दुर्व्यवहार कर रहे हैं इसे रोकने के लिए उन्हें प्रशिक्षण की आवश्यकता है। दूसरी बात यह कि ऐसे अधिकारियों को सिर्फ हटा देना पर्याप्त नहीं है। इन्हें दंडित भी करना चाहिए। उनकी सीआर में घटना का उल्लेख किया जाना चाहिए। दरअसल, 2 जनवरी को ट्रक और बस ड्राइवरों की हड़ताल के दौरान शाजापुर कलेक्टर किशोर कान्याल ने बैठक में ड्राइवर से कहा था, क्या करोगे तुम, क्या औकात है तुम्हारी? इस पर उस व्यक्ति ने कहा था यह लड़ाई इसलिए लड़ रहे हैं, क्योंकि मेरी कोई औकात नहीं है। इंटरनेट मीडिया पर वीडियो बहु प्रसारित होने के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कान्याल को हटाने

अब तक कईयों पर कार्यवाही

मप्र में अभी तक जो नौकरशाही निरंकुश होकर काम कर रही थी, अब वह संवेदनशील नजर आने लगी है, इसकी वजह यह है कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव अफसरों की असंवेदनशीलता तनिक भी बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, उन्होंने अभी तक यह दिखा दिया है कि जनता ही सर्वोपरि है। इसका आंकलन इससे लगाया जा सकता है कि वे अब तक 9 कलेक्टर, 3 एसपी, 1 संभागायुक्त को मैदानी पोस्टिंग से हटाकर भोपाल बुला चुके हैं। कुल 45 आईएएस अफसरों को इधर से उधर किया है। इनमें अतिरिक्त मुख्य सचिव से लेकर कलेक्टर शामिल हैं। 11 आईपीएस भी प्रभावित हुए। चितरंगी एसडीएम को हटाने से पहले 24 जनवरी को बांधवगढ़ एसडीएम और 15 जनवरी को सोनकच्छ तहसीलदार को हटाया था। मुख्यमंत्री के इस कदम से अफसरशाही में जहां एक तरफ संवेदनशीलता दिखने लगी है, वहीं प्रदेश में सुशासन की झलक नजर आ रही है। गौरतलब है कि पूर्ववर्ती सरकारों के समय ऐसा लगता था कि सरकार और नौकरशाही के बीच तलवारें खिंची हुई हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि नौकरशाही की तलवार बहुत बारीकी और बिना आवाज के चलती थी, जबकि सरकार की तलवार भले ही मार नहीं रही थी, पर आवाज बहुत करती थी। आमतौर पर मजबूत सरकारों और सरकारों के मजबूत नेतृत्व को अपनी नौकरशाही को धमकाने या चमकाने की जरूरत नहीं होती।

के निर्देश दिए थे। उन्हें मंत्रालय में उप सचिव पदस्थ किया गया था। वहीं 15 जनवरी को सोनकच्छ की तहसीलदार अंजली गुप्ता का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर बहुप्रसारित हुआ, जिसमें वह एक किसान को कह रही हैं कि, चूजे हैं, ये अंडे से निकले नहीं मरने-मारने की बड़ी-बड़ी बात करते हैं। मैं अभी तक आराम से बात कर रही थी, लेकिन आज इसने कैसे बोल दिया मैं रिस्पान्सिबल हूं। मैं तहसीलदार हूं, शासन को आपने चुना, मैंने चुना क्या? किसान ने अपने खेत में निजी कंपनी को खड़ी फसल में टावर लगाने से मना कर दिया था, जिससे विवाद की स्थिति बनी थी। मुख्यमंत्री के निर्देश पर तहसीलदार को हटा दिया गया था। वहीं 22 जनवरी को उमरिया जिले के बांधवगढ़ के एसडीएम अमित सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया में सामने आया है। वीडियो में अमित सिंह सड़क पर कुछ युवकों से मारपीट करते दिखाई दे रहे हैं। पीड़ित प्रकाश दाहिया ने इस मामले में उमरिया के सिविल लाइन थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। कहा जा रहा है कि युवक ने एसडीएम की गाड़ी को ओवर टेक करने की कोशिश की थी, जिससे वह गुस्सा हो गए थे। मुख्यमंत्री के निर्देश पर अमित सिंह को निलंबित कर दिया गया।

यही नहीं गत दिनों सिंगरौली में महिला कर्मचारी द्वारा एसडीएम का लेस बांधते हुए फोटो वायरल हुआ था। मुख्यमंत्री ने उसे भी गंभीरता से लिया और एसडीएम को हटा दिया। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि सिंगरौली जिले के चितरंगी में एसडीएम द्वारा एक महिला से उनके जूते के फीते बंधवाने का मामला सामने आया है, जो अत्यंत निंदनीय है। इस घटनाक्रम को लेकर एसडीएम को तत्काल हटाने के निर्देश दिए हैं। हमारी सरकार में नारी सम्मान सर्वोपरि है। इसके बाद भोपाल में एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि गनीमत है कि एसडीएम को सिर्फ हटाया, सस्पेंड नहीं किया। बीमार हैं तो छुट्टी पर चले जाते, किसने रोका है। दरअसल, 22 जनवरी को जिले के चितरंगी में मंदिर के बाहर एक महिला कर्मचारी एसडीएम असवन राम चिरावन के जूते की लेस बांधते नजर आई थी। वहां मौजूद किसी व्यक्ति ने इसका वीडियो बना लिया। इसके फोटो भी सामने आए हैं। एसडीएम असवन राम चिरावन ने बताया कि महिला कर्मचारी उनकी मदद कर रही थी। महिला कर्मचारी ने भी कहा कि जूते की लेस उन्होंने अपनी स्वेच्छा से बांधी। असवन राम की जगह माईकेल तिर्की को चितरंगी एसडीएम बनाया गया है। एसडीएम असवन राम चिरावन से इस बारे में पूछा गया तो उनका कहना था कि 30 दिसंबर को उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला एनएच 39 के निर्माण कार्यों की स्थिति जानने के लिए चितरंगी आए थे। प्रोटोकॉल के अनुसार, मैं भी मौजूद था। यहां ब्रिज के निरीक्षण के दौरान मेरा पैर एक एंगल में फंस गया। इससे बायां पैर फ्रैक्चर हो गया। मुझे चलने, झुकने और अन्य कार्य करने में तकलीफ हो रही थी। 22 जनवरी को राज्यमंत्री राधा सिंह हनुमान मंदिर में दर्शन करने आई थीं। वहां मैं भी मौजूद था। पैर में फ्रैक्चर के कारण मंदिर के बाहर जूते पहनने में परेशानी हो रही थी। ये देख वहां मौजूद निर्मला देवी ने जूते की लेस बांधने में मेरी मदद की। मैंने उन्हें ऐसा करने के आदेश नहीं दिए थे। निर्मला देवी ने कहा, एसडीएम साहब के पैर में चोट लगने के कारण वो लेस बांधने में असमर्थ थे, इसलिए मैं अपनी मर्जी से उनके पास गई और उनकी मदद की। इसके लिए उन्होंने मुझ पर कोई दबाव नहीं बनाया था।

भोपाल के रवींद्र भवन में मप्र सिविल सेवा परीक्षा-2019 एवं 2020 में चयनित 559 अधिकारियों को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने नियुक्ति पत्र दिए। इस मौके पर सिंगरौली का उदाहरण देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं अभी एक कठोर निर्णय लेकर आया हूं। हमने कल एक चित्र देखा कि एक एसडीएम साहब अपने जूते के फीते महिला से बंधवा रहे थे। मुझे मालूम है कि महिला के बांधने का भाव अपने साहब के प्रति कोई खराब नहीं हो सकता। यह भी पता चला कि उन एसडीएम साहब के पैर में कोई चोट है। यह उनकी व्यक्तिगत बात हो सकती है। लेकिन पब्लिकली इसका चित्र क्या बनेगा? यह उनसे कौन पूछने जाएगा कि वह बीमार है या नहीं है। इम्पैक्ट पूरे समाज पर आएगा। भले ही बीमार हैं या तो छुट्टी पर चले जाते, किसने रोका है। आपने पब्लिकली लेस बंधवाई, फिर हम तो अपने दिन के कार्यक्रम की शुरुआत ऐसे ही करते हैं। कैसे यह बर्दाश्त कर सकते हैं। जस्टिस नहीं किया जा सकता। हम आपको सस्पेंड नहीं कर रहे। लेकिन वहां से तो हटा देंगे। अगली बार आपको ध्यान में आ जाएगा कि आप क्या कर रहे हो।

● सुनील सिंह

सख्त फैसले लेने में संकोच नहीं

पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार, अपनी लोकप्रियता के चरम पर भी, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भाजपा आलाकमान से संघर्ष करना पड़ा, जिनका मानना था कि अनियंत्रित नौकरशाही को संभालना भी एक कठिन कार्य था। शिवराज के विपरीत, यादव क्षेत्रीय प्रशासनिक मामलों की समीक्षा भोपाल के बजाय अपने मुख्यालय में करते हैं। मुख्यमंत्री ने अपर मुख्य सचिवों को जिलों और जोनों के विकास कार्यों की समीक्षा के लिए जमीनी तौर पर काम करने का निर्देश दिया है। इसी प्रकार, एडीजी को उनके अधिकार क्षेत्र वाले मुख्यालयों का दौरा करके कानून व्यवस्था की देखभाल के लिए प्रतिनियुक्त किया जाता है। दस वरिष्ठ आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को राज्य के 10 क्षेत्रों की देखभाल का जिम्मा सौंपा गया था। भाजपा के एक राज्य पदाधिकारी का कहना है कि चाहे लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने की बात हो या भोपाल के बाहर कैबिनेट बैठक बुलाने की बात हो, वह (यादव) कुछ चीजों को बदलने की कोशिश कर रहे हैं और संदेश दे रहे हैं कि वह सख्त फैसले लेने में संकोच नहीं करेंगे। प्रदेश भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि मुख्यमंत्री जानते हैं कि व्यापक शिकायत थी कि नौकरशाह शिवराज सिंह चौहान की सरकार चलाते थे। उन्होंने बताया कि कैलाश विजयवर्गीय जैसे कई नेताओं ने सार्वजनिक रूप से शिवराज से पार्टी कार्यकर्ताओं को शांत करने के लिए नौकरशाही को नियंत्रित करने के लिए कहा। बाद में शिवराज को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने नौकरशाहों को डांटना शुरू कर दिया। यादव को शिवराज की गलती पता है, जो पिछले 18 साल से सत्ता के शीर्ष पर थे, वह न केवल नौकरशाही की जवाबदेही तय करना चाहते हैं, बल्कि यह संदेश भी देना चाहते हैं कि नौकरशाहों से निपटने में लोगों की धारणा अधिक मायने रखती है।

पर्यटन का प्राण बना इंदौर

226 इकाइयां संचालित कर रहीं 350 से अधिक होम स्टे

हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की तर्ज पर मप्र में भी कोविडकाल से पूर्व आरंभ हुई होम स्टे की परियोजना अब गति पकड़ने लगी है। वर्तमान में होम स्टे के लिए 226 इकाइयां पंजीकृत हैं, जिनके माध्यम से 350 से अधिक होम स्टे (कमरे) पर्यटकों के लिए उपलब्ध हैं। एक इकाई एक से अधिक होम स्टे का संचालन कर रही है। पर्यटन बोर्ड की ओर से दी गई सब्सिडी से बने इन होम स्टे का संचालन ज्यादातर महिलाएं कर रही हैं, जिन्हें पर्यटन विभाग समय-समय पर प्रशिक्षित करता है। कई जनजातीय महिलाओं को भी इससे रोजगार के अवसर उपलब्ध हुए हैं। मप्र पर्यटन बोर्ड ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के उन सभी घर मालिकों को आय का अवसर देने वाली होम स्टे परियोजना वर्ष 2018 में आरंभ की थी। ये ऐसे लोगों के लिए है, जो घरेलू और अंतरराष्ट्रीय आगंतुकों के लिए अपने घर का एक हिस्सा पर्यटक आवास के रूप में देने के इच्छुक होते हैं। मप्र में पर्यटन गंतव्यों के निकट शहरों और गांवों में उपलब्ध पर्यटक आवास की पूर्ति इनके माध्यम से हो रही है। मप्र पर्यटन बोर्ड के संचालक (स्किल) मनोज कुमार सिंह का कहना है कि होम स्टे के क्षेत्र में वर्ष 2023 उल्लेखनीय रहा है। इस वर्ष 28 गांवों में 64 नए होम स्टे बनाए गए तथा 67 गांवों में 313 निर्माणाधीन हैं।

यूं तो इंदौर मप्र का सबसे धनाढ्य, तेजतर्रार और रहने के लिए सबसे श्रेष्ठ शहर है, किंतु अब पर्यटन पर जाने और खर्च करने के मामले में भी इंदौरी पीछे नहीं हैं। दरअसल, प्रदेश के कुल पर्यटन में अकेले इंदौर की हिस्सेदारी 30 प्रतिशत है। इंदौरियों में अब एक बदलाव और देखने को मिल रहा है कि वे अब राजस्थान, गुजरात या अन्य राज्यों में घूमने जाने के बजाय पहली प्राथमिकता मप्र के ही अनएक्सप्लोर क्षेत्रों को दे रहे हैं। इसका लाभ यह हो रहा है कि राज्य का धन राज्य में ही खर्च हो रहा है।

प्रदेश के पर्यटन स्थलों की सैर करने वालों में अब इंदौरियों की सहभागिता तेजी से बढ़ने लगी है। एक वक्त था जब इंदौरी अपनी छुट्टियां प्रदेश के बाहर जाकर मनाना पसंद करते थे, किंतु अब इंदौरियों की पसंद में शहर के आसपास के पर्यटन स्थल ज्यादा शामिल हो रहे हैं। यहां के पर्यटक, विशेषकर युवा ऐसे स्थानों पर जाना पसंद कर रहे हैं, जहां जाकर वे एक-दो दिन में ही लौटकर वापस काम पर आ सकें। इससे पर्यटन भी हो जाता है और काम भी होता रहता है। इन स्थानों के प्रति जाने वालों की न केवल संख्या बढ़ी है बल्कि उन स्थानों पर पर्यटकों के लिए सुविधा और उनके मनोरंजन के लिए गतिविधियां भी बढ़ी हैं। बीते करीब डेढ़ वर्ष में स्थानीय पर्यटन स्थलों पर इंदौर के सैलानियों की संख्या में 30 प्रतिशत तक का इजाफा हुआ है। बदली जीवनशैली, फाइव डेज वर्किंग (सप्ताह में केवल पांच दिन काम), निजी वाहनों की बढ़ी संख्या और पर्यटक स्थलों पर बेहतर होती सुविधाओं के चलते लोग दूर जाने से पहले आसपास के पर्यटक स्थलों की सैर करना पसंद करने लगे हैं। स्थानीय पर्यटन स्थलों में इंदौरी जिन स्थानों पर सबसे ज्यादा जा रहे हैं उनमें पचमढ़ी, मांडू, महेश्वर, हनुवंतिया जैसे चिर-परिचित स्थान तो हैं ही, किंतु अब गांधीसागर, केरवा डेम, पातालपानी, मढ़ई और रातीबड़ जैसे स्थान भी खासे पसंद किए जा रहे हैं। स्थिति यह है कि चिर-परिचित स्थान को चुनने से पहले इंदौर के घुमंतू उन स्थानों की पूछपरख कर रहे हैं, जिनके बारे में कम ही लोग जानते हैं।

मप्र पर्यटन विभाग के श्याम तिवारी का कहना है कि आईटी सहित अन्य इंडस्ट्री में कार्य करने वाले युवा ऐसे स्थानों पर जाना पसंद कर रहे हैं जिनके बारे में कम ही लोग जानते हों और जहां एक या दो दिन में जाकर आया जा सके। पचमढ़ी पहुंचने वाले कुल पर्यटकों में से करीब 30 प्रतिशत पर्यटक प्रदेश के ही रहते हैं। इनमें भी करीब 25 प्रतिशत तो इंदौर के होते हैं। इसके अलावा हनुवंतिया और गांधीसागर जाने वाले इंदौरी पर्यटकों की संख्या भी करीब 40 प्रतिशत है। वर्तमान में जाम गेट के समीप गांवों में बनने वाली टेंट सिटी, पातालपानी और गांधीसागर के प्रति पूछपरख बढ़ी है। ये ऐसे स्थान हैं जहां अब निजी एजेंसियों द्वारा भी सुविधाएं प्रदान की जाने लगी हैं। ट्रेवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ मप्र व छत्तीसगढ़ के चैप्टर चेयरमेन हेमेंद्र सिंह जादौन का कहना है कि इंदौर के आसपास के पर्यटक स्थलों पर जाने वालों में युवाओं की संख्या सर्वाधिक है। युवा समूह में यहां जाना पसंद कर रहे हैं। परिणाम यह है कि सप्ताह के अंत में या जब दो दिन का अवकाश हो, तब तो शहर के आसपास के पर्यटक स्थलों पर कमरे मिलना मुश्किल हो जाता है। महाकाल कॉरिडोर और ओंकारेश्वर में आदिगुरु शंकराचार्य की प्रतिमा स्थापित होने के बाद से इन दोनों स्थानों पर दर्शन के लिए बाहर से आने वाले पर्यटक इंदौर के आसपास के पर्यटक स्थलों की सैर करने में भी रुचि ले रहे हैं। पर्यटक स्थलों पर बढ़ी रोमांचक गतिविधियों के कारण भी यहां के युवा अन्य प्रदेश में जाने से पहले इन स्थानों को तवज्जो दे रहे हैं।

ट्रेवल एजेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया मप्र चैप्टर के चेयरमेन शैलेंद्र खरे का कहना है कि विगत करीब डेढ़ वर्ष में प्रदेश के पर्यटक स्थलों पर जाने वालों की संख्या में 30 प्रतिशत तक की बढ़त हुई है। इंदौर के पर्यटक ऐसे स्थानों पर जाना पसंद कर रहे हैं, जहां भीड़ कम और रोमांच ज्यादा हो। बीते वर्षों में प्रदेश के पर्यटक स्थलों का विकास भी बेहतर हुआ है और सुविधाएं भी बढ़ी हैं। बात अगर नए स्थानों की करें, तो गांधीसागर, केरवा डेम, मढ़ई और रातीबड़ के लिए भी लोग खूब जानकारी ले रहे हैं और बुकिंग करवा रहे हैं। यही नहीं, चीतों का घर बने कूनो अभयारण्य जाने के लिए भी रुझान बढ़ा है। उधर, साल 2028 में उज्जैन में सिंहस्थ होना है, जिसको लेकर अभी से ही तैयारी शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि, इंदौर से उज्जैन तक के मार्ग को सिक्स लेन बनाने को लेकर भी तैयारी चालू कर दी गई है। सिंहस्थ में लाखों की संख्या में श्रद्धालु दुनियाभर से आते हैं। ऐसे में आवागमन में किसी भी तरह की समस्या ना हो इसको लेकर प्रस्ताव तैयार किया गया है।

● जितेंद्र तिवारी

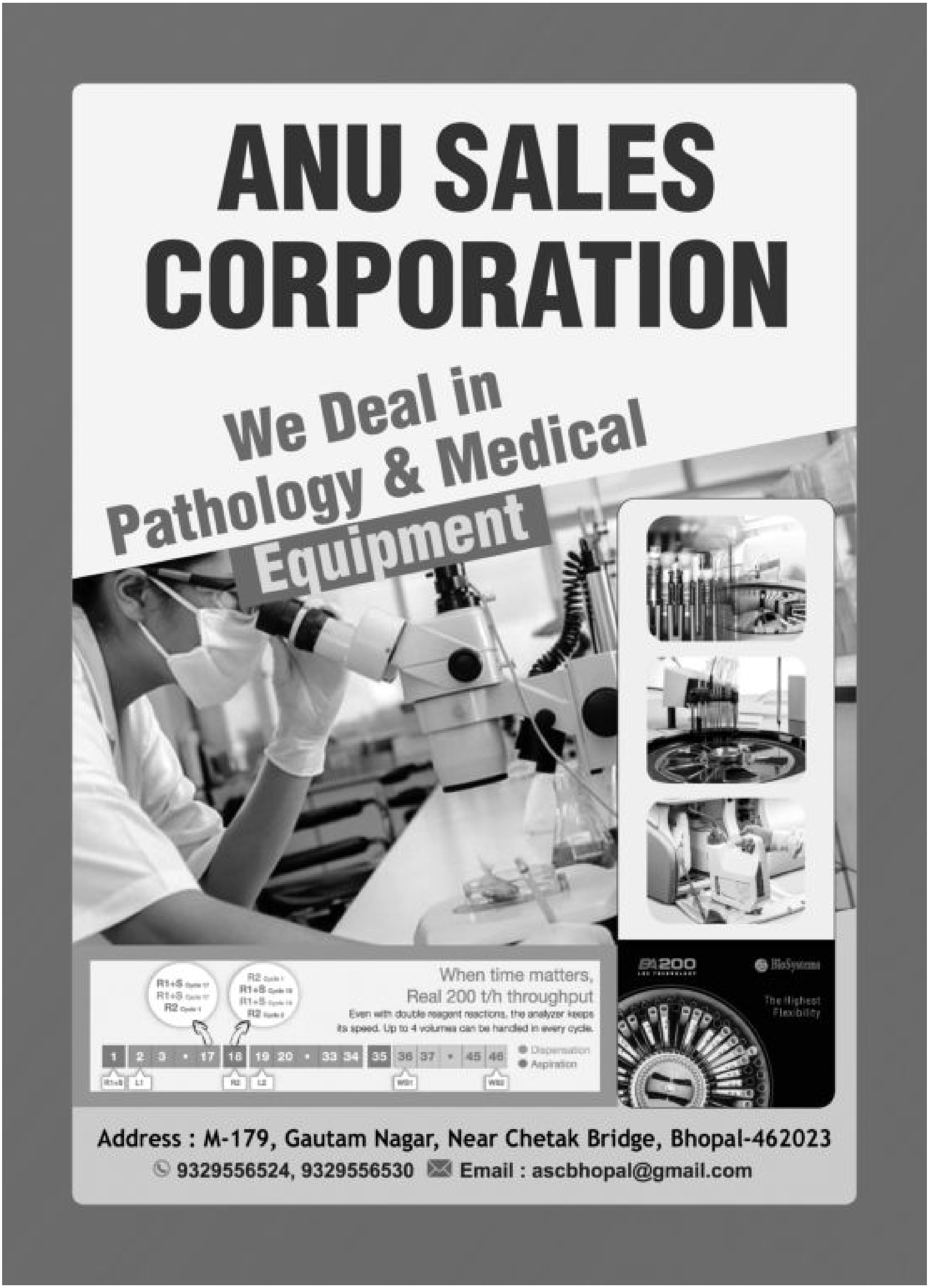
ANU SALES
CORPORATION
We Deal in
Pathology & Medical
Equipment
When time matters,
Real 200 t/h throughput
Even with double reagent reactions, the analyzer keeps its speed. Up to 4 volumes can be handled in every cycle.
Dispensation
Aspiration
BioSystems
The Highest
Flexibility
Address : M-179, Gautam Nagar, Near Chetak Bridge, Bhopal-462023
9329556524, 9329556530 Email : ascbhopal@gmail.com

75वें
गणतंत्र दिवस
की शुभकामनाओं सहित...
सचिव ● भार साधक अधिकारी
कृषि उपज मंडी समिति, बैरसिया, जिला - भोपाल

75वें
गणतंत्र दिवस
की शुभकामनाओं सहित...
सचिव ● भार साधक अधिकारी
कृषि उपज मंडी समिति, सिरोंज, जिला-विदिशा

75वें
गणतंत्र दिवस
की शुभकामनाओं सहित...
सचिव ● भार साधक अधिकारी
कृषि उपज मंडी समिति, नसरुल्लागंज, जिला-सीहोर

75वें
गणतंत्र दिवस
की शुभकामनाओं सहित...
अपील
♦ सभी किसान भाई मुख्यमंत्री हम्माल तुलावटी योजना का लाभ प्राप्त करें।
♦ मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का लाभ प्राप्त करें।
सचिव ● भार साधक अधिकारी
कृषि उपज मंडी समिति, अशोकनगर

75वें
गणतंत्र दिवस
की शुभकामनाओं सहित...
अपील
♦ सभी किसान भाई मुख्यमंत्री हम्माल तुलावटी योजना का लाभ प्राप्त करें।
♦ मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का लाभ प्राप्त करें।
सचिव ● भार साधक अधिकारी
कृषि उपज मंडी समिति, डबरा, जिला-ग्वालियर

75वें
गणतंत्र दिवस
की शुभकामनाओं सहित...
अपील
♦ नीलामी के समय किसान भाई अपने ढेर पर उपस्थित रहें।
♦ मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का लाभ प्राप्त करें।
♦ मंडी प्रांगण में प्रवेश करते समय अपनी कृषि उपज आवश्यक रूप से दर्ज कराएं।
♦ सही तौल एवं समय पर भुगतान पाएं।
♦ किसान भाई अपनी फसल का क्रय-विक्रय मंडी प्रांगण में ही करें।
♦ मुख्यमंत्री हम्माल तुलावटी योजना का लाभ प्राप्त करें।
सचिव ● भार साधक अधिकारी
कृषि उपज मंडी समिति, उज्जैन

२६ जनवरी
75वें
गणतंत्र दिवस
की शुभकामनाओं सहित...
अपील
♦ मंडी प्रांगण में प्रवेश करते समय अपनी कृषि उपज आवश्यक रूप से दर्ज कराएं।
♦ मुख्यमंत्री हम्माल तुलावटी योजना का लाभ प्राप्त करें।
♦ सही तौल एवं समय पर भुगतान पाएं।
♦ मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का लाभ प्राप्त करें।
♦ नीलामी के समय किसान भाई अपने ढेर पर उपस्थित रहें।
♦ किसान भाई अपनी फसल का क्रय-विक्रय मंडी प्रांगण में ही करें।
सचिव ● भार साधक अधिकारी
कृषि उपज मंडी समिति, देवास

मोदी जी की गारंटी
यानी गारंटी पूरी होने की गारंटी
"हर संकल्प पूरा करने को प्रतिबद्ध" - डॉ. मोहन यादव,
मध्यप्रदेश संकल्प पत्र 2023 में उल्लेखित कुछ प्रमुख संकल्प
सशक्त नारी
समृद्ध किसान
जनजातीय कल्याण
सुशासन एवं कानून व्यवस्था
सबका साथ, सबका विकास
उत्तम शिक्षा एवं सक्षम युवा
सुदृढ़ आधारभूत संरचना
स्वस्थ प्रदेश
सांस्कृतिक धरोहर एवं विकसित पर्यटन
प्रगतिशील अर्थव्यवस्था एवं औद्योगिक विकास
डॉ. मोहन यादव, मुख्यमंत्री
एमपी के मन में मोदी
सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास

मोहन का सुशासन

जैसा नाम वैसा शासन का आगाज कर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेश की साढ़े आठ करोड़ आबादी का मन मोह लिया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का अब तक का कार्यकाल ऐसा रहा है जिसमें सुशासन की पूरी झलक देखने को मिली है। जहां उन्होंने विकास कार्यों को गति दी है, वहीं नए कार्यों का भूमिपूजन और लोकार्पण भी किया है। साथ ही जनता के मन में अपनी सरकार होने का भाव भरा है। जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रहे मुख्यमंत्री यादव तत्काल फैसले ले रहे हैं। प्रदेशवासियों के स्वास्थ्य से लेकर आत्मनिर्भर बनाने तक की योजनाओं पर काम हो रहा है। युवाओं, महिलाओं, किसानों, मजदूरों पर सरकार का अधिक फोकस है।

● राजेंद्र आगाल

मप्र में मुख्यमंत्री का दायित्व संभालने के बाद डॉ. मोहन यादव ने आम जनता के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का संकल्प लिया है। मप्र के 19वें मुख्यमंत्री के रूप में डॉ. मोहन यादव ने जिस मजबूत इच्छाशक्ति के साथ जनता के हितों को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता में रखा है, उससे पूरे राज्य में एक सकारात्मक संदेश गया है कि यह सरकार जनता की सेवा के लिए है। यह सरकार जनभावनाओं के अनुरूप विकास के पथ पर आगे बढ़ेगी। खास बात यह कि डॉ. मोहन यादव के द्वारा अब तक लिए गए तमाम निर्णयों में प्रदेश की लंबित कई समस्याओं के निदान की चिंता भी दिखाई पड़ती है। नए मुख्यमंत्री ने प्रदेश की समस्याओं के निदान के लिए जैसी संजीदगी दिखाई है, उसकी दूसरी मिसाल देखने को नहीं मिलती। अपने शुरुआती कार्यकाल में ही मुख्यमंत्री ने विकास और सुशासन की स्थापना पर फोकस कर रखा है, जिससे मप्र में चारों तरफ विकास और सुशासन नजर आने लगा है।

ध्वनि प्रदूषण को लेकर संजीदा

मोहन सरकार ने ध्वनि प्रदूषण के मामलों की जांच के लिए एक फ्लाइंग स्क्वॉड भी गठित किया, जो निर्धारित सीमा से अधिक ध्वनि प्रदूषण की शिकायत मिलने पर क्षेत्र में जाकर सीधे कार्रवाई कर रही है। साथ ही धार्मिक स्थलों पर ध्वनि प्रदूषण की हर हफ्ते समीक्षा भी प्रदेश में शुरू की गई है, जिसका जमीनी असर दिखने लगा है। मुख्यमंत्री की शपथ लेने के तुरंत बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का पहला फैसला मप्र में धार्मिक स्थानों पर जोर से लाउडस्पीकर बजाने और खुले में मांस-अंडे की बिक्री पर सख्ती से रोक का रहा। इस फैसले का सभी ने स्वागत किया। प्रदेश के धार्मिक स्थलों में लगाए गए कानफोड़ू लाउडस्पीकर लंबे समय से आम जनता की परेशानी का सबब बन गए थे। चूंकि, यह मामला धार्मिक था, इसलिए इसके खिलाफ कोई कुछ नहीं कर पाता था, लेकिन मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने एक झटके में इस पर एक्शन लेकर अपने मजबूत इरादों को पहले दिन ही जता दिया। यही नहीं, खुले में मांस से लेकर अंडा बेचने पर भी उन्होंने रोक लगा दी। विपक्षी दलों ने इस आदेश में भाजपा और उसके अनुषांगिक संगठनों का साम्प्रदायिक एजेंडा देखा और इसे मुसलमानों के खिलाफ बताने की भी कोशिश की, लेकिन प्रदेश की आम जनता ने इसका स्वागत ही किया, क्योंकि यह नियम प्रदेश के सभी धार्मिक स्थलों के लिए समान रूप से लागू किया गया था। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी इस फैसले को देखें तो खुले में मांस की बिक्री सेहत के लिए हानिकारक है। यही वजह रही कि जनता की तरफ से इस फैसले की सराहना हुई।

मोहन सरकार का एक अहम फैसला राज्य में विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद भोपाल में एक भाजपा कार्यकर्ता पर हमला कर उसकी कलाई काटने के आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाने का था। अल्पसंख्यक समुदाय के आरोपियों के घर बुलडोजर चलवाकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने संदेश दिया कि अपराध नियंत्रण के मामलों में किसी भी तरह की कोताही प्रदेश में अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आरोपी को हर कीमत पर सबक सिखाया जाएगा। प्रदेश में इससे पहले मां, बहन और बेटियों के खिलाफ अत्याचार करने वाले आरोपियों के घर बुलडोजर चला करते थे, लेकिन मोहन सरकार ने एक माह के भीतर अवैध जगहों पर बुलडोजर चलाने का फैसला लेकर अपराधियों के मन में खौफ पैदा किया है। अपराधियों के नेटवर्क को तोड़ने और प्रदेश में आपराधिक गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए सरकार ने अपराधियों की जमानत निरस्त करने का भी बड़ा फैसला किया है।

मुख्यमंत्री के बड़े फैसले

मुख्यमंत्री के रूप में डॉ. मोहन यादव ने सरकार की तरफ से, अब तक जो निर्णय लिया है, वह जनता के बीच सराहा जा रहा है। उन्होंने पहला निर्णय लिया गया था वह लाउडस्पीकर और डीजे का अनियंत्रित प्रयोग प्रतिबंधित करने का था। इसी के साथ खुले में मांस, मछली की बिक्री पर प्रतिबंध। हुकुमचंद मिल के 4800 श्रमिक परिवारों को 224 करोड़ रुपए का बकाया भुगतान। तेंदूपत्ता संग्राहकों का मानदेय 3 हजार प्रति बोरा से बढ़ाकर 4 हजार रुपए किया। यातायात सुगमता के लिए भोपाल में बीआरटीएस हटाने का निर्णय। श्री अन्न को बढ़ावा देने के लिए रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना में किसानों को प्रति 10 रुपए किलो का अतिरिक्त प्रोत्साहन। दो लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई के विस्तार के लिए 5 हजार करोड़ की परियोजनाओं को मंजूरी दी। प्रदेशवासियों की सुविधा के लिए प्रदेश में संभाग, जिले, तहसील और पुलिस थानों की सीमाओं के पुनर्निर्धारण की प्रक्रिया प्रारंभ की। एक हजार से अधिक पुलिसकर्मियों को पदोन्नति दी। उज्जैन-इंदौर और धार जिले में जहां-जहां भगवान श्रीकृष्ण के चरण पड़े हैं, वहां तीर्थ स्थलों का विकास होगा। प्रदेश में श्री राम वन पथ गमन के विकास की कार्य योजना को चरणबद्ध तरीके से लागू करने का निर्णय लिया। उन्होंने नई शिक्षा नीति के अंतर्गत विद्यालयों और महाविद्यालयों के पाठ्यक्रम में वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी और रानी दुर्गावती की प्रेरणादायी वीरगाथा के विषय को शामिल करने का निर्णय लिया। वहीं हर जिले में एक शासकीय महाविद्यालय का पीएम उत्कृष्टता महाविद्यालय के रूप में उन्नयन, 350 करोड़ लागत से 6.67 किमी का इंदौर में बनेगा एलिवेटेड कॉरिडोर। ग्रीन बॉन्ड जारी कर जुटाए गए 308 करोड़ की राशि से खरगोन जिले के जलूद गांव में ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के एक महीने के कार्यकाल की बात करें तो इस दौरान 45 आईएएस और 11 आईपीएस अफसरों को इधर से उधर किया है, जिसमें 9 कलेक्टर, 3 एसपी और 1 संभागायुक्त को मैदानी पोस्टिंग से हटाकर भोपाल बुलाया। मुख्यमंत्री का पद संभालते ही डॉ. मोहन यादव शपथ लेने के तीसरे दिन ही छिंदवाड़ा पहुंचे और मंच से कहा कि कलेक्टर साहब ध्यान रखिए पटवारी से गलती हुई तो आप पर भी कार्रवाई होगी। जबकि गुना बस हादसे में 13 लोगों के मरने के बाद मुख्यमंत्री गुना पहुंचे और आरटीओ को सस्पेंड किया। यही नहीं उन्होंने परिवहन आयुक्त और विभाग के प्रमुख सचिव को हटा दिया। शाजापुर में कलेक्टर के औकात वाला वीडियो वायरल होने के बाद शाजापुर कलेक्टर को भी हटा दिया। इसके बाद एक महिला तहसीलदार के भी तीखे तेवरों के बाद उन्हें भी हटा दिया गया।

बीआरटीएस कॉरिडोर खत्म

मोहन सरकार का एक और बड़ा फैसला प्रदेश की राजधानी भोपाल में हमेशा सुर्खियों में रहने वाले बीआरटीएस (बस रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम) के खात्मे का रहा। भोपाल में निर्मित बीआरटीएस शुरू से विवादों में रहा। 13 वर्ष पहले शिवराज सरकार के कार्यकाल में बना यह बीआरटीएस 360 करोड़ रुपए खर्च के बाद भी सफल नहीं रहा। राजधानी के यातायात को सुगम बनाने के लिए इसे लाया गया था, लेकिन आए दिन लगने वाले जाम से ट्रैफिक व्यवस्था बेपटरी सी रही। शिवराज सरकार के साथ ही कमलनाथ सरकार भी इस मामले पर कोई एक्शन नहीं ले सकी, लेकिन मोहन सरकार ने ठोस निर्णय लेकर अपने भविष्य के एक्शन प्लान को बता दिया।

मोहन सरकार ने नौकरशाही पर नकेल कसते हुए पारदर्शी प्रशासन और जीरो टॉलरेंस नीति के माध्यम से सुशासन का संदेश दिया है। मुख्यमंत्री ने इस दौरान सभी को यह संदेश दिया है कि जनता को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए और जनता की समस्याएं अधिकारी तत्परता के साथ सुलझाने की कोशिश करें। मोहन सरकार ने एसीएस, एडीजी अधिकारियों को अपने कार्यालयों से बाहर निकलकर जमीन पर जाने के आदेश से प्रशासनिक गलियारों में हलचल मचाई है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गुना बस हादसे के लिए पूरी नौकरशाही को जिम्मेदार मानते हुए कलेक्टर पर एक्शन लेने के साथ ही अधिकारियों को सस्पेंड कर अपने बुलंद इरादे सभी के सामने जता दिए हैं। गुना में एक निजी बस और डंपर की टक्कर के बाद हुई जांच में सामने आया कि दोनों वाहनों का अवैध तरीके से संचालन किया जा रहा था। इसके बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गुना कलेक्टर, एसपी के साथ-साथ ट्रांसपोर्ट कमिश्नर और प्रमुख सचिव परिवहन को भी पद से हटाकर समूची नौकरशाही को कड़े लहजे में अपना संदेश दिया। प्रदेश के किसी सड़क हादसे में सरकार द्वारा अब तक की गई यह सबसे बड़ी कार्रवाई थी।

थानों की सीमा का पुनर्निधारण

प्रदेश में जन समस्याओं से जुड़ा एक मुद्दा जिलों, तहसीलों और थानों की सीमा के पुनर्निधारण का है, जिसके लिए एक कमेटी बनाने का फैसला मोहन सरकार ने किया है। इसकी शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इंदौर संभाग से की जाएगी। राज्य में कई तहसीलों और थानों की भौगोलिक सीमाएं ऐसी हैं, जो स्थानीय नागरिकों की पहुंच से सरकार और प्रशासन की खाई को चौड़ा करती है। मोहन सरकार ने अपने दूरदर्शी फैसले से इसे पाटने की कोशिश की है। मोहन सरकार ने इस विषय में पहल कर जनता को प्रशासन के करीब लाने की दिशा में अपने कदम तेजी से आगे बढ़ा दिए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उच्च शिक्षा में गुणवत्ता के उद्देश्य से हर जिले में प्रधानमंत्री एक्सीलेंस कॉलेज खोलने का निर्णय भी लिया है। यही नहीं, सरकार उच्च शिक्षा में प्रदेश के सभी सरकारी और निजी विश्वविद्यालय में डिजी लॉकर सिस्टम लाकर छात्र-छात्राओं की समस्याओं के निवारण हेतु गंभीर दिखी है। जमीनों के फर्जीवाड़े को रोकने की दिशा में रजिस्ट्री के साथ अब नामांतरण की प्रक्रिया भी शुरू होने जा रही है।

नए साल में देशभर में ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल से आम जनता को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। मोहन सरकार ने इसे देखते हुए ट्रांसपोर्टरों से सीधे बातचीत करने का फैसला किया, जिसमें प्रशासन ने बड़ी भूमिका निभाई। ट्रांसपोर्टरों के साथ बातचीत में जब शाजापुर के डीएम ने एक ड्राइवर को औकात बताने की नसीहत दी, तो मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने संवेदनशीलता की मिसाल पेश करते हुए डीएम को पद से हटाने में देरी नहीं की। इससे मुख्यमंत्री ने यह संदेश देने की कोशिश की कि उनकी सरकार में ड्राइवर का भी महत्व है। आम जनता के साथ जो अफसर बदसलूकी करेगा, उनकी सरकार में यह बर्दाश्त नहीं होगा। सरकार का मतलब जनता की सरकार है और अधिकारी को जनता का सम्मान भी करना होगा।

सागर में खुलेगा राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सागर की जनता को अभूतपूर्व सौगात देते हुए कहा कि शहर में इस वर्ष जून से राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय शुरू किया जाएगा, जो इसी सत्र से आरंभ भी होगा। उन्होंने बुंदेलखंड में रोजगार के नए अवसर सृजित करने के लिए बुंदेलखंड पैकेज की भी घोषणा की। उन्होंने सागर में सड़कों के जीर्णोद्धार के लिए भी 25 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। इससे युवाओं और बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सागर जिले के लिए 62.3 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण तथा 10.94 करोड़ के निर्माण कार्यों का भूमिपूजन किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने विशाल जनसमुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि आज समूचे भारत में उत्सव, त्यौहार का माहौल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश एक बार फिर दिवाली मना रहा है। उन्होंने कहा कि 22 तारीख का दिन इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित हो जाएगा। डॉ. सर हरि सिंह गौर की यह धरती त्याग, बलिदान और कर्तव्य परायणता के विशेषणों से जानी जाती है। डॉ. गौर ने सागर को विश्वविद्यालय के रूप में तब ऐसी सौगात दी थी, जब इतना बड़ा शिक्षा का केंद्र बनाने की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव का सागर में अभूतपूर्व स्वागत हुआ। मुख्यमंत्री जब विशाल जन आभार यात्रा के साथ पीटीसी ग्राउंड स्थित सभा स्थल पहुंचे तो तालियों की गूंज के साथ उनका भव्य स्वागत किया गया। उन्होंने दीप प्रज्ज्वलन कर अयोध्या के श्रीराम मंदिर की प्रतिकृति की पूजा-अर्चना और रामधुन के साथ जनमानस का आभार मानते हुए कार्यक्रम की शुरुआत की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि आल्हा-ऊदल की परंपरा को जीवंत रखने वाले बुंदेलखंड के लोगों ने कभी सिर नहीं झुकाया और अपनी आजादी किसी को नहीं सौंपी। बलिदान की परंपरा वाली यह धरती, उद्देश्यों के लिए कैसे जीते हैं, यह सिखलाती है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि बुंदेलखंड में रोजगार के नए आयाम के विस्तार के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने 50 हजार करोड़ रुपए से बीना रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट की सौगात दी है। साथ ही केन-बेतवा लिंक परियोजना के माध्यम से बुंदेलखंड की इस धरा को उपजाऊ बनाने का अभूतपूर्व कार्य शुरू किया जा रहा है।

अयोध्या जैसा चित्रकूट का विकास

मप्र सरकार चित्रकूट का अयोध्या की तर्ज पर विकास करेगी। इसे भगवान श्रीराम के जीवन से जुड़ा सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल बनाया जाएगा। श्रीराम वन गमन पथ के विकास की कार्ययोजना को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। उन सभी स्थानों को सड़क मार्ग से जोड़ा जाएगा, जहां से भगवान राम गुजरे थे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का कहना है कि धार्मिक विद्वानों के परामर्श से श्रीराम वन गमन पथ के सभी प्रमुख स्थलों का विकास किया जाएगा। अधिकारी जल्द ही इस रोडमैप को अमल में लाने के लिए काम शुरू करेंगे। संपर्क मार्ग से पथ को जोड़ने के बाद सरकार इसके आगे के चरण के लिए काम शुरू करेगी।

गौरतलब है कि मप्र में भगवान राम जिन रास्तों से होकर गुजरे हैं, उनमें सिंगरौर की पहचान तत्कालीन श्रृंगवेरपुर के रूप में की गई है। यह स्थान प्रयागराज में गंगा के बाएं किनारे पर है। यहां निषादराज गुह का शासन था। प्रयागराज में सिंगरौर के दूसरी तरफ कुरई नामक स्थान है। यहां एक मंदिर है, जिसमें राम, लक्ष्मण और सीताजी ने कुछ देर विश्राम किया था। कुरई से आगे राम प्रयाग पहुंचे थे। यहां भारद्वाज ऋषि से मुलाकात हुई। प्रयागराज में संगम के समीप यमुना नदी पार कर वे यहां से चित्रकूट पहुंचे। यहां वाल्मीकि आश्रम, मांडव्य आश्रम, भरतकूप आदि हैं। चित्रकूट में ही राम को मनाने के लिए भरत अपनी सेना के साथ पहुंचे थे। यहीं से वे राम की चरण पादुका लेकर लौटे। मंदाकिनी नदी के उस पार के चित्रकूट में उप्र सरकार ने बेहतर सुविधाओं का विकास किया है। वहां के घाट भी सुंदर हैं और पर्यटकों की संख्या भी अधिक होती है। अयोध्या से चित्रकूट तक 177 किमी के कॉरिडोर का निर्माण राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्राधिकरण कर रहा है।

2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, उसके बाद 2015 में केंद्र सरकार ने रामायण सर्किट नाम से एक परियोजना बनाकर भगवान श्रीराम से जुड़े 21 स्थानों को पर्यटन के एक कॉरिडोर से जोड़ने और तीर्थों के विकास की योजना बनाई थी। राम से जुड़े जिन ऐतिहासिक स्थलों की पहचान की गई, उनमें उप्र में 5, मप्र में 3, छत्तीसगढ़ में 2, महाराष्ट्र में 3, आंध्र प्रदेश में 2, केरल में 1, कर्नाटक में 1, तमिलनाडु में 2 और श्रीलंका में 1 स्थान शामिल था। कई संगठनों ने निजी तौर पर शोध कर जिन तीर्थों की पहचान की थी, उनकी संख्या 248 थी। केंद्र ने इस प्रोजेक्ट के लिए 13 हजार करोड़ रुपए आवंटित किए थे। इधर, तत्कालीन शिवराज सरकार ने अपने प्रोजेक्ट को रामायण सर्किट में शामिल करा लिया था, ताकि 40 प्रतिशत राशि केंद्र सरकार से मिल सके।

2 दशक बाद नदियां होंगी लिंक

मप्र सरकार, राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार के बीच गत दिनों श्रमशक्ति भवन स्थित जल शक्ति मंत्रालय के कार्यालय में संशोधित पार्वती-कालीसिंध-चंबल-ईआरसीपी लिंक परियोजना के त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, मप्र के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की उपस्थिति में समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित होने के बाद मप्र के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि 2003 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी के नेतृत्व में मप्र और राजस्थान की नदियों को लेकर एक योजना बनी थी। जिसका आशय दोनों राज्यों के लोगों को इन नदियों का लाभ पहुंचाना था। लेकिन 2004 में केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद इस योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। आज प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में लगभग दो दशकों से लंबित पार्वती-कालीसिंध-चंबल परियोजना अब मूर्त रूप ले सकेगी। इस परियोजना से मप्र के चंबल और मालवा-अंचल के 13 जिलों को लाभ पहुंचेगा। प्रदेश के ड्राई बेल्ट वाले जिलों जैसे मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, भिंड और श्योपुर में पानी की उपलब्धता बढ़ेगी और औद्योगिक बेल्ट वाले जिलों जैसे इंदौर, उज्जैन, धार, आगर-मालवा, शाजापुर, देवास और राजगढ़ के औद्योगीकरण को और बढ़ावा मिलेगा। इससे प्रदेश के मालवा और चंबल अंचल में लगभग तीन लाख हेक्टेयर का सिंचाई रकबा बढ़ेगा। परिणामस्वरूप इन अंचलों के धार्मिक और पर्यटन केंद्र भी विकसित होंगे। यह परियोजना निश्चित रूप से पश्चिमी मप्र के लिए एक वरदान है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बताया कि यह परियोजना 5 वर्ष से कम समय में फलीभूत होगी, जिसकी वर्तमान लागत लगभग 75,000 करोड़ रुपए है। प्रदेश के लगभग 1.5 करोड़ आबादी इस परियोजना से लाभान्वित होगी। इस अवसर पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि यह मप्र और राजस्थान के पानी की कमी वाले 26 जिलों के लिए स्वर्णिम सूर्योदय का दिन है। परियोजना से लगभग 5.60 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई के साथ ही बांधों और बड़े तालाबों में पानी का संचय कर जल-स्तर उठाने में सफलता मिलेगी।

सांस्कृतिक वन का निर्माण

मोहन यादव सरकार ने सत्ता में आते ही बड़ी आध्यात्मिक परियोजना श्रीराम वन गमन पथ पर ध्यान केंद्रित किया है। सरकार का फोकस इस बात पर है कि चित्रकूट का आध्यात्मिक विकास अयोध्या की ही तरह किया जाए। गौरतलब है कि भगवान राम वनवास के दौरान सबसे अधिक समय चित्रकूट में ही रहे थे। इसलिए चित्रकूट को आध्यात्म और पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाएगा। इसी क्रम में भगवान राम की तपोस्थली चित्रकूट में वन गमन पथ मार्ग पर राम वन वाटिका तैयार की जा रही है। अयोध्या व प्रयागराज के बाद चित्रकूट में यह वाटिका आकार ले रही है। मझगवां ब्लॉक के अनसुइया वन खंड में 8 हेक्टेयर क्षेत्र में करीब 11 करोड़ से इसका निर्माण किया जा रहा है। यहां वाल्मीकि रामायण में वर्णित उत्तराखंड की संजीवनी बूटी से लेकर श्रीलंका में पाई जाने वाली नागकेशर सहित 149 वनस्पतियों को संरक्षित किया जाएगा। डीएफओ सतना विपिन पटेल का कहना है कि चित्रकूट वनपरिक्षेत्र में श्रीराम वन का निर्माण किया जा रहा है। आठ हेक्टेयर में बन रहे इस वन में श्रीराम के 11 साल के वनवास का वर्णन किया जाएगा। इसी साल दिसंबर में आम जनों के लिए खोल दिया जाएगा। सांस्कृतिक वन का निर्माण करीब 11 करोड़ की लागत से किया जा रहा है।

सड़कें प्रदेश के विकास का द्वार

सड़कें प्रदेश के विकास का द्वार हैं। जिन क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण होता है, वहां आवासीय और औद्योगिक विकास होता है। अगले 10 वर्ष में विकास की गति को देखते हुए शहरों का चयन करें और भविष्य में विकास की संभावनाओं वाले क्षेत्रों की पहचान कर सड़क निर्माण की योजना बनाएं। गत दिनों मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव मंत्रालय में लोक निर्माण विभाग की समीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने निर्देश दिए कि सड़क निर्माण कार्य उच्चतम गुणवत्ता का करें। समय पर कार्य पूरा हो इसका विशेष ध्यान रखें। निर्माण करने के लिए सड़कों और भवनों के मेंटेनेंस का भी ध्यान रखें। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने निर्देश दिए कि क्वालिटी कार्य करने वाली अच्छी एजेंसियों को कार्य दें। क्वालिटी कंट्रोल और मॉनिटरिंग के लिए राज्यस्तरीय ऑनलाइन क्वालिटी स्टेटस डैशबोर्ड बनाएं। क्वालिटी लैब विकसित करने के साथ ही थर्ड पार्टी क्वालिटी ऑडिट कराएं। 50 लाख रुपए से अधिक की लागत वाले निर्माण कार्यों की मॉनिटरिंग के लिए मॉनिटरिंग सेल बनाएं। इसके साथ ही दूसरे देश और राज्यों की सड़क निर्माण की बेस्ट प्रैक्टिसेज का अध्ययन करें और प्रेरणा लें। अधोसंरचना के क्षेत्र में कार्य करने वाली बड़ी संस्थाओं से भी चर्चा करें। इससे निर्माण कार्य की गुणवत्ता बढ़ेगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने निर्देश दिए कि एनएचआई जैसे निर्माण संस्थाओं से प्रेरणा लेकर रेवेन्यू जेनरेशन मॉडल पर कार्य करने की योजना बनाएं, जिससे निर्माण कार्य की लागत निकलने के साथ ही शासन को अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति होगी। इसी तरह समग्र विकास की परिकल्पना पर कार्य करते हुए सड़क निर्माण, भवन निर्माण और पुल निर्माण आदि गतिविधियों में प्राधिकरण, नगरीय निकाय, पर्यटन विभाग, संस्कृति विभाग आदि को योजना में शामिल करें। उनसे आवश्यक सुझाव लें और योजना बनाएं।

वनस्पतियों के साथ ही रामायण की विस्तृत जानकारी

दरअसल, राम वन पथ गमन मार्ग पर प्रदेश सरकार भगवान श्रीराम का रामायण कालीन राम वन वाटिका का निर्माण कर रही है। यह वाटिका तीन स्थानों अयोध्या, प्रयागराज और चित्रकूट में बनाने की जिम्मेदारी वन विभाग को दी गई है। यहां पर रामायण कालीन विभिन्न प्रजातियों के पौधे व औषधियां रोपित की जा रही हैं। वाटिका में इस कालखंड की वनस्पतियों के साथ ही रामायण की विस्तृत जानकारी मिलेगी। इसके लिए पूरी वाटिका में बोर्ड लगाए जाएंगे। जिनमें चित्र के साथ वनस्पतियों और श्रीराम की यात्रा का वर्णन किया जाएगा। किस वन में श्रीराम किस समय रहे और कौनसी वनस्पति उक्त वनों में पाई जाती है। यह भी बताया जाएगा। इस सांस्कृतिक वन में राम के वनवास से जुड़ी सभी स्मृतियों को पर्यावरण के जरिए वन विभाग सहेजना का प्रयास कर रहा है। राम वन में औषधि पौधों से आदि मानव बनाया गया है। भारी भरकम बनाए गए आदि मानव के माध्यम से शरीर के प्रत्येक हिस्से में होने वाले रोगों के इलाज के लिए काम आने वाली औषधि लगाई गई है। जैसे कान, गला, नाक, हृदय, पेट सहित अन्य बीमारियों में काम आने वाली औषधि लगाई गई है। आरोग्य वाटिका, नवग्रह वन, नक्षत्र वाटिका और अशोक वाटिका, सीता रसोई, फायकस वन जहां बाहर से लाए हुए पौधे लगाए जाएंगे। सरयू नदी, कामदगिरी का पहाड़ का निर्माण अंतिम चरण में है। श्रीलंका और भारत के नक्शे का निर्माण भी किया जा रहा है। इन्हें पौधों के माध्यम से दिखाया जाएगा। वर्तमान में पौधे छोटे हैं। वन विभाग के अफसरों का कहना है कि आठ-दस महीने में पौधे बड़े हो जाएंगे। इनकी कटाई के बाद यहां भारत का नक्शा साफ नजर आएगा।

400 करोड़ से निखारा जाएगा चित्रकूट का वैभव

भगवान श्रीराम की तपोभूमि चित्रकूट का 400 करोड़ रुपए से वैभव लौटेगा। इसके लिए सरकार एशियन डेवलपमेंट बैंक से कर्ज लेगी। विगत दिनों श्रीरामचंद्र न्यास की पहली बैठक में चित्रकूट में विकास कार्यों के लिए बजट की उपलब्धता सुनिश्चित करने पुराने प्रस्ताव को रिवाइज कर एशियन डेवलपमेंट बैंक को प्रस्तुत कर फॉलोअप लेने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं। तय किया गया कि हर तीन माह में न्यास की बैठक की जाएगी। मुख्यमंत्री द्वारा चित्रकूट के समग्र विकास को प्राथमिकता में लेने के निर्देश के बाद निधि की व्यवस्था को लेकर आयुक्त नगरीय प्रशासन ने बताया कि इंटीग्रेटेड अर्बन डेवलपमेंट प्लान (आईयूडीपी) के तहत पूर्व में चार नगरों को नामांकित किया गया था। इसमें से एक चित्रकूट भी था। योजना के तहत 500 करोड़ रुपए खर्च कर नगरों का समग्र विकास किया जाना था, लेकिन पहले फेज में दो नगरों बुधनी और खुरई का चयन किया गया। इसमें चित्रकूट नहीं था। इसके लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक से राशि भी मिल गई थी। उसमें से अभी 100 करोड़ रुपए के लगभग राशि शेष बची है। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि चित्रकूट प्रमुख धार्मिक महत्व का स्थल है। ऐसे में पुराने प्रपोजल को रिवाइज किया जाए। चित्रकूट का प्रस्ताव तैयार कर एशियन बैंक से राशि मांगी जाए और इसके लिए फॉलोअप करें। पुरानी शेष राशि और नई राशि को मिलाकर जो लगभग 400 करोड़ रुपए होगी, उससे चित्रकूट का समग्र विकास किया जाए। विकास किस प्रकार से करना है उसके लिए सभी संबंधित विभाग अपने-अपने प्रस्ताव तैयार करें। चित्रकूट को इस तरह से तैयार किया जाना है, जिससे यह भगवान श्रीराम के जीवन से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल बन सके और धार्मिक चेतना, आध्यात्मिक विकास और राम कथा से जुड़े आयामों के केंद्र के रूप में पहचाना जाए।

वाटिका में मिलेंगी कई जानकारियां

पिछले 9 महीने से राम वन वाटिका बनाने की जिम्मेदारी वन विभाग को दी गई है। यहां पर रामायण कालीन विभिन्न प्रजातियों के पौधे व औषधियां रोपित की जा रही हैं। वाटिका में इस कालखंड की वनस्पतियों के साथ ही रामायण की विस्तृत जानकारी मिलेगी। इसके लिए पूरी वाटिका में बोर्ड लगाए जाएंगे। जिनमें चित्र के साथ वनस्पतियों और श्रीराम की यात्रा का वर्णन

किया जाएगा। किस वन में श्रीराम किस समय रहे और कौन सी वनस्पति उक्त वनों में पाई जाती है। यह भी बताया जाएगा। राम वन में सरयू नदी, सीता रसोई, आदि मानव, भारत का नक्शा, कामदगिरि की पहाड़ी और श्रीलंका का निर्माण किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट को चार साल में पूरा करना है, लेकिन विभाग प्रयास कर रहा है कि इसे आगामी दिसंबर में जनता के लिए खोल दिया जाए। इसे लेकर तेजी से काम किया जा रहा है।

700 करोड़ से शिप्रा को संवारेंगे

2028 में उज्जैन में होने वाले सिंहस्थ से पहले शिप्रा नदी के संरक्षण और स्वच्छता के लिए 17 घाटों के पुनरुद्धार के साथ आकर्षक रिवर फ्रंट की योजना बन चुकी है। वहीं उज्जैन और इंदौर का दूषित जल शिप्रा में मिलने से रोकना, उज्जैन में ग्राउंड वाटर रिचार्ज सुधारना और सप्त सरोवरों को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने की योजना है। सिंहस्थ की तैयारियों के क्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शिप्रा के संरक्षण और संवर्धन सहित उज्जैन के विकास पर कई बैठकें ले चुके हैं। इसके बाद सरकार द्वारा लगभग 700 करोड़ रुपए बजट वाला एक्शन प्लान बनाया गया है। 2016 में हुए सिंहस्थ में जहां लगभग 7.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने शिप्रा में डुबकी लगाई थी, वहीं 2028 में ये संख्या दोगुनी होने की संभावना है। शिप्रा तट पर बने 17 घाटों को सुधारकर पर्यटकों के लिए आकर्षक रिवर फ्रंट बनाया जाएगा। घाटों को बेहतर कनेक्टिविटी से आपस में जोड़ा भी जाएगा। घाट पर ही गंदे पानी को साफ करने की सुविधाएं विकसित होंगी। करीब 22 किमी में फैले इन घाटों को ऐतिहासिक संरचना के हिसाब से पुनर्जीवित किया जाएगा। नहाने, दूषित जल, ठोस कचरे के प्रबंधन के साथ अनुष्ठान के लिए व्यवस्था होगी। नदी को दूषित करने वाले 11 शहरी, 20 ग्रामीण नाले डाइवर्ट होंगे। घाटों पर सेफ्टी चेन, लाइटिंग के साथ वेंडरों को भी व्यवस्थित किया जाएगा। 2028 के आयोजन को ध्यान में रखकर वर्तमान में बने प्लेटफॉर्मों का सुधार होगा, विक्रय क्षेत्र व्यवस्थित होगा। बैराज-छोटे डेम बनाकर शिप्रा में अतिरिक्त 170 मिलियन घमी जल इकट्ठा करेंगे। हाटपिपल्या और सांवेर सिंचाई परियोजनाओं से भी जल आएगा। शहर के 121 प्राचीन कुएं-बावड़ियों का सुधार होगा। नगर की 7 झीलों (सप्त सरोवर) को सुधारकर पर्यटक स्थल विकसित होंगे। ठोस कचरे को जल में मिलने से रोकने के लिए 230 टीपीडी का प्लांट और जैविक कचरे के लिए 50 टीपीडी का प्लांट लगेगा।

शिप्रा के मुख्य रामघाट से लेकर आमने-सामने के सभी घाट की बात करें तो यह ऊंचे-नीचे है, जिसके चलते एक जैसे प्लेटफॉर्म नहीं होने की वजह से पानी का लेवल भी कहीं कम तो कहीं अधिक है। बाहर से आने वाले श्रद्धालु इसी कारण गफलत के चलते नदी में डूबकर हादसे का शिकार होते हैं। शिप्रा नदी के घाटों पर 13.30 करोड़ की लागत से एक जैसे प्लेटफॉर्म और रेलिंग लगाई जाने का टेंडर तक जारी हो चुका है लेकिन 2 साल से काम ही नहीं हुआ जिसके चलते श्रद्धालुओं की मौत जारी है। शिप्रा नदी में इंदौर की कान्ह नदी का गंदा पानी अभी भी मिल रहा है, जिसके चलते हर बार स्नान पर नर्मदा का पानी लिया जाता है और प्रदूषित पानी बाहर आ जाता है। हर बार पानी लेने पर करोड़ों रुपए का खर्च हो रहा है। स्थायी हल आज तक नहीं निकाला गया।

राम वनपथ गमन मार्ग के सभी स्थलों का होगा विकास

चित्रकूट के ग्रामोदय विश्वविद्यालय सभागार में श्रीरामचंद्र पथ गमन न्यास की प्रथम बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि चित्रकूट सहित राम वन पथ गमन मार्ग के सभी प्रमुख स्थलों का विकास किया जाएगा। इसके लिए पूरी कार्य योजना बनाकर उसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। इसमें अधोसंरचना विकास के कार्यों के साथ-साथ धार्मिक चेतना, आध्यात्मिक विकास और राम कथा से जुड़े आयामों को भी शामिल किया जाएगा। चित्रकूट का अयोध्या की तरह विकास करके इसे भगवान राम के जीवन से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल बनाया जाएगा। विद्वानों के परामर्श से राम वन पथ गमन के प्रमुख स्थलों का विकास किया जाएगा। चित्रकूट के दीवाली मेले तथा अमावस्या मेले में रामकथा और राम के जीवन से जुड़ी प्रदर्शनी एवं राम वन पथ गमन से जुड़ी जानकारियां प्रदर्शित कराएं। इनका व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान कामतानाथ के परिक्रमा पथ का निर्माण कार्य शीघ्र शुरू कराएं। जिला पर्यटन संवर्धन परिषद को सक्रिय कर चित्रकूट में पर्यटन गतिविधियां संचालित कराएं। अमावस्या मेले को पर्यटन कैलेंडर में शामिल किया जाएगा। राम वन पथ गमन से जुड़े निर्माण कार्यों में लोक चेतना को शामिल करें। राम वन पथ गमन के प्रमुख स्थलों में सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। राम वन पथ गमन मार्ग में मोटर साइकिल रैली जैसे आयोजन करके इससे आमजनता को जोड़ें। बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रदेश के मंदिरों की पुस्तक का विमोचन किया। इसमें 155 प्रमुख मंदिरों के छायाचित्र तथा 6800 राम मंदिरों की जानकारी संकलित है।

6 लेन बनेगा इंदौर-उज्जैन हाईवे

वर्ष 2028 में उज्जैन में होने वाले सिंहस्थ की तैयारी में प्रदेश की मोहन यादव सरकार जुट गई है। महाकाल लोक बनने के बाद जिस तरह से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं उज्जैन पहुंच रहे हैं, उसे ध्यान में रखते हुए विभागों ने तैयारियां प्रारंभ कर दी गई हैं। इसी कड़ी में लोक निर्माण विभाग इंदौर-उज्जैन हाईवे को 6 लेन मार्ग बनाएगा। यह इंदौर के अरबिंदो मेडिकल कॉलेज गेट से उज्जैन के हरिफाटक चौराहे तक 45.47 किमी रहेगा। इसमें एक फ्लाईओवर उज्जैन शहर में बनाया जाएगा। सिंहस्थ की तैयारियों के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बैठक करके सभी विभागों को अभी से तैयारी करने के निर्देश दिए थे। गौरतलब है कि महाकाल लोक बनने के बाद जिस तरह से उज्जैन आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी है, उसे देखते हुए लोक निर्माण विभाग ने स्टेट हाईवे 59 इंदौर-उज्जैन को 6 लेन करने का प्रस्ताव तैयार किया है। इसमें दो बड़े पुल बनाए जाएंगे। सर्विस रोड रहेगा और उज्जैन शहर में फ्लाइओवर भी बनाया जाएगा। प्रारंभिक आंकलन के अनुसार इस कार्य में 894 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसमें 40 प्रतिशत राशि राज्य सरकार लगाएगी और शेष राशि निर्माण एजेंसी द्वारा व्यय की जाएगी। निर्माण एजेंसी को लागत की राशि एक निश्चित अवधि में सरकार किश्तों के रूप में लौटाएगी। टोल टैक्स की वसूली सड़क विकास निगम करेगा। विभाग के अधिकारियों का कहना है कि सैद्धांतिक सहमति के बाद अब प्रस्ताव प्रशासकीय और वित्तीय स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। इसके बाद बजट प्रविधान करके निविदा आमंत्रित की जाएगी।

इंडस्ट्रियल हब बनेगा मप्र

मप्र को इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर हब बनाने की तैयारी मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की है। गत दिनों केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में 499 किलोमीटर लंबाई की 15 राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इनकी लागत 8038 करोड़ रुपए है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मप्र में सड़क परियोजनाओं से प्रदेश को इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर हब बनाने में मदद मिलेगी। मप्र में सड़क नेटवर्क बेहतर बनाने के लिए नए कार्य प्रारंभ किए जा रहे हैं। इस वर्ष के अंत तक अनेक कार्य पूर्ण होंगे। मप्र में सड़कों के निर्माण से निवेश आएगा, निर्यात भी बढ़ेगा। रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे और निर्धनता को दूर करने में मदद मिलेगी। स्थानों की दूरियां भी कम होंगी। सड़कें विकास की संभावनाओं को साकार करती हैं।

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का कहना है कि मप्र की तस्वीर बदल रही है। पहले मप्र के लोग नागपुर से छिंदवाड़ा की तरफ जाते थे तो नींद लग जाती थी, जब गड्ढों के कारण नींद खुल जाती थी तो पता चलता था कि मप्र आ गया। इस स्थिति में आज सुधार हुआ हैं। 2024 के समाप्त होने तक मप्र का रोड नेटवर्क अमेरिका के समान होने जा रहा है। यह मैं यकीन दिला रहा हूं। उज्जैन में रेलवे स्टेशन से बाबा महाकाल मंदिर तक रोप-वे के संचालन का प्रकल्प महत्वपूर्ण है। आगामी महीने में 171 करोड़ रुपए के इस प्रकल्प के लिए निविदा की कार्यवाही करने की तैयारी है। उज्जैन से कोटा की दूरी सिर्फ ढाई घंटे में पूरी की जा सकेगी।

महत्वपूर्ण कार्यों में उज्जैन से गरोठ 136 किलोमीटर की फोर लेन भी शामिल है। इंदौर से ओंकारेश्वर की दूरी एक घंटे में तय हो जाएगी। वर्ष 2025 तक अनेक कार्य पूरे होंगे। जिसमें इंदौर-हैदराबाद कॉरिडोर भी शामिल है। कई ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे भी बन रहे हैं। मप्र के 27 सड़क निर्माण प्रस्तावों को शीघ्र स्वीकृति दी जा रही है। भोपाल झीलों का शहर है। झील पर रोप-वे और केबल कार के मप्र सरकार के प्रस्तावों को शीघ्र स्वीकृति दी जाएगी। मप्र के सभी एक्सप्रेसवे कंप्लीट करके देंगे, जिसके बाद प्रदेश के औद्योगिक विकास की गति बढ़ेगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जो नए रिंगरोड बन रहे हैं और उसके पास की जमीन हमें मिलेगी तो हम अपने खर्च पर वहां क्लस्टर डेवलप करेंगे। उन्होंने कहा कि इसको लेकर मुख्यमंत्री से प्रस्ताव भी मांगे है। मालवा का आटा, पास्ता की अरब देशों में बहुत मांग है। उन्होंने कहा कि मप्र में 27 रोपवे बनाने के प्रस्ताव पर काम कर रहे हैं। खजुराहो, ओंकारेंश्वर, सागर समेत कई जगहों पर रोपवे की स्टडी कर रहे हैं।

चंबल संभाग में बढ़ेंगे रोजगार के अवसर

50 हजार करोड़ के ग्रीन एक्सप्रेसवे का काम चालू है। इसके पूरे होने पर 12 घंटे में मुंबई से दिल्ली सड़क मार्ग से पहुंच सकेंगे। इस साल अंत तक इस मार्ग का काम पूरा कर लेंगे। 6 घंटे में मप्र से मुंबई का सफर पूरा होगा। ग्वालियर से दिल्ली चार घंटे में जा सकेंगे। गुड़गांव की पूरी इवेंस्टमेंट चंबल की तरफ आएगी। दिल्ली से काफी उद्योग आएंगे। इससे चंबल संभाग में लोगों को रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। 2024 के अंत तक 3 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट पूरे होंगे। अटल एक्सप्रेसवे को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के साथ एलाइनमेंट की थी, लेकिन पर्यावरण स्वीकृति के साथ अड़चने आई थी। अभी भोपाल से कानपुर आने में 15 घंटे लगते हैं। नए हाईवे के बाद सिर्फ 7 घंटे में आ पाएंगे। सागर से कानपुर का नया कॉरिडोर 8 हजार करोड़ का बन रहा है। सभी हाईवे के द्वारा लॉजिस्टिक, इंडस्ट्री हब बनेगा और विकास होगा।

प्रत्येक परिवार को रोजगार देने का फॉर्मूला, मोहन सरकार एक्शन मोड़ में

मप्र के नए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भाजपा के संकल्प पत्र को लेकर सजग नजर आ रहे हैं। दरअसल, पहली ही कैबिनेट की बैठक में कई ऐतिहासिक निर्णय लेकर मुख्यमंत्री ने अफसरों को काम में जुटा दिया है। बैठक में अफसरों को मिशन मोड पर काम करने के निर्देश मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव दे चुके हैं। अब भाजपा के संकल्प पत्र पर अफसरों ने काम करना भी शुरू कर दिया है। प्रत्येक परिवार में कम से कम एक रोजगार अथवा स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने और गरीब परिवारों के छात्रों को 12वीं तक मुफ्त शिक्षा देने के संकल्पों पर अफसरों ने काम करना शुरू कर दिया है। बता दें कि भाजपा के संकल्प पत्र के 10 प्रमुख भाग हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने धार्मिक स्थलों पर तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाने को लेकर प्रतिबंध के आदेश जारी किए हैं। इसके साथ ही खुले में मांस बिक्री पर भी मोहन सरकार ने रोक लगा दी है। इसके अलावा रजिस्ट्री के साथ नामांतरण किए जाने, हर जिले में एक्सीलेंस कॉलेज बनाने, विद्यार्थियों की अंक सूची रखना, डीजी लॉकर का निर्माण करने, आदतन अपराधियों की जमानत रद्द करने, तेंदूपत्ता संग्रहण पर राशि बढ़ाए जाने के निर्णय भी मोहन यादव ले चुके हैं। अब भाजपा के संकल्प पत्र में युवाओं को उत्तम शिक्षा देकर सक्षम युवा तैयार करने के संकल्प पर विभागों ने काम शुरू कर दिया है। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का सफल क्रियान्वन करते हुए प्रदेश के हर परिवार में कम से कम एक को रोजगार अथवा स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए कवायद शुरू हो गई है। तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग इस पर अन्य विभागों के समन्वय से काम करेगा। मप्र में जो गरीब परिवारों के बच्चे हैं उन्हें कक्षा 1 से 12वीं तक मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। हर साल 1200 रुपए की वार्षिक सहायता स्कूल बैग, किताबें और यूनिफॉर्म के लिए दिए जाएंगे। इस पर स्कूल शिक्षा विभाग ने काम शुरू कर दिया है।

75वें
गणतंत्र दिवस
की शुभकामनाओं सहित...
सचिव भार साधक अधिकारी
कृषि उपज मंडी समिति, नरसिंहगढ़, जिला - राजगढ़

75वें
गणतंत्र दिवस
की शुभकामनाओं सहित...
सचिव ● भार साधक अधिकारी
कृषि उपज मंडी समिति, खिलचीपुर, जिला - राजगढ़

26 जनवरी
75वें
गणतंत्र दिवस
की शुभकामनाओं सहित...
सचिव ● भार साधक अधिकारी
कृषि उपज मंडी समिति, बेगमगंज, जिला - रायसेन

26 जनवरी
75वें
गणतंत्र दिवस
की शुभकामनाओं सहित...
सचिव ● भार साधक अधिकारी
कृषि उपज मंडी समिति, बरेली, जिला - रायसेन

75वें
गणतंत्र दिवस
26 जनवरी
की शुभकामनाओं सहित...
सचिव ● भार साधक अधिकारी
कृषि उपज मंडी समिति, रायसेन

75वें
गणतंत्र दिवस
की शुभकामनाओं सहित...
सचिव ● भार साधक अधिकारी
कृषि उपज मंडी समिति, औबेदुल्लागंज, जिला - रायसेन

75वें
गणतंत्र दिवस
26 जनवरी
की शुभकामनाओं सहित...
सचिव ● भार साधक अधिकारी
कृषि उपज मंडी समिति, उदयपुरा, जिला - रायसेन

75वें
गणतंत्र दिवस
की शुभकामनाओं सहित...
सचिव भार साधक अधिकारी
कृषि उपज मंडी समिति, खिरकिया, जिला - हरदा

75वें
गणतंत्र दिवस
की शुभकामनाओं सहित...
26 जनवरी
सचिव ● भार साधक अधिकारी
कृषि उपज मंडी समिति, बनखेड़ी, जिला - नर्मदापुरम

कार्यालय, कृषि उपज मण्डी समिति, इन्दौर, जिला इन्दौर

लक्ष्मीबाई नगर, इन्दौर, दूरभाष क्रमांक 0731-2411223, 2412902

Fax No.:-0731-2412040 & E-mail ID :- apmcindore@gmail.com

-: कृषकों से अपील :-

1. किसान भाई अपनी विक्रित कृषि उपज का भुगतान उसी दिन प्राप्त करें, यदि भुगतान प्राप्त नहीं होता है, तो उसकी लिखित सूचना अगले दिन तक मण्डी कार्यालय में अवश्य देवें अन्यथा यह मान लिया जावेगा कि संबंधित कृषक को भुगतान प्राप्त हो गया है तथा इसके बाद की जाने वाली शिकायत को आपसी लेन-देन माना जावेगा।
2. किसान भाई शासन के नियमानुसार राशि रू. 2 लाख रूपये तक का नगद भुगतान प्राप्त करें तथा शेष राशि RTGS/NEFT से प्राप्त कर सकते हैं। तथा चेक के माध्यम से भुगतान प्राप्त न करें।
3. धोखाधड़ी से बचने हेतु किसान भाई अपनी कृषि उपज को मण्डी प्रांगण में अनुज्ञप्तिधारी व्यापारी को ही खुली नीलाम अथवा सौदा पत्रक एप के माध्यम से ही विक्रय करें तथा मण्डी प्रांगण के बाहर किसी भी स्थिति में सीधे विक्रय न करें।
4. किसान भाई मण्डी प्रांगण में कृषक भोजन, कृषक विपणन पुरस्कार, विश्राम गृह तथा शासन की अन्य सुविधाओं का लाभ उठायें।
5. किसान भाई अपने एंड्राइड मोबाईल में गूगल प्लेस्टोर से ई-मण्डी एप इंस्टाल करें।
6. कृषक भाई इस एप में कृषक पंजीयन की कार्यवाही पूर्ण करें। इस हेतु अपना न्यूनतम आवश्यक विवरण स्वयं भरें।
7. किसान लॉगिन में जाकर मण्डी इन्दौर का चयन कर अपनी फसल विवरण दर्ज कर प्रवेश पर्ची स्वयं अपने मोबाईल में ही प्राप्त करें।

सचिव
मण्डी, इन्दौर

अपर कलेक्टर/भारसाधक अधिकारी
मण्डी इन्दौर

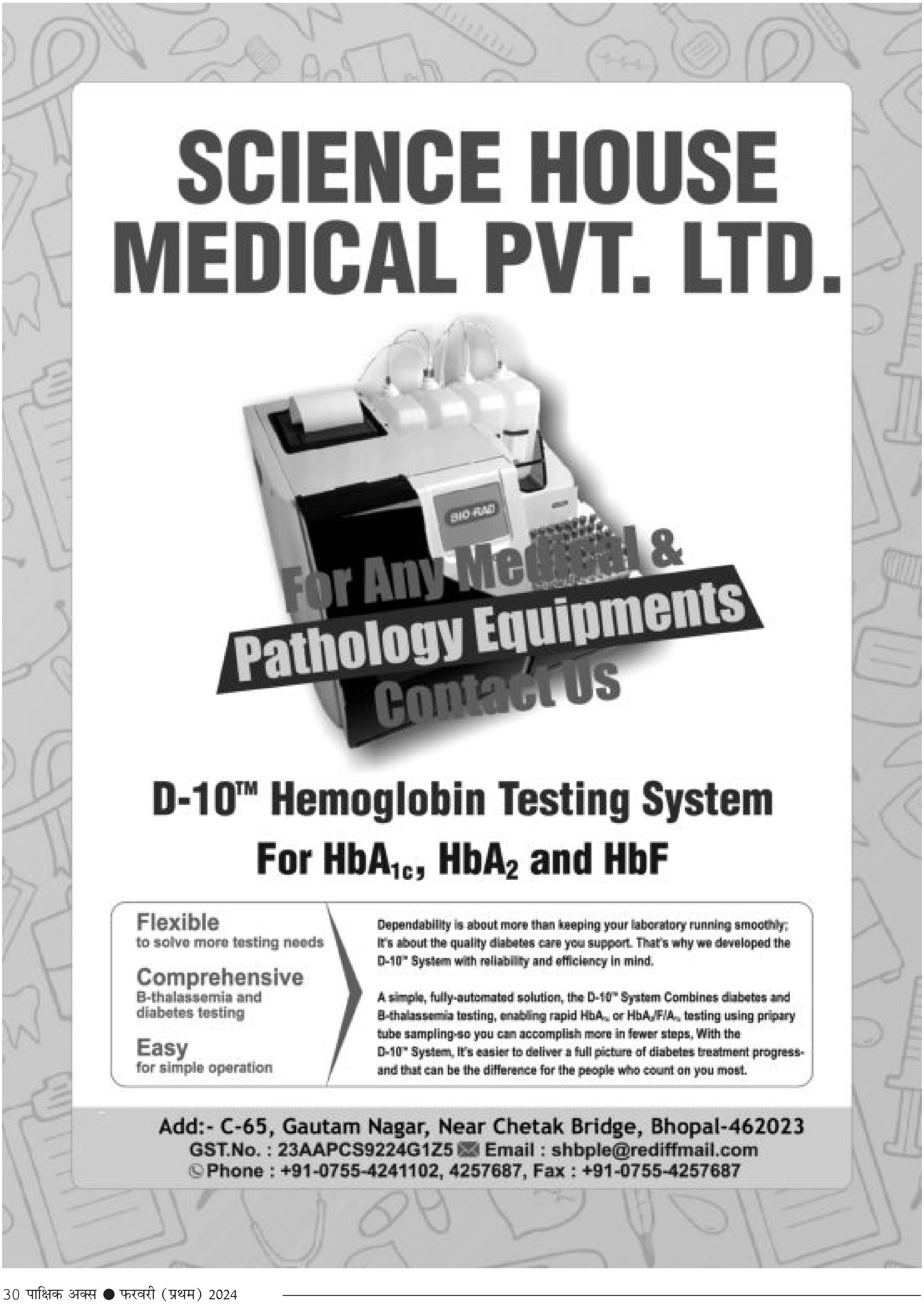
SCIENCE HOUSE MEDICAL PVT. LTD.
For Any Medical &
Pathology Equipments
Contact Us
D-10™ Hemoglobin Testing System
For HbA_{1c}, HbA_2 and HbF
Flexible
to solve more testing needs
Comprehensive
B-thalassemia and diabetes testing
Easy
for simple operation
Dependability is about more than keeping your laboratory running smoothly; It's about the quality diabetes care you support. That's why we developed the D-10™ System with reliability and efficiency in mind.
A simple, fully-automated solution, the D-10™ System Combines diabetes and B-thalassemia testing, enabling rapid HbA1c or HbA2/F/A1c testing using pripary tube sampling-so you can accomplish more in fewer steps, With the D-10™ System, It's easier to deliver a full picture of diabetes treatment progress-and that can be the difference for the people who count on you most.
Add:- C-65, Gautam Nagar, Near Chetak Bridge, Bhopal-462023
GST.No. : 23AAPCS9224G1Z5 Email : shbple@rediffmail.com
Phone : +91-0755-4241102, 4257687, Fax : +91-0755-4257687

राज्यसभा में रहे मंत्रियों पर भाजपा लगाएगी दांव

लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी भाजपा 2024 के लोकसभा चुनाव में मप्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में अपनाए गए मॉडल को लागू करेगी। यानी जिस तरह विधानसभा चुनाव में लोकसभा सांसदों को मैदान में उतार दिया था, उसी तर्ज पर कई बड़े नेताओं और मंत्रियों को जो राज्यसभा से सांसद हैं, उनको लोकसभा चुनाव लड़वाया जाएगा। दरअसल 2019 के लोकसभा चुनाव में भी भाजपा ने यह प्रयोग समिति स्तर पर किया था। इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में व्यापक स्तर पर इसका प्रयोग करना चाहती है। भाजपा को लग रहा है कि मोदी की लोकप्रियता अपने चरम पर है और संगठन भी जमीनी स्तर पर मजबूत है, ऐसे में मोदी सरकार के मंत्री जो राज्यसभा से हैं, उनको लोकसभा चुनाव में उतारकर जीत हासिल की जा सकती है। मोदी और शाह भी चाहते हैं कि केंद्रीय मंत्रियों की पहचान अब बन चुकी है, ऐसे में उनको लोकसभा चुनाव लड़ने का साहस करना चाहिए, इससे उनकी खाली सीटों पर किसी अन्य को राज्यसभा भेजा जा सकेगा।

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा खुद राज्यसभा से हैं। ऐसे में उनके सामने भी चुनाव लड़ने की चुनौती होगी। हालांकि खुद जेपी नड्डा इस बात से इनकार कर रहे हैं लेकिन समझा जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी नड्डा से हिमाचल की किसी सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए कह सकते हैं। अगर भाजपा के अध्यक्ष लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं तो पार्टी के अन्य राज्यसभा सांसदों को भी चुनाव लड़ने का नैतिक आधार बनेगा। फिलहाल मोदी सरकार में 18 मंत्री राज्यसभा से हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री और राज्यसभा सांसद धर्मेंद्र प्रधान ने लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। धर्मेंद्र प्रधान 2004 में उड़ीसा की देवगढ़ सीट से लोकसभा सांसद रह चुके हैं। इस सीट का परिसीमन होने के बाद इसे दो सीटों ढ़ेकानाल और संबलपुर में बांट दिया गया। इन दोनों सीटों में से किसी एक सीट से धर्मेंद्र प्रधान लोकसभा के उम्मीदवार हो सकते हैं। मोदी और शाह के गृह राज्य गुजरात से भी मोदी के दो केंद्रीय मंत्रियों के लोकसभा चुनाव लड़ने की संभावना है। केंद्रीय स्वास्थ्य और उर्वरक मंत्री मनसुख मंडाविया को सौराष्ट्र से आने वाली राजकोट से लोकसभा चुनाव लड़ाया जा सकता है। सौराष्ट्र के अलावा मनसुख भाई मंडाविया के गृह क्षेत्र की सीट भावनगर से भी उम्मीदवार बनाने की चर्चा है। केंद्रीय पशुपालन मंत्री पुरूषोत्तम रूपाला को गुजरात की अमरेली से भाजपा उम्मीदवार बना सकती है। राजस्थान से भी राज्यसभा से आने वाले दो केंद्रीय मंत्रियों को भाजपा चुनाव मैदान में उतार सकती है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ओडिसा कैडर के आईएएस अधिकारी रहे हैं और राज्यसभा में भी उड़ीसा से ही हैं, लेकिन उनका गृह राज्य राजस्थान है। अश्विनी वैष्णव जयपुर से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन यह भी हो सकता है कि भाजपा हाईकमान अश्विनी वैष्णव को उड़ीसा की ही किसी सीट से मैदान में उतार दे। राजस्थान से राज्यसभा सांसद और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को भी राजस्थान की अलवर सीट से लड़ाया जा सकता है। अलवर सीट से सांसद बाबा बालकनाथ विधायक बन चुके है। ऐसे में भूपेंद्र यादव के अलवर सीट से लड़ने की प्रबल संभावना है। भूपेंद्र यादव दिल्ली से सटी सीट गुरूग्राम से भी लड़ सकते हैं।

मोदी कैबिनेट में वित्त मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रही निर्मला सीतारमन को तमिलनाडु की मदुरै सीट से उतारा जा सकता है। खबर है कि निर्मला सीतारमन को उनकी पंसदीदा सीट बताने के लिए कहा गया है। तमिलनाडु से मोदी सरकार के विदेश मंत्री एस जयशंकर को भी पार्टी चुनाव लड़वा सकती है। जयशंकर के माता-पिता जरूर तमिलनाडु से हैं लेकिन उनका जन्म दिल्ली में और पढ़ाई भी दिल्ली में हुई है। उल्लेखनीय है कि 2023 में मोदी सरकार के नौ साल पूरे होने पर भाजपा ने जो महाजनसंपर्क अभियान चलाया, उसमें जयशंकर को दिल्ली की चार लोकसभा सीटों की जिम्मेदारी दी गई थी। ऐसे में संभावना है कि पार्टी विदेश मंत्री जयशंकर को दिल्ली की किसी सीट से मैदान में उतारे। संभावना है कि मीनाक्षी लेखी की सीट से भी जयशंकर को टिकट दिया जा सकता है।

मोदी सरकार के एक और मंत्री पीयूष गोयल के भी लोकसभा चुनाव लड़ने की पूरी संभावना है। 2010 से पीयूष गोयल लगातार राज्यसभा सांसद और 2014 से लगातार मोदी सरकार में मंत्री है। पीयूष गोयल को पुणे लोकसभा सीट से उतारा जा सकता है। पिछले पांच लोकसभा चुनाव की बात करें तो तीन चुनाव में भाजपा यहां से जीत रही है। भाजपा ऐसे राज्यसभा सांसदों को भी लोकसभा चुनाव लड़ा सकती है जो मंत्री नहीं है लेकिन लोकसभा चुनाव लड़ने को उत्सुक है।

● रजनीकांत पारे

अपनी पसंद की सीट खोजने का निर्देश

दरअसल, प्रधानमंत्री मोदी ने पार्टी के भीतर एक व्यवस्था बनाने का निर्देश दिया था, जिसके अंतर्गत लगातार दो बार राज्यसभा सांसद रहे नेताओं को तीसरी बार राज्यसभा नहीं भेजा जाए। मोदी ने कहा था कि कोई सांसद यह कहता है कि वह लगातार तीन बार से राज्यसभा का सासंद है तो इसका मतलब है कि पार्टी अन्य विकल्पों पर विचार नहीं कर रही है। मोदी का मानना है कि एक ही व्यक्ति को दो बार से अधिक राज्यसभा में भेजना यह दर्शाता है कि पार्टी की उस पर अत्याधिक निर्भरता है और वह व्यक्ति निर्भरता का पूरा लाभ ले रहा है। मोदी ने साफ कहा था कि पार्टी में ऐसी अपरिहार्य स्थिति किसी भी नेता को लेकर नहीं बननी चाहिए। पार्टी की इसी लाईन को अमित शाह ने आगे बढ़ाते हुए राज्यसभा से सांसद और मोदी सरकार में मंत्रियों से दो टूक कह दिया है कि चुनाव लड़ने की तैयारी रखें और अपनी पंसद की सीट से पार्टी नेतृत्व को अवगत करा दे। अगर आपके पास सीट का विकल्प नहीं है तो पार्टी आपके लिए उचित सीट उपलब्ध करा देगी। मोदी ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक में साफ कहा था कि कोई लोकसभा सीट न होना और जीतने की गारंटी न होना बार-बार राज्यसभा भेजने का आधार नहीं हो सकता है। दरअसल मोदी का मानना है कि एक नेता के रूप में आप संगठन में बड़े पद पर रहें, किसी राज्य के चुनाव प्रभारी रहते प्रदेश के नेताओं को चुनाव जीतने की रणनीति भी बताएं, केंद्र में मंत्री भी रहें लेकिन चुनाव लड़ने से तौबा करें और राज्यसभा सांसद बनकर मंत्री पद को सुभोशित करें, यह स्वीकार्य नहीं है।

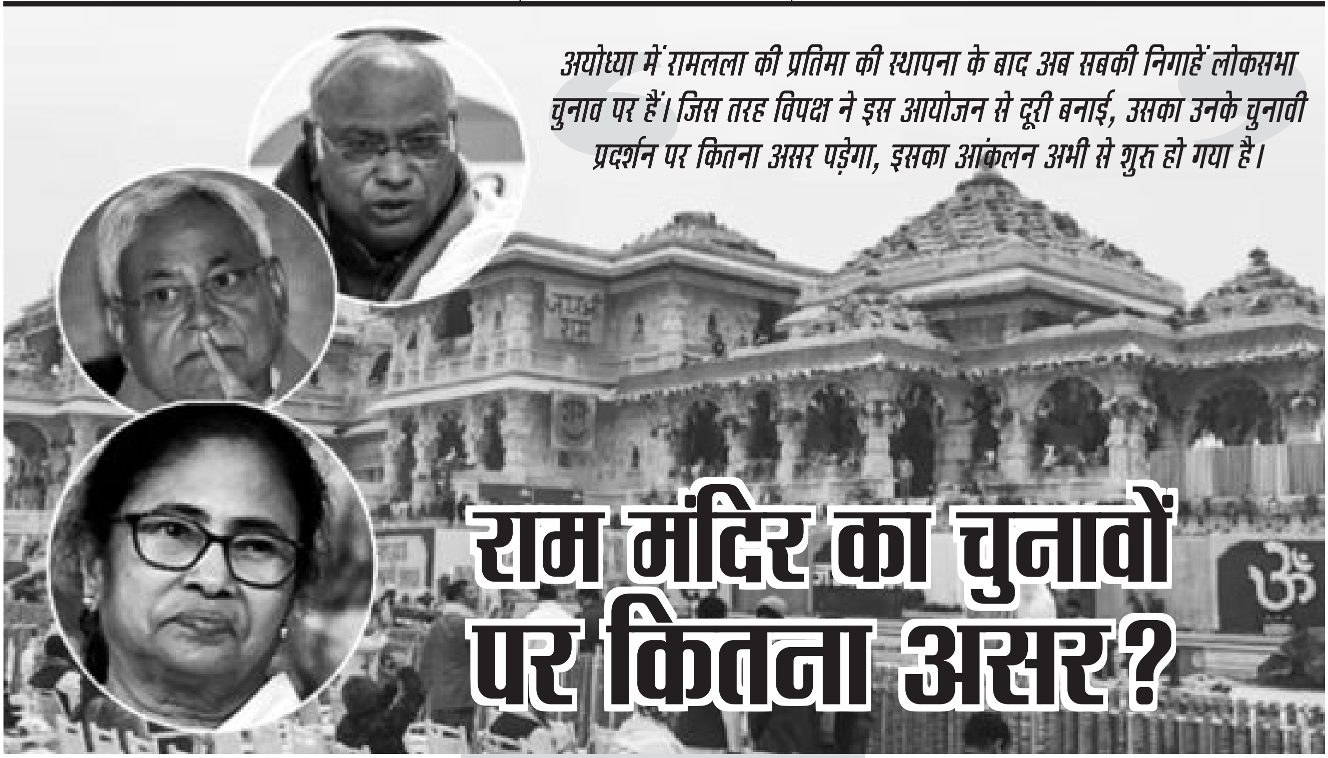

अयोध्या में रामलला की प्रतिमा की स्थापना के बाद अब सबकी निगाहें लोकसभा चुनाव पर हैं। जिस तरह विपक्ष ने इस आयोजन से दूरी बनाई, उसका उनके चुनावी प्रदर्शन पर कितना असर पड़ेगा, इसका आंकलन अभी से शुरू हो गया है।

राम मंदिर का चुनावों पर कितना असर?

श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा के बाद की राजनीति कैसी होगी, उसकी झलक दो घटनाओं से मिलती है। कांग्रेस के नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने अयोध्या पहुंचकर कहा कि भले ही जन्मभूमि मंदिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बना है, लेकिन अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते तो फैसला भी नहीं आता और मंदिर भी नहीं बन पाता। यही वह बात है, जो देश का हर हिंदू मानता है, और यही वह बात है, जिसे आचार्य प्रमोद की कांग्रेस पार्टी नकारती है। इसी तरह जेडीयू के प्रवक्ता डॉ. सुनील कुमार सिंह ने इस बात से नाराज होकर पार्टी छोड़ दी कि न्यौता मिलने के बाद भी नीतीश कुमार रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए। विपक्षी दल ऐसा समझते हैं कि श्रीराम जन्मभूमि मंदिर चुनावी मुद्दा नहीं बनेगा। इसलिए कांग्रेस, वामपंथी दलों और राष्ट्रीय जनता दल ने मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को संघ और भाजपा का कार्यक्रम बताकर उसका बायकाट कर दिया। बायकाट उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, शरद पवार और नीतीश कुमार ने भी किया, लेकिन चारों ने बायकाट का ऐलान नहीं किया। बल्कि इन सभी ने कहा कि वे प्राण प्रतिष्ठा के बाद सपरिवार दर्शन करने जाएंगे।

ममता बनर्जी ने अलग रास्ता अपनाया, उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को राजनीतिक बताकर बंगाल के मंदिरों में भ्रमण का कार्यक्रम बना लिया। वह अच्छी तरह जानती हैं कि बंगाल में हिंदुत्व अपने उभार पर है, और इसी हिंदुत्व के उभार के कारण भाजपा 2019 में लोकसभा की 18 सीटें जीत गई थी। इसलिए ममता बनर्जी ने हिंदू धर्म में अपनी श्रद्धा का प्रकटीकरण किया। वैसे कांग्रेस की तरह विपक्ष के अन्य सभी दल भी मानते हैं कि श्रीराम जन्मभूमि मंदिर निर्माण चुनावी मुद्दा नहीं बनेगा, लेकिन अधिकांश नेताओं ने विरोध का रिस्क नहीं लिया। उद्धव ठाकरे के सिपहसालार संजय राउत ने यह भ्रम फैलाने की कोशिश की, कि मंदिर वहां बना ही नहीं, जिसके लिए 500 साल संघर्ष हुआ था। जबकि सब जानते हैं कि मंदिर वहीं बना है। योगी आदित्यनाथ ने प्राण प्रतिष्ठा के बाद दिए भाषण में कहा– हमने कहा था मंदिर वहीं बनाएंगे और मंदिर वहीं बना है। विपक्षी दलों में सबसे बड़ी मुश्किल में कांग्रेस खड़ी हुई है। उसे अपनी गलती का एहसास है, उसने प्राण प्रतिष्ठा का न्यौता अस्वीकार करने का ऐलान तो कर दिया, लेकिन बाकी दलों के नेताओं की तरह यह नहीं कहा कि कांग्रेस के शीर्ष नेता प्राण प्रतिष्ठा के बाद किसी दिन श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के दर्शन करने जाएंगे। ऐसा कह दिया होता, तो राहुल गांधी की यात्रा को प्राण प्रतिष्ठा के खिलाफ कांग्रेस का कार्यक्रम नहीं माना जाता। धारणा यह बनी है कि प्राण प्रतिष्ठा का बायकाट करके वह अपनी न्याय यात्रा पर निकल गए। सारी कांग्रेस उनकी यात्रा को सफल बनाने में लग गई, कांग्रेस के भीतर धारणा यह बनी कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का बायकाट करना है।

कांग्रेस को अपनी गलती का एहसास राहुल गांधी की यात्रा शुरू होने के बाद हुआ। इसलिए 14 जनवरी को यह कार्यक्रम बनाया गया कि राहुल गांधी 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह के समय यात्रा मार्ग में पड़ने वाले श्रीमंत शंकरदेव की जन्मस्थली में दर्शन करने जाएंगे। श्रीमंत शंकरदेव पंद्रहवीं शताब्दी के समाज सुधारक वैष्णव मत के प्रचारक संत थे। राहुल गांधी के सलाहकार जयराम रमेश का कहना है कि उन्होंने यह प्रोग्राम इसलिए बनाया था, ताकि लोग यह न कहें कि राहुल गांधी नौगांव से गुजर रहे थे,

जातिगत जनगणना हुई बेअसर

जाति आधारित जनगणना करवाकर हिंदुओं को जातियों में बांटने का राहुल गांधी का अभियान तो चल ही रहा है, अब उन्होंने हिंदू समाज को मूर्ति पूजकों और मूर्तिपूजा विरोधियों में बांटना भी शुरू कर दिया है। राहुल गांधी का शंकरदेव की जन्मस्थली पर जाने का फैसला सही है, लेकिन समय उचित नहीं है। शंकरदेव की जन्मस्थली पर जाने के लिए उन्हें यह दिन नहीं चुनना चाहिए था। असम के मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता हिमंत बिस्व सरमा ने पहले ही राहुल गांधी से आग्रह किया था कि वह उस दिन असम के वैष्णव संत शंकरदेव के जन्मस्थान पर न जाएं। उनका कहना था कि राहुल गांधी भगवान श्रीराम और वैष्णव संप्रदाय के संत शंकरदेव में प्रतिस्पर्धा करवाने की कोशिश कर रहे हैं, जो उचित नहीं है। उनका कहना था कि श्रीराम जन्मभूमि में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हो जाने के बाद वह शंकरदेव के जन्मस्थान पर जाएं, तो ठीक रहेगा। किंतु राहुल गांधी ने किसी की एक न सुनी और धरने पर बैठ गए, जिसका खामियाजा आमजन को भुगतना पड़ा।

लेकिन असम में अत्याधिक सम्मानित वैष्णव मत के प्रवर्तक और समाज सुधारक शंकरदेव के जन्मस्थल पर नहीं गए। श्रीमंत शंकरदेव जन्मस्थल मंदिर की मैनेजिंग कमेटी ने 21 जनवरी को राहुल गांधी को सूचित कर दिया था कि श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के कारण सुबह वहां दस हजार से ज्यादा लोग जमा होंगे, इसलिए वह 3 बजे के बाद आएं। इस पर राहुल गांधी आग बबूला होकर धरने पर बैठ गए। राहुल गांधी और जयराम रमेश को इसमें भी असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा की साजिश नजर आने लगी। उन्होंने कहा कि हमें मंदिर से न्यौता मिला था, लेकिन पुलिस उन्हें जाने नहीं दे रही। जबकि यह बिलकुल गलत है, मंदिर ने उन्हें कोई न्यौता नहीं दिया था।

प्राण प्रतिष्ठा के बायकाट से हुए नुकसान की भरपाई के लिए वह ठीक उसी समय मंदिर में दर्शन करने जाना चाहते थे। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि आज शायद एक ही व्यक्ति को मंदिर जाने की इजाजत है। उनका इशारा रामजन्मभूमि मंदिर में उस समय प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे नरेंद्र मोदी की ओर था, जहां देश के हजारों गणमान्य व्यक्ति मंदिर दर्शन करने पहुंचे हुए थे। कांग्रेस के मौजूदा अपरिपक्त नेतृत्व के गलत फैसले के कारण कांग्रेस की यह स्थिति पैदा हुई कि उन्हें प्राण प्रतिष्ठा के बायकाट की भरपाई के लिए रास्ते का मंदिर ढूंढना पड़ा। जैसे देशभर से हर क्षेत्र के गणमान्य लोग प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में पहुंचे, उसका चुनावों पर असर पड़ने की पूरी संभावना है। जिसका सर्वाधिक असर भाजपा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बिहार, बंगाल और महाराष्ट्र में पड़ेगा, जहां भाजपा इंडिया गठबंधन के मुकाबले खुद को कमजोर पा रही है। 22 जनवरी को जो वातावरण बना है, उसे चुनाव तक बनाए रखने के लिए भाजपा ने 24 जनवरी से श्रीराम जन्मभूमि दर्शन अभियान शुरू कर दिया है। यह अभियान आने वाले दो महीनों तक चलेगा।

अयोध्या में देशभर से लोगों को रामलला के दर्शन करवाने के लिए लाया जाएगा, जिसके लिए भाजपा ने 20 हजार लोगों को रोज रुकवाने की व्यवस्था कर ली है। क्योंकि दर्शनार्थी देशभर से आएंगे, इसलिए सभी प्रदेशों से 200 से ज्यादा कार्यकर्ता उन्हीं की भाषा में उनका स्वागत और संवाद करने के लिए दो महीनों तक अयोध्या में तैनात रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 11 दिन के व्रत के दौरान चार दिन तक दक्षिण भारत के मंदिरों में पूजा पाठ करके दक्षिण में भी भाजपा के लिए अलख जगाने का काम किया है। इसमें कोई शक नहीं कि भाजपा श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण को राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है, और करेगी भी। कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियों को भाजपा के तीनों पुराने मुद्दों के विरोध का खामियाजा 2024 में भुगतना पड़ेगा। इन पांच वर्षों में भाजपा ने तीन में से दो मुद्दे पूरे कर दिए हैं। इन्हीं पांच सालों में कश्मीर से 370 भी खत्म हो गई और श्रीराम जन्मभूमि पर रामलला का मंदिर भी बन गया। अब कांग्रेस या विपक्षी दल कितना भी कहें कि रामजन्मभूमि मंदिर तो कोर्ट के फैसले से बना है, कांग्रेस के ही नेता आचार्य प्रमोद कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री न होते, तो श्रीराम जन्मभूमि पर मंदिर नहीं बनता। और यही आम हिंदुओं की धारणा भी है। उद्धव ठाकरे को भी महाराष्ट्र में चुनावी असर का आभास है, इसलिए उनकी पार्टी यह भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है कि मंदिर उस स्थान पर नहीं, उससे चार किलोमीटर दूर बना है। बिहार में हाल ही में हुए एक सर्वेक्षण में कहा गया है कि श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के कारण भाजपा को छह प्रतिशत वोट ज्यादा मिल सकता है। अगर बिहार जैसे जाति आधारित राजनीति वाले प्रदेश में इतना असर पड़ सकता है, तो बाकी प्रदेशों में उससे भी ज्यादा असर की संभावना बनती है, जो विपक्ष के लिए बहुत ही घातक साबित होगी।

हिंदू वोट बैंक के एकतरफा भाजपा के समर्थन में आ जाने के कारण भाजपा को पहली बार पूर्ण बहुमत मिला था। एके एंटनी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में पहली बात यह कही थी कि कांग्रेस की छवि हिंदू विरोधी पार्टी की बन गई है, इसलिए कांग्रेस को जनता ने ठुकरा दिया। कांग्रेस को इस रिपोर्ट पर मंथन करके खुद की छवि सुधारने की कोशिश करनी चाहिए थी, लेकिन हुआ इसके उलट। कांग्रेस के महासचिव जनार्दन द्विवेदी को इसलिए किनारे कर दिया गया क्योंकि उन्होंने कहा था कि मोदी को रोकने में कांग्रेस विफल रही। जनार्दन द्विवेदी कांग्रेस में अंतिम हिंदूवादी चेहरा थे, जिन्होंने 2014 के लोकसभा चुनावों से पहले ही हार की इबारत पढ़ ली थी। जनार्दन द्विवेदी ने फरवरी 2014 में ही कह दिया था कि कांग्रेस को 2009 में सत्ता से अलग होकर दूसरों को सरकार बनाने देनी चाहिए थी। 2009 से 2014 की कांग्रेस की पारी उसके लिए बेहद नुकसानदायक साबित हुई। इस अवधि में एक तरफ जमकर भ्रष्टाचार हुआ, तो दूसरी तरफ अल्पसंख्यक तुष्टिकरण ने कांग्रेस की छवि हिंदू विरोधी और मुस्लिम पार्टी की बना दी थी। लोकसभा चुनावों के बाद राहुल गांधी का बयान भी इसकी पुष्टि करता था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो लोग मंदिर जाते हैं, वही महिलाओं से छेड़खानी करते हैं। एके एंटनी की रिपोर्ट से सबक लेते हुए 2017 के गुजरात विधानसभा चुनावों में राहुल गांधी ने हिंदू देवी-देवताओं और मंदिरों के बारे में अपनी धारणा में बदलाव किया था। उन्होंने मंदिरों में जाकर हिंदू देवी-देवताओं के दर्शन किए, जिसका कांग्रेस को फायदा भी हुआ। कांग्रेस की सीटें 61 से बढ़कर 77 हो गईं और भाजपा की सीटें 115 से घटकर 99 रह गईं।

● विपिन कंधारी

राहुल गांधी की सॉफ्ट हिंदू लाइन

2011 में सॉफ्ट हिंदू लाइन अपनाते हुए राहुल गांधी ने मंदिर दर्शन अभियान चलाया था। उन्होंने खुद को शिवभक्त घोषित किया, मानसरोवर यात्रा पर भी गए। पुष्कर जाकर ब्रह्मा की पूजा करते हुए खुद को ब्राह्मण और अपना गोत्र दतात्रेय बताया, जनेऊ भी धारण किया। लेकिन श्रीराम जन्मभूमि मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का आमंत्रण अस्वीकार करके नेहरू परिवार ने हिंदुओं को अच्छा सिग्नल नहीं दिया। नेहरू परिवार यह समझ नहीं पाया कि श्रीराम जन्मभूमि को वापस हासिल करने के लिए हिंदुओं ने लगभग 500 सालों में 76 बार संघर्ष किए, जिनमें से ज्यादातर जमीनी संघर्ष थे। लाखों रामभक्तों ने अपने बलिदान दिए, 70 साल तक कानूनी लड़ाई लड़ी, ढांचे के नीचे खुदाई में मंदिर के अवशेष मिले, तब जाकर हिंदुओं को अपनी पवित्र भूमि वापस मिली। नेहरू परिवार को श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का बायकाट करने से पहले हिंदुओं के पक्ष को सुनना चाहिए था। सारा देश इंतजार कर रहा था कि राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान 22 जनवरी को कुछ ऐसा करेंगे कि हिंदुओं की नाराजगी किसी हद तक दूर हो। लेकिन राहुल गांधी का दोहरापन उस समय उजागर हो गया था, जब गुजरात विधानसभा चुनाव के ठीक बाद संगठन में बची एकमात्र हिंदुओं की आवाज जनार्दन द्विवेदी को कांग्रेस महासचिव पद से हटा दिया गया।

भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले हुए हैं। इस बार उन्होंने यह यात्रा पूर्वोत्तर के राज्य मणिपुर से शुरू की है। यात्रा में भीड़ उमड़ रही है। इस भीड़ को देखकर कांग्रेस उत्साहित है, लेकिन उसके सामने भारत जोड़ो यात्रा के परिणाम भी हैं। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की थी तो दावे किए गए थे कि इससे कांग्रेस को बड़ा फायदा पहुंचेगा। लेकिन यात्रा का असर मप्र, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बिलकुल नहीं दिखा। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि लोकसभा चुनाव में यात्रा कितनी प्रभावी रहेगी।

न्याय यात्रा कितनी प्रभावी

राहुल गांधी की न्याय यात्रा मणिपुर से चल पड़ी है और यह यात्रा मुंबई तक पहुंचेगी। लेकिन राहुल गांधी के मणिपुर से रवाना होते ही मुंबई में धमाका हो गया। मिलिंद देवड़ा का कांग्रेस छोड़ना, उसी दिन हुआ जिस दिन राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की। कांग्रेस इससे इतनी जल-भुन गई कि जयराम रमेश ने इसका ठीकरा नरेंद्र मोदी के सिर फोड़ दिया। उन्होंने कहा कि मिलिंद देवड़ा के कांग्रेस छोड़ने की टाइमिंग नरेंद्र मोदी ने तय की है। वैसे इस बयान का कोई लॉजिक नहीं है। मिलिंद देवड़ा की कांग्रेस छोड़ने की टाइमिंग मोदी ने तय की होती, तो वह भाजपा में जाते, शिवसेना में क्यों गए। मिलिंद देवड़ा कांग्रेस की दूध देने वाली गाय थी। उनका कांग्रेस छोड़ना कोई छोटी-मोटी घटना नहीं है। उन्होंने कांग्रेस छोड़कर कांग्रेस की रीढ़ पर हथौड़ा मारा है।

1991 में जब उदारीकरण की शुरुआत हुई, तब से पहले उनके पिता मुरली देवड़ा और बाद में मिलिंद कांग्रेस और कॉरपोरेट घरानों के बीच कड़ी का काम कर रहे थे। कांग्रेस सरकारों के समय कॉरपोरेट घरानों को फायदा पहुंचाने वाली नीतियों के बदले चंदा उगाने की भूमिका इन दोनों के पास थी। उनके पिता मुरली देवड़ा इसीलिए 22 साल तक मुंबई प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। मिलिंद देवड़ा भाजपा के साथ गठबंधन वाली शिवसेना में शामिल हुए हैं, जिसे हाल ही में असली शिवसेना का प्रमाण पत्र मिला है। यह संयोग ही है कि उनके पिता मुरली देवड़ा 1980 में शिवसेना की मदद से ही मुंबई के मेयर बने थे। मिलिंद देवड़ा के कांग्रेस छोड़ने की भूमिका डेढ़ साल पहले ही तय हो गई थी। 2019 में वह लोकसभा चुनाव हार गए थे। मिलिंद देवड़ा की कांग्रेस को कितनी जरूरत थी, इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि उन्हें ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का सह कोषाध्यक्ष बनाया गया था। इसके बावजूद कांग्रेस ने जून 2022 में उनकी उपेक्षा करके उप्र के इमरान प्रतापगढ़ी को महाराष्ट्र से राज्यसभा में भेज दिया था।

अब जब वह दक्षिण मुंबई की अपनी पुरानी सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे, तो कांग्रेस ने वह सीट समझौते में उद्धव ठाकरे की शिवसेना को देने का फैसला कर लिया। मिलिंद देवड़ा का कांग्रेस छोड़ना ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद, आरपीएन सिंह और सुष्मिता देव जैसा ही महत्वपूर्ण है। ये पांचों कांग्रेस की नई पीढ़ी के नेता थे। हम उम्र होने के कारण राहुल गांधी की कोटरी के सदस्य थे। इनमें से चार मनमोहन सरकार में मंत्री थे, सुष्मिता देव महिला कांग्रेस

राहुल की न्याय यात्रा पर सबकी नजर

राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का ऐलान करते वक्त जब मल्लिकार्जुन खड़गे से नीतीश कुमार को संयोजक बनाए जाने पर सवाल पूछा गया था, तो उन्होंने कहा था कि यह सवाल कौन बनेगा करोड़पति जैसा बन गया है। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि आने वाले 15 दिन में संयोजक और अन्य पदों पर फैसला हो जाएगा। यह संकेत काफी था कि नियुक्ति सिर्फ संयोजक पद की नहीं होगी, कांग्रेस अपने प्री प्लान के मुताबिक ही चेयरमेन का पद अपने पास रखने की रणनीति पर ही काम कर रही है। इसी के बाद नीतीश कुमार ने कह दिया था कि वह किसी पद के इच्छुक नहीं हैं। 13 जनवरी की वर्चुअल बैठक में भी जब संयोजक पद पर उनके नाम का प्रस्ताव आया, तो उन्होंने वही बात दोहराई कि वह किसी पद के इच्छुक नहीं हैं। लेकिन इसे उनकी नाराजगी के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि उनकी पार्टी कुछ और कह रही थी, और वह खुद कुछ और कह रहे हैं। बेंगलुरू की बैठक में लालू यादव और तेजस्वी यादव भी इस बात से नाराज होकर निकले थे कि नीतीश कुमार को संयोजक बनाने का फैसला क्यों नहीं किया जा रहा। जेडीयू ने तो पटना, बेंगलुरू और मुंबई बैठक स्थलों पर नीतीश कुमार को भावी प्रधानमंत्री बताने वाले होर्डिंग तक लगवाए थे।

की राष्ट्रीय अध्यक्ष थीं। पांचों अपने पिता की विरासत से कांग्रेस में आए थे। यानी पांचों का कांग्रेस से दो-तीन पीढ़ियों का रिश्ता था। पहले इस कोटरी की वजह से कई सीनियर कुंठित होकर कांग्रेस छोड़ गए थे। अब उस कोटरी में से सिर्फ सचिन पायलट ही कांग्रेस में बचे हैं।

राहुल गांधी की यात्रा का श्रीगणेश अपशकुन से हो गया है। इस मौके पर दो नेताओं के बयान बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि जिसे जाना है, जाओ, कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ता। उधर मल्लिकार्जुन खड़गे ने नरेंद्र मोदी के लिए राम नाम सत्य बोल दिया। इन दोनों बयानों में 2024 की पटकथा लिखी जाएगी। राहुल गांधी ने ऐसे मौके पर न्याय यात्रा शुरू की, जब श्रीराम जन्मभूमि मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी। देश के 80 फीसदी हिंदुओं के लिए यह अवसर अति महत्वपूर्ण था, जिसे उन्होंने 500 साल के जमीनी और अदालती संघर्षों के बाद हासिल किया है। पहले रामजन्मभूमि मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का बायकाट और उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा का प्रभाव कम करने के लिए राहुल गांधी की यह यात्रा।

22 जनवरी को जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा था, उस दिन राहुल गांधी असम में थे। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा भी राहुल गांधी से खफा होकर कांग्रेस छोड़कर भाजपा में गए थे। हिमंत बिस्व सरमा की नई हिंदूवादी छवि ने असम में करिश्मा किया है। 35 प्रतिशत मुस्लिम आबादी वाले इस प्रदेश में भाजपा का जीतना करिश्मे से कम नहीं। असम में कांग्रेस अभी भी मुस्लिम भरोसे बैठी है। इसलिए राहुल गांधी की असम यात्रा बहुत ही संवेदनशीलता का मामला है। उनकी यात्रा के दौरान हिंदू-मुस्लिम दंगों की आशंका बनी हुई है। उद्धव ठाकरे पहले ही कह चुके हैं कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के बाद दंगे हो सकते हैं। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ दिखा नहीं है।

राहुल गांधी की बंगाल यात्रा से ममता बनर्जी बेहद कुपित हैं, क्योंकि वह मुस्लिम प्रभाव वाले क्षेत्रों से गुजरेंगे। ममता बनर्जी ने इंडी एलायंस की 13 जनवरी की वर्चुअल बैठक में न तो खुद हिस्सा लिया, न अपने किसी महासचिव को मीटिंग में हिस्सा लेने का निर्देश दिया। हालात ऐसे बन चुके हैं कि संभवत बंगाल में कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस में गठबंधन नहीं होगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी पर हमले तेज कर दिए हैं। ममता बनर्जी समझती हैं कि राहुल गांधी उनके प्रभाव वाली सीटों में सेंध मारने आ रहे हैं। बंगाल के बाद राहुल जब उप्र-बिहार में जाएंगे, तो ये दोनों राज्य राममय हो चुके होंगे। इन दोनों राज्यों में राहुल गांधी की यात्रा का मार्ग भी अति संवेदनशील है। वह मुस्लिम प्रभाव वाले इलाकों से गुजरेंगे, तो उत्तेजना हो सकती है।

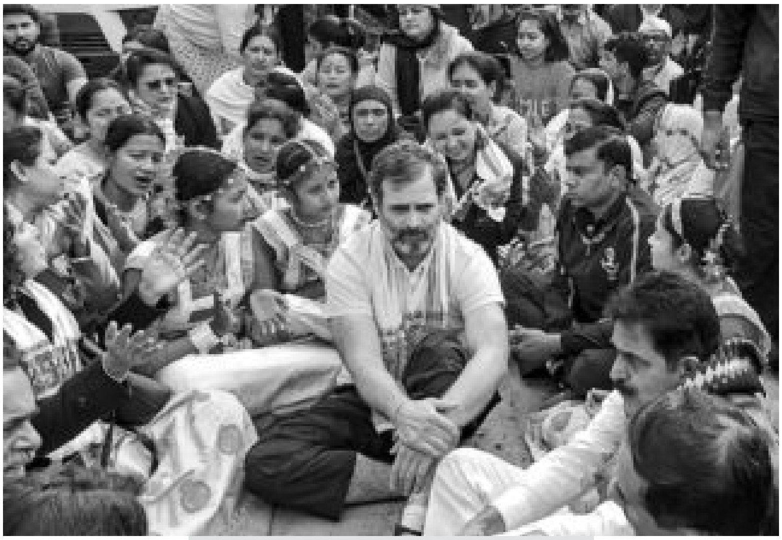

राहुल गांधी मप्र में करेंगे पांच सभाएं

आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस हर बड़े वर्ग को साधने की कोशिश कर रही है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी मप्र में पांच बड़ी जनसभाएं अलग-अलग क्षेत्रों में करेंगे। कहीं बेरोजगारों की तो कहीं किसान, आदिवासी, अनुसूचित जाति वर्ग और महिलाओं की सभाएं होंगी। पार्टी सभाओं की तैयारी में जुट गई है। हर स्तर पर इसके लिए समितियां बनाई गई हैं। प्रत्यके सभा में बड़ी संख्या में भीड़ जुटाने का लक्ष्य है। मणिपुर से शुरू हुई राहुल गांधी की न्याय यात्रा फरवरी के अंतिम सप्ताह मप्र में मुरैना से प्रवेश करेगी। यह यात्रा सात लोकसभा क्षेत्रों से गुजरेगी। पहली सभा ग्वालियर-चंबल में बेरोजगारों की होगी। वजह यह कि इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में युवा अग्निवीर, अर्ध सैनिक बल और पुलिस में भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। यहां अग्निवीर और पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं से राहुल गांधी बात करेंगे। राजगढ़ या आसपास किसी स्थान पर किसान महासभा करने की तैयारी है। कारण यह कि इस क्षेत्र में किसानों की संख्या अधिक है। रतलाम और आसपास के जिलों में आदिवासियों की बहुतायत संख्या होने के कारण राहुल गांधी यहां आदिवासी न्याय सभा करेंगे।

कांग्रेस लालू यादव और नीतीश कुमार से बिहार में 10 से 12 सीटें मांग रही है। लालू यादव 4-5 से ज्यादा देने की स्थिति में नहीं हैं। 2019 में जब जेडीयू गठबंधन में नहीं थी, तब लालू यादव ने कांग्रेस को 9 सीटें लड़ने को दी थी, लेकिन कांग्रेस मुस्लिम बहुल किशनगंज ही जीत पाई थी। जबकि लालू यादव की आरजेडी तो एक सीट भी नहीं जीत पाई थी। इसलिए नीतीश कुमार इंडी गठबंधन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उनके बिना लालू और राहुल दोनों ही जीरो हैं। लेकिन नीतीश कुमार नाराज हुए बैठे हैं। भले ही सार्वजनिक तौर पर एक-दूसरे के खिलाफ बयानबाजी नहीं हो रही, लेकिन एक-दूसरे पर तंज कसने वाली भाषा का इस्तेमाल हो रहा है।

13 जनवरी की मीटिंग में जब राहुल गांधी ने संयोजक पद के लिए नीतीश कुमार का नाम प्रस्तावित किया, तो उन्होंने प्रस्ताव ठुकराते हुए कहा कि लालू प्रसाद यादव को संयोजक बना दीजिए। अब सब जानते हैं कि चारा घोटाले में सजायाफ्ता और जॉब फॉर लैंड घोटाले में चार्जशीट लालू यादव को संयोजक बनाकर इंडी एलायंस अपना राम नाम सत्य नहीं करना चाहेगा। इसलिए जैसे ही नीतीश कुमार ने लालू यादव का नाम लिया, मीटिंग में सन्नाटा छा गया। नीतीश कुमार और लालू यादव में शीत युद्ध शुरू हो गया है। नीतीश कुमार इशारों-इशारों में अभी भी राजग के प्रति झुकाव के संकेत दे रहे हैं। कांग्रेस की तरह उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बायकाट का ऐलान नहीं किया था।

दूसरा प्रमाण यह है कि गत दिनों जब नीतीश कुमार ने एक लाख शिक्षकों की भर्ती के अपॉइंटमेंट लेटर दिए तो होर्डिंग में तेजस्वी का फोटो हटा दिया गया। जबकि 15 लाख नौकरियों का वादा करने वाले तेजस्वी यादव नौकरियों का श्रेय ले रहे हैं। मंच पर भाषण देते हुए नीतीश कुमार के मंत्री विजय चौधरी का कहना है कि पिछली सरकार (एनडीए सरकार) में जब वह शिक्षा मंत्री थे, तभी इन नौकरियों की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। जबकि इन नियुक्ति पत्रों के वितरण के बाद आरजेडी ने एक प्रेस कांफ्रेंस की, जिसमें श्रेय लेते हुए कहा गया कि पिछले 15 महीने की गठबंधन सरकार बिहार का स्वर्णिम काल है।

● इन्द्र कुमार

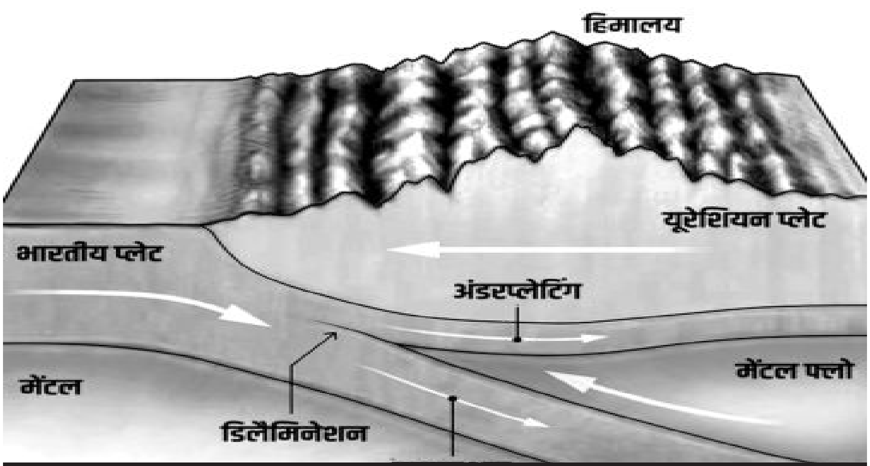

पाताल की ओर जा रही भारतीय प्लेट

भारतीय टेक्टोनिक प्लेट दो टुकड़ों में बंट रही है। एक हिस्सा चीन के नीचे जा रहा है। दूसरा हिस्सा पाताल में। इस वजह से हिमालय में और हिमालय से बड़ा भूकंप आने की पूरी आशंका है। अगर ऐसा होता है तो भारी तबाही होगी। भारत, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, तिब्बत और भूटान जैसे देशों में बड़ी आपदा आएगी। भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट की टक्कर से हिमालय बना है। अब भारतीय प्लेट का एक हिस्सा यूरेशियन प्लेट के अंदर धंस रहा है। यानी भारतीय प्लेट दो हिस्सों में बंट रही है। पहला हिस्सा तो यूरेशियन प्लेट के अंदर है। दूसरा हिस्सा धरती के मेंटल में जा रहा है। यानी पाताल की तरफ। डिलैमिनेशन वाला दरार करीब 100 से 200 किलोमीटर लंबी है। जहां तेजी से मेंटल का बहाव भी दिखाया जा रहा है। वह भी भारतीय प्लेट की तरफ है। यह सब ऊर्जा के तेज बहाव पैदा कर रहे हैं। बहुत सारी एनर्जी इनसे निकल रही है। साथ ही स्टोर हो रही है। ये एनर्जी जब तेजी से निकलती है तगड़े भूकंप आते हैं। इसी एनर्जी की वजह से हिमालय की ऊंचाई हर साल बढ़ रही है। ऊपर इनकी गति कम दिखती है लेकिन जमीन के अंदर जंग चल रही है।

भारतीय टेक्टोनिक प्लेट और यूरेशियन प्लेट का टकराव 6 करोड़ साल पहले शुरू हुआ था। उसके पहले भारत एक आईलैंड यानी द्वीप था। जो जाकर यूरेशिया से भिड़ गया। जब दो जमीनें एकसाथ टकराए तो हिमालय का निर्माण हुआ। जमीन के ऊपर हिमालय बना और अंदर रहस्य बनते रहे। वैज्ञानिकों का मानना है कि भारतीय टेक्टोनिक प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे जा रही है। जिसके दबाव से यह दो टुकड़ों में रही है। इसे डीलैमिनेशन कहते हैं। लेकिन ऊपरी हिस्सा यानी यूरेशियन प्लेट ऊपर उठ रहा है, फैल रहा है। इससे हिमालय की ऊंचाई बढ़ रही है। जियोडायनेमिसिस्ट डुवे वान हिंसबर्गेन कहते हैं कि हमें अब तक नहीं पता है कि दो महाद्वीप आपस में किस तरह से व्यवहार करते हैं। लेकिन बेहद डरावना और हैरान करने वाला है। अगर यह दरार तेजी से बढ़ी तो हिमालय से और हिमालय में कई सारे भूकंप आ सकते हैं। मोनाश यूनिवर्सिटी के जियोडायनेमिसिस्ट फैबियो कैपितानो ने कहा कि यह सिर्फ एक ट्रेलर है। पूरी फिल्म आनी बाकी है। हम स्टडी कर रहे हैं। ताकि ज्यादा से ज्यादा जानकारी जमा कर सकें। हम भूगर्भीय अस्थिरता की स्टडी कर रहे हैं। अभी तक ऐसा देखने को नहीं मिला था कि कोई इतनी बड़ी टेक्टोनिक प्लेट दो हिस्सों में टूटी हो। जैसा भारतीय प्लेट के साथ हो रहा है। यह एक बेहद मोटी महाद्वीपीय प्लेट है, जिसे आप बड़ी चट्टानी परत भी बोल सकते हैं। यह पाताल में जा रही है।

एरिजोना यूनिवर्सिटी के जियोलॉजिस्ट पीटर डेसेलेस ने कहा कि अगर भारतीय प्लेट के टूटने की स्टडी सही से करनी है तो हमें हिमालय की उत्पत्ति पर नजर रखनी होगी, शोध करनी होगी। हिमालय के 2500 किलोमीटर लंबे रेंज के नीचे की स्टडी करनी होगी। भारतीय प्लेट एक समान मोटाई या चौड़ाई वाली नहीं है। कहीं पतली है तो कहीं मोटी। यह लगातार यूरेशियन प्लेट में जा रही है। जो आकार में इससे बड़ी है। यूरेशियन प्लेट अपनी ताकत से इसे दबा रही है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के जियोफिजिसिस्ट साइमन क्लेमपरर का कहना है कि भारत की टेक्टोनिक प्लेट किसी कपड़े के टुकड़े की तरह है, जिसके धागों को चारों तरफ से खींचा और धकेला जा रहा है। भूटान के नीचे सबडक्शन जोन है। यहीं पर चीजें बुरी होती नजर आ रही हैं। जमीन के अंदर भारतीय टेक्टोनिक प्लेट के साथ बड़े पैमाने पर हिंसा हो रही है।

तिब्बत की कई जगहों पर ऐसे जलस्रोत हैं, जहां पर हीलियम-3 आइसोटोप देखने को मिले। दक्षिणी तिब्बत के 1000 किलोमीटर में फैले 200 प्राकृतिक जलस्रोतों के सैंपल लिए गए। यानी जमीन के अंदर से हीलियम निकलकर बाहर आ रहा है। ऐसा भारतीय प्लेट के मेंटल की ओर जाने से हो रहा है। क्योंकि भूटान के पूर्वी सीमा की तरफ भी हीलियम निकलने की घटनाएं देखने को मिली हैं। यह बताता है कि भारतीय प्लेट दो टुकड़ों में टूट रही है। भारतीय प्लेट का निचला हिस्सा लगातार मेंटल में धंस रहा है। यह प्रक्रिया तिब्बत के नीचे हो रही है। इस स्टडी को करने के लिए वैज्ञानिकों ने भारतीय और यूरेशियन प्लेट के टक्कर वाली जगह पर भूकंपीय तरंगें भेजीं। फिर उनसे मिले डेटा से यह स्टडी की। भूकंपीय तरंगों ने साफ बताया कि भारतीय प्लेट फट रही है। लेहाई यूनिवर्सिटी की सीस्मोलॉजिस्ट एनी मेल्टजर कहती हैं कि भारतीय प्लेट के टूटने की घटना की जमीनी सतह से 200 किलोमीटर नीचे हो रही है। मेंटल वाले इलाके के पत्थर भारतीय प्लेट पर बहकर 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक आ चुके हैं। यह तय है कि अगले कुछ हजार सालों में इस इलाके में बड़े भौगोलिक बदलाव होने वाले हैं।

यह बात पूरी दुनिया को पता है कि भारतीय प्लेट लगातार यूरेशियन प्लेट को धकेल रही है, उत्तर की तरफ बढ़ रही है। वहीं तिब्बत के दक्षिण में 90 डिग्री नीचे लिथोस्फेयर-एस्थेनोस्फेयर बाउंड्री है। वहीं पर ये हलचल हो रही है। यारलंग-जांग्बो दरार से 100 किमी दूर उत्तर की तरफ दरारें बननी शुरू हुई हैं। ये तिब्बत के नीचे हैं। पूर्व की तरफ भारत के नीचे का मेंटल के पास ग्रैविटी के असर से ऊपरी हिस्सा सेपरेट हो रहा है। यादोंग-गुलू और कोना-सांगरी रिफ्ट में हीलियम आइसोटोप की तीव्रता बढ़ी है। यानी धरती के केंद्र से हीलियम आ रहा है। इसके अलावा इस इलाके में लगातार भूकंप आ रहे हैं। जिससे भारतीय टेक्टोनिक प्लेट और तेजी से टूट रही है।

● सिद्धार्थ पांडे

हिमाचल की नदियां सूखी

हिमाचल प्रदेश में पिछले तीन महीनों से सूखे की स्थिति बनी हुई है। हिमाचल से निकलने वाली उत्तर भारत की कई प्रमुख नदियों सतलुज, ब्यास, यमुना, रावी और चिनाब में पानी का स्तर कम हो गया है। पीने के पानी के स्रोत तक सूखने लगे हैं। कई इलाकों में पानी की आपूर्ति बाधित हो गई है और प्रशासन को पानी की राशनिंग करनी पड़ रही है। पर्यावरण एवं ग्लेशियर विशेषज्ञ और हिमाचल प्रदेश विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण परिषद में प्रधान वैज्ञानिक एसएस रंधावा ने बताया कि सर्दियों के दिनों में दिसंबर और जनवरी माह में पड़ी बर्फ लंबे समय तक जमी रहती है।

क्यों शांत है वसुंधरा राजे

आपको वो दिन याद है जब राजस्थान में सीएम फेस की घोषणा होनी थी। तारीख थी, 12 दिसंबर 2023 और दिन था मंगलवार, भाजपा के दिग्गज नेता बैठे हुए थे। राजनाथ सिंह थे। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे थीं। वसुंधरा राजे ने ही पर्ची खोली और सामने नाम आया भजनलाल शर्मा। इसके बाद ये वीडियो खूब वायरल हुई, और वसुंधरा के हाव-भाव क्या थे, ये कहने की जरूरत नहीं, पर अब राजनीतिक गलियारों में ये सवाल उठ रहा है कि वसुंधरा राजे चुप क्यों हैं।

राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे कोई नया विकल्प तलाश रही हैं? राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा जोरों पर है। अटकलों का बाजार इसलिए गर्म हुआ कि वसुंधरा राजे लोकसभा चुनाव के लिए बुलाई गई पहली बैठक से दूर रहीं। यही नहीं राजस्थान में 3 दिसंबर को रिजल्ट के बाद बड़े कार्यक्रमों से वसुंधरा राजे ने दूरी बना ली थी। वसुंधरा राजे कैंप के तरफ से कोई प्रतिक्रिया भी नहीं आ रही है। सियासी जानकार इसे तूफान के पहले की शांति बता रहे हैं। इस बार भजनलाल शर्मा कैबिनेट में वसुंधरा राजे के करीबियों को एंट्री नहीं मिली है। सियासी जानकारों का कहना है कि माना यही जा रहा है कि मुख्यमंत्री नहीं बनाए जाने से वसुंधरा राजे नाराज हैं। हालांकि, वसुंधरा राजे चुप हैं। हाव भाव से भी संकेत नहीं मिल रहे हैं कि राजस्थान की राजनीति में क्या होने जा रहा है।

सियासी जानकारों का कहना है कि वसुंधरा राजे सचिन पायलट की स्टाइल में चुप हैं। पायलट भी सत्ता मिलने के बाद 2 साल तक चुप रहे। पायलट ने 2020 में ही बगावत की थी। सियासी जानकारों का कहना है कि अभी तक वसुंधरा राजे ने ऐसे कोई संकेत नहीं दिए हैं, जिससे यह अंदाजा लगाया जा सके कि राजस्थान में बगावत हो सकती है। लेकिन वसुंधरा राजे के करीबियों का कहना है कि वसुंधरा राजे पार्टी के कार्यक्रमों से दूर ही रहेंगीं। क्योंकि पार्टी ने जिस तरह से उनकी अनदेखी की है, वह उनके कद काठी के हिसाब से ठीक नहीं है। राजस्थान भाजपा में वसुंधरा राजे के कद काठी का कोई नेता नहीं है। वसुंधरा राजे में ही सभी समाज को एकसाथ लेकर चलने की क्षमता है। सियासी जानकारों का कहना है कि भाजपा की असली परीक्षा लोकसभा चुनाव में होगी। क्योंकि इस बार वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री नहीं बनाए जाने से भाजपा का कोर वोट बैंक राजपूत समाज नाराज बताया जा रहा है। विधानसभा चुनाव के हिसाब से कांग्रेस को 11 लोकसभा सीटों पर बंपर जीत मिली थी। जबकि भाजपा 14 लोकसभा सीटों पर आगे रहीं थी। भाजपा लगातार राजस्थान में 25 सीटों को जीतती आ रही है। लेकिन सियासी जानकारों का कहना है कि इस बार मुकाबला कांटे का है।

राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि वसुंधरा राजे सही मौके के इंतजार में हैं। वैसे ही जैसे मप्र में उनके भतीजे और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया तलाश में थे। वैसे ही जैसे गहलोत के शासन में सचिन पायलट। सियासी जानकारों का कहना है कि राजनीति में कुछ भी स्थाई नहीं होता है, कब क्या हो जाए। किसी ने नहीं सोचा कि पहली बार ही विधायक बनने वाले भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री बन जाएंगे। सियासी जानकारों का कहना है कि वसुंधरा राजे की चुप्पी तक ही राज रहेगा। जिस दिन राजे की चुप्पी टूटी राजस्थान की राजनीति में खेला हो सकता है।

राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल का राज आते ही अब सियासत की फिजा भी बदल गई है। दो बार की मुख्यमंत्री रह चुकीं वसुंधरा राजे के अब राजस्थान में युग समाप्त होने को लेकर जमकर चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से एक रात पहले ही भाजपा कार्यालय से वसुंधरा राजे की फोटो लगे हुए होर्डिंग्स उतार दिए गए। पिछले कई सालों तक इन होर्डिंग्स पर वसुंधरा राजे और भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़ की फोटो दिखाई देती थी। लेकिन अब सियासत बदल चुकी है, तो चेहरे भी बदल गए हैं। वहीं वसुंधरा की फोटो हटाने के साथ सियासत में उनके युग के अंत होने की जमकर चर्चाएं हो रही हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने बीती देर शाम भाजपा विधायक और पदाधिकारी से संवाद किया। इस संवाद कार्यक्रम में वसुंधरा राजे नदारद रही। जिसको लेकर सियासत में कई मायने निकाले जा रहे हैं।

● जयपुर से आर.के. बिन्नानी

धार्मिक पर्यटन की धुरी बनता उप्र

उप्र ने बीते दो सालों में जिस तेजी से धार्मिक पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित किया है, उससे साफ जाहिर है कि धार्मिक पर्यटन के लिहाज से आने वाला दशक उप्र का है। जिस राज्य की पहचान मुगल धरोहरों से होती थी, उस राज्य की नई पहचान अब अयोध्या, काशी, मथुरा और विंध्याचल जैसे श्रद्धा एवं आस्था के केंद्र बन गए हैं। उप्र धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। सदियों तक बदहाल रहे अयोध्या, काशी और मथुरा के जीर्णोद्धार ने इस राज्य को नई पहचान दी है। जिसका सकारात्मक असर राज्य की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ रहा है।

उप्र में धार्मिक पहचान रखने वाले जिलों में पर्यटकों की संख्या, उन जिलों के अनुपात में ज्यादा बढ़ी है, जो ऐतिहासिक पहचान रखते हैं। धार्मिक पर्यटन ने राज्य में रोजगार की नई संभावनाओं को जन्म दिया है। ढांचागत एवं बुनियादी सुविधाओं में निवेश तेज हुआ है। बीते एक दशक में उप्र में पर्यटन के आंकड़े देखें तो वर्ष 2020-21 तक आगरा पर्यटकों का सबसे पसंदीदा शहर रहा है। प्रतिवर्ष 1 करोड़ से ज्यादा पर्यटक आगरा आते रहे हैं। अन्य जिलों में यह आंकड़ा लाखों तक सिमटकर रह जाता था, लेकिन वर्ष 2021-22 से बनारस पर्यटकों का सबसे पसंदीदा शहर बन गया है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद से बनारस आने वाले पर्यटकों की सख्या में तेजी से इजाफा हुआ है।

वर्ष 2021-22 में 31.85 करोड़ पर्यटक उप्र आए। इस वर्ष पहली बार बनारस ने पर्यटकों के मामले में आगरा को पीछे छोड़ दिया। आगरा में जहां 1.03 करोड़ पर्यटक पहुंचे, वहीं बनारस में पर्यटकों की संख्या 8.06 करोड़ को पार कर गई। मथुरा में 6.53 करोड़, प्रयागराज में 2.60 करोड़, अयोध्या में 2.39 करोड़ पर्यटक आए। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो जाने के बाद इस आंकड़े में और तेजी आएगी। अनुमान लगाया जा रहा है कि राम मंदिर निर्माण पूर्ण होने के बाद धार्मिक पर्यटन के लिहाज से अयोध्या राज्य का सर्वाधिक तेजी से बढ़ने वाला जिला बन जाएगा। धार्मिक पर्यटन में श्रीराम मंदिर निर्माण के पूर्व ही उप्र ने सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं।

धार्मिक पर्यटन में दशकों से अग्रणी रहे तमिलनाडु को उप्र ने बनारस के बल पर पीछे छोड़ दिया है। तमिलनाडु में 2022-23 में लगभग 22 करोड़ पर्यटक पहुंचे थे, जिसे केवल काशी और मथुरा पहुंचे 23 करोड़ पर्यटकों की बदौलत उप्र ने पीछे कर दिया है। उप्र धार्मिक पर्यटकों के मामले में नंबर एक हो गया है। इस वर्ष उप्र में 36.58 करोड़ से ज्यादा पर्यटक आए। बीते एक दशक से तमिलनाडु रामेश्वरम और कन्याकुमारी जैसे धार्मिक स्थलों की बदौलत धार्मिक पर्यटन में नंबर वन रहा है। इस साल रामेश्वरम में 10 करोड़, कन्याकुमारी में 7 करोड़, धनुषकोड़ी में 4 करोड़ तथा वन्य अभयारण्य में एक करोड़ पर्यटक पहुंचे। इस अवधि में उप्र के काशी में 12 करोड़, मथुरा में 11 करोड़, अयोध्या में 6 करोड़ प्रयागराज में 4.58 करोड़, विंध्याचल में 1.6 करोड़ श्रद्धालु पर्यटक पहुंचे। आगरा में भी एक करोड़ पर्यटक पहुंचे। वर्ष 2016 में उप्र आने वाले सैलानियों की संख्या 21.67 करोड़ थी, जो 2022-23 में बढ़कर 36.58 करोड़ तक पहुंच गई है। बीते एक दशक में उप्र के पर्यटन आंकड़ों को देखें तो आगरा पर्यटकों का सबसे पसंदीदा शहर रहा है। 2021 तक यही स्थिति बनी रही। बनारस में यह आंकड़ा 75 लाख तक था, लेकिन 2022 के बाद परिस्थिति बदल चुकी है। बनारस उप्र का सबसे ज्यादा पर्यटकों के पसंद वाला जिला बन चुका है। यह संभव हुआ है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर निर्माण के बाद।

उम्मीद है कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण हो जाने के बाद ना केवल उप्र की पहचान बदलेगी बल्कि धार्मिक पर्यटन में और ज्यादा उछाल आएगा। ताजमहल से पहचाने जाने वाले प्रदेश की नई पहचान काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के बाद अयोध्या श्रीराम जन्मभूमि होने जा रहा है। केंद्र की मोदी सरकार एवं उप्र की योगी आदित्यनाथ की सरकार जिस तरह से अयोध्या का जीर्णोद्धार कर रही है, उस लिहाज से यह शहर ही नहीं आसपास के पिछड़े जिलों को भी संजीवनी मिलेगी। अयोध्या से सड़क कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी और एयर कनेक्टिविटी बेहतर होने से अयोध्या उप्र के धार्मिक, आर्थिक एवं सामाजिक विकास का इंजन बनेगा। इसके लिए केवल अयोध्या में एयरपोर्ट ही नहीं शुरू हुआ है। अयोध्या रेलवे स्टेशन के साथ अयोध्या कैंट और दर्शन नगर स्टेशनों का भी विकास किया जा रहा है।

● लखनऊ से मधु आलोक निगम

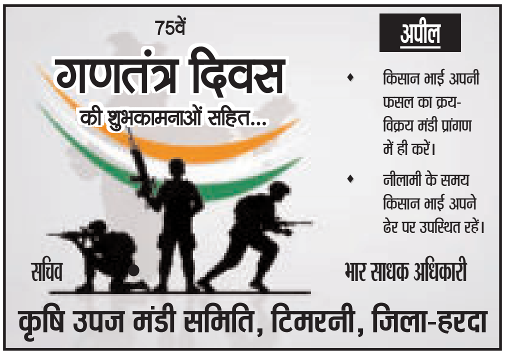

40 सीट, 6 दावेदार...

बिहार में नीतीश कुमार फिर से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) में लौट आए हैं। नीतीश ने कहा है कि जहां से गए थे, वहीं लौट आए हैं। अब इधर-उधर जाने का सवाल ही नहीं है। नीतीश कुमार की एनडीए में वापसी से सत्ता की तस्वीर बदल गई है तो साथ ही बदल गया है गठबंधन का गणित और वोटों का समीकरण भी। बदल गया है सूबे की 40 लोकसभा सीटों का गणित भी। नीतीश के साथ आने से सीट शेयरिंग के मोर्चे पर भाजपा की टेंशन भी बढ़ गई है। कुछ ही महीने में लोकसभा चुनाव होने हैं लेकिन इससे पहले ही नीतीश के पाला बदलने से बिहार की लोकसभा सीटों का गणित पूरी तरह से बदल गया है। चंद रोज पहले तक एनडीए की 23 सीटों के मुकाबले विपक्षी इंडिया 17 सीटों के साथ करीब-करीब बराबरी वाली स्थिति में था। लेकिन नीतीश के एनडीए में जाने के बाद यह गणित बदल गया है। बिहार में लोकसभा की 40 सीटों के लिए एनडीए में छह दावेदार हैं। भाजपा और जेडीयू दो बड़ी पार्टियों के साथ ही एलजेपी के दो धड़े, मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को एडजस्ट कर पाना एनडीए के लिए आसान नहीं होगा। बिहार विधानसभा के ताजा नंबर गेम से मांझी की अहमियत बढ़ गई है और उनकी पार्टी भी कम से कम दो सीटें चाहती है। एलजेपी के दोनों धड़े सात-सात सीटों की डिमांड कर रहे हैं तो वहीं उपेंद्र कुशवाहा भी 2014 की तर्ज पर तीन सीटों की दावेदारी कर रहे हैं। ऐसे में सीट शेयरिंग पर एनडीए में कैसे सहमति बनती है, यह देखने वाली बात होगी।

जनता दल से अलग होकर 1994 में जॉर्ज फर्नांडिस और नीतीश कुमार ने समता पार्टी की शुरुआत की। 1996 के लोकसभा चुनावों में समता पार्टी ने भाजपा के साथ गठबंधन किया। समता पार्टी को इस लोकसभा चुनाव में आठ सीटों पर जीत मिली। इनमें से छह बिहार में और एक-एक उप्र और ओडिशा में थी। 1998 के आम चुनावों में भाजपा के साथ गठबंधन में समता पार्टी ने 12 सीटें जीतीं। इनमें बिहार से 10 और उप्र से दो सीटें शामिल थीं। मार्च 2000 में नीतीश कुमार को बिहार के मुख्यमंत्री पद के लिए एनडीए का नेता चुना गया। उन्होंने केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी के कहने पर पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। 324 सदस्यीय सदन में एनडीए और सहयोगी दलों के पास 151 विधायक थे जबकि लालू प्रसाद यादव के पास 159 विधायक थे। दोनों गठबंधन बहुमत के आंकड़े यानी 163 से कम थे। सदन में बहुमत साबित नहीं कर पाने के चलते नीतीश ने इस्तीफा दे दिया। महज सात दिन बाद ही वह सत्ता से बाहर हो गए। 2003 नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली समता पार्टी का पहले ही कई टुकड़ों में बंट चुके जनता दल में विलय हो गया। विलय की गई इकाई को जनता दल (यूनाइटेड) नाम मिला और राज्य में एक नई पार्टी अस्तित्व में आई। 2005 में बिहार में विधानसभा चुनाव हुए। इस चुनाव के लिए पहली बार भाजपा और जदयू को चुनावी सफलता हासिल हुई। 243 सदस्यीय विधानसभा में इस चुनाव में भाजपा ने 55 सीटें जबकि जदयू ने 88 सीटें जीतीं। राजद के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार को हराने के बाद जदयू नेता नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने। 2009 के लोकसभा चुनाव में भी गठबंधन को बड़ी सफलता मिली। 40 लोकसभा सीटों वाले बिहार में जदयू 25 और भाजपा 15 सीटों पर लड़ी। इनमें से 32 सीटों पर इस गठबंधन को सफलता मिली। भाजपा के 15 में से 12 उम्मीदवार जीतने में सफल रहे। वहीं, जदयू के 25 में से 20 उम्मीदवार जीतकर लोकसभा पहुंचे। साल 2010 में बिहार विधानसभा चुनाव हुए। भाजपा-जदयू ने एक बार फिर एक साथ चुनाव लड़ा और जबरदस्त सफलता हासिल की। इस जीत के साथ नीतीश एक बार फिर राज्य के मुख्यमंत्री बने। 2014 में भाजपा से गठबंधन तोड़ने के बाद भी नीतीश की पार्टी सत्ता में बनी रही। उनकी पार्टी की सरकार को राजद और कांग्रेस ने बाहर से समर्थन दिया।

● **विनोद बक्सरी**

सीट शेयरिंग के मोर्चे पर बढ़ी चुनौती

एनडीए के लिए अब सीट शेयरिंग के मोर्चे पर चुनौती बढ़ गई है। दरअसल, पिछले दो लोकसभा चुनावों की चर्चा करें तो एनडीए में एक बार नीतीश की पार्टी नहीं थी तो दूसरी बार उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी। इस बार जब ये सभी दल साथ हैं तो सीट शेयरिंग कैसे होगा, क्या फॉर्मूला होगा? नीतीश के एनडीए में आने से पहले तक यह कहा जा रहा था कि सीट शेयरिंग 2014 के फॉर्मूले पर हो सकती है। हालांकि, इसमें भी चुनौती यह थी कि एलजेपी तब एकजुट थी और अब इसके दो धड़े हैं। दोनों ही धड़े 7-7 सीट की डिमांड कर रहे थे। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में बिहार की 40 में से 30 सीटों पर भाजपा ने उम्मीदवार उतारे थे। एलजेपी ने सात, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ने तीन सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे।

75वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाओं सहित...
सचिव ● भार साधक अधिकारी
कृषि उपज मंडी समिति, नर्मदापुरम, जिला - नर्मदापुरम

75वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाओं सहित...
सचिव ● भार साधक अधिकारी
कृषि उपज मंडी समिति, पचोर, जिला - राजगढ़

26 जनवरी
75वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाओं सहित...
सचिव ● भार साधक अधिकारी
कृषि उपज मंडी समिति, कुरावर, जिला - राजगढ़

75वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाओं सहित...
सचिव ● भार साधक अधिकारी
कृषि उपज मंडी समिति, ब्यावरा, जिला - राजगढ़

पिस रहे हैं बलूच

पाकिस्तान और ईरान के बीच टकराव की संक्षिप्त कहानी यह है कि घोषित रूप से ईरान ने पाकिस्तान स्थित बलूची आतंकवादी ग्रुप जैश अल अदल के दो ठिकानों को नष्ट करने के लिए हमले किए, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने ईरान के अंदर अलगाववादी आतंकवादियों पर हमले कर दिए। एक-दूसरे पर हमले के साथ तेहरान और इस्लामाबाद ने अपने-अपने राजदूत वापस बुला लिए। दोनों देशों की आपसी सीमा 900 किमी लंबी है और दोनों तरफ अब भी तनाव है। लेकिन दोनों के बीच कोई पहली बार झड़प नहीं हुई है। एक साल के अंदर ही दोनों तरफ से कई आतंकवादी हमले हुए हैं। दिसंबर 2023 में ही जैश अल-अदल ने दक्षिणपूर्वी सीमा प्रांत स्थित ईरानी शहर रस्क में एक पुलिस स्टेशन पर हमला कर 11 सुरक्षाकर्मियों को मार डाला था। जून 2023 में पाकिस्तानी सेना की मीडिया शाखा आईएसपीआर ने यह आरोप लगाया था कि बलूचों ने धावा बोलकर दो पाकिस्तानी सैनिकों की हत्या कर दी। अप्रैल 2023 में भी आईएसपीआर ने यही कहा था कि ईरान के हमलावरों ने केच जिले के जलगाई सेक्टर में गश्ती कर रहे चार सैनिकों की हत्या कर दी। सितंबर 2021 में भी पाकिस्तान ने दावा किया था कि ईरान की ओर से सीमा पार से की गई गोलीबारी में एक सैनिक की मौत हो गई।

ईरान और पाकिस्तान के बीच तनाव और सहयोग दोनों का इतिहास रहा है। दोनों ओर से दहशतगर्दी के लिए बलूच विद्रोहियों को ही दोषी बताया जा रहा है। ईरान विरोधी बलूच आतंकवादी समूह जैश अल-अदल पर पकिस्तान में पनाह लेने का आरोप लग रहा है तो सरमाचर बलूच ईरान की भूमि से पाकिस्तान के खिलाफ हमले के लिए जिम्मेदार ठहराए जा रहे हैं। हमले दोनों तरफ से हो रहे हैं, इसलिए दोनों देश अब एक-दूसरे पर हमलावर होने की भूमिका में हैं। कभी ईरान और पाकिस्तान मिलकर भारत और अमेरिका के खिलाफ कूट रचनाएं रचते रहे हैं। ईरान ने भारत के खिलाफ 1965 और 1971 के युद्ध में पाकिस्तान की खुलकर सहायता की थी। अयातुल्ला खुमैनी ने ईरान में अति-रूढ़िवादी शिया शासन को स्थापित किया तो उसी समय पाकिस्तान सैन्य तानाशाह जनरल जिया-उल-हक ने सुन्नी-बहुसंख्यक नजरिए के साथ पाकिस्तान का इस्लामीकरण किया। 1979 के बाद पाकिस्तान और ईरान के बीच अविश्वास की एक दीवार खड़ी हुई, जिसका मुख्य कारण अमेरिका रहा। इस्लामाबाद अमेरिका का सहयोगी बन गया और तेहरान अमेरिका का विरोधी। 9/11 के बाद यह खाई और चौड़ी हो गई जब पाकिस्तान ने अपने यहां अमेरिकी फौज को मिलिट्री बेस प्रदान कर आतंकवाद के खिलाफ बड़े ऑपरेशन चलवा दिए।

इसके अलावा अरब देशों के साथ पाकिस्तान के बढ़ते रणनीतिक संबंधों ने भी ईरान को पाकिस्तान से दूरी बढ़ाने में मदद की। फिर अफगानिस्तान से सोवियत सेना की वापसी के बाद तो पाकिस्तान और ईरान एक-दूसरे के सामने खड़े हो गए। 1998 में मजार-ए-शरीफ में कट्टरपंथी सुन्नी मिलिशिया द्वारा शिया हजारा और आठ ईरानी राजनयिकों की हत्या के बाद दोनों देशों में एक बार युद्ध की स्थिति बन गई थी। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की जब-जब सरकार रही, ईरान के साथ दोस्ती आगे बढ़ाने का प्रयास हुआ, लेकिन नवाज शरीफ की पार्टी के दौर में अरब देशों के साथ संबंध सुधारने में ईरान को नजरअंदाज किया गया। लगभग 900 किलोमीटर लंबी ईरान-पाकिस्तान सीमा, जिसे गोल्डस्मिथ लाइन भी कहा जाता है, पर दोनों तरफ मुख्य रूप से बलूच रहते हैं। उनकी संख्या लगभग 90 लाख है। एक तरफ पाकिस्तानी प्रांत बलूचिस्तान है तो दूसरी तरफ ईरानी प्रांत सिस्तान। बलूच आज भी कबीलाई जिंदगी बसर कर रहे हैं। पाकिस्तान में पंजाबी मुसलमानों के मुकाबले वे जातीय अल्पसंख्यक समूह हैं।

ईरान में जो बलूच हैं वे वहां भी अल्पसंख्यक हैं और उनके सुन्नी होने के कारण ईरान के शासकों द्वारा उन्हें खूब सताया जाता है। ईरान में बलूच आबादी का 80 प्रतिशत हिस्सा गरीबी रेखा के नीचे है।

● ऋतेन्द्र माथुर

हूतियों का बढ़ता आतंक

15 जनवरी को भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तेहरान के विदेश मंत्री एच अमीरब्दुल्ला से मुलाकात की। यह मुलाकात हूतियों द्वारा लाल सागर में भारत की ओर आने वाले मालवाहक जहाजों को निशाना बनाने को लेकर थी। पिछले दो महीनों में दो दर्जन से ज्यादा व्यापारिक जहाजों को ऐसे हमलों का सामना करना पड़ा है। अमेरिका का दावा है कि इन सभी हमलों के पीछे यमन के हूती आतंकियों का ही हाथ है।

तेहरान में हुई इस मुलाकात से उम्मीद की जानी चाहिए कि मालवाहक जहाजों पर हूती आतंकियों के हमले रुकेंगे। परोक्ष रूप से यमन में हूतियों पर ईरान का ही नियंत्रण है और समझा जाता है कि ईरान के दखल देने के बाद यमन में सक्रिय हूती लाल सागर में अपनी आतंकी गतिविधियों पर लगाम लगाएंगे। क्योंकि बीते साल दिसंबर के आखिरी हफ्ते में जहाज एमवी साईंबाबा पर आतंकियों द्वारा ड्रोन से हमले की घटना ने इस समस्या को बहुत गहरा दिया है। इस घटना के कुछ ही घंटे पहले एक और जहाज एमवी चेम प्लूटो पर हवाई हमला हुआ था, जिसकी वजह से उसमें आग लग गई थी।

● **कुमार विनोद**

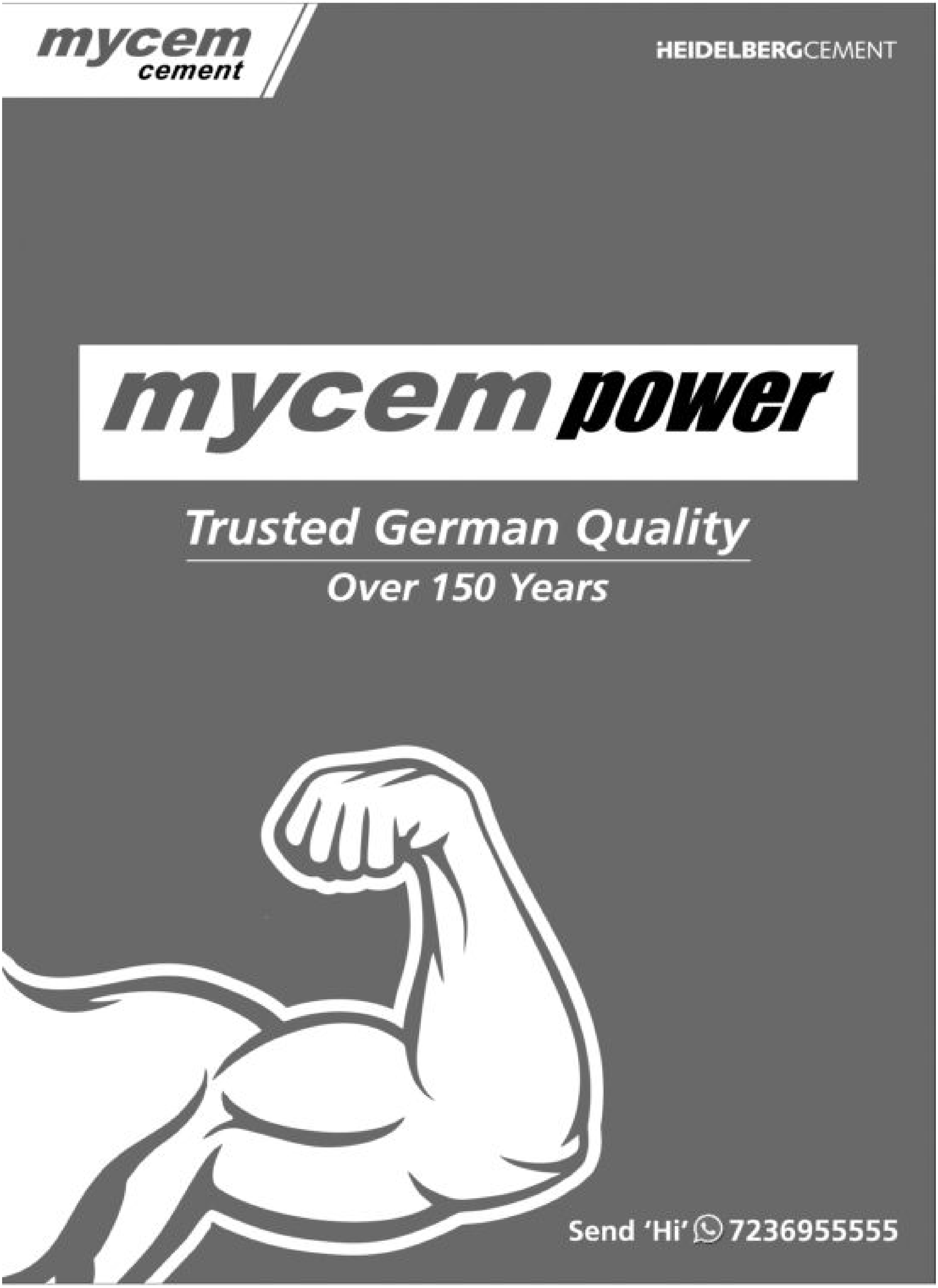
mycem cement
HEIDELBERGCEMENT
mycem power
Trusted German Quality
Over 150 Years
Send 'Hi' 7236955555

भिखारी

विद्यालय के वार्षिक जलसे में शिक्षा मंत्री ने शहर के जाने-माने उद्योगपति को बुलाया गया था। बार-बार घोषणा हो रही थी कि, आज के अति विशिष्ट अतिथि बस कुछ ही देर में पधार रहे हैं। दर्शक दीर्घा के आगे की पंक्ति में कई पत्रकार बैठे थे। सबके मन में मुख्य अतिथि को एक नजर देखने की उत्कंठा बढ़ती ही जा रही थी।

अचानक एक किशोरवय बालक ने मंच पर आकर क्षमा याचना करते हुए अपने पिताजी के तरफ से माफी मांगी- उपस्थिति गणमान्य एवं परम आदरणीय सभी सुधिजनों से मैं अपने पिता जी की ओर से क्षमा याचाना की आशा करता हूं। उनकी तबीयत अस्वस्थ है, इसीलिए आप सबके बीच उपस्थित नहीं हो सकेंगे। यह कहते हुए, भीड़ और कोलाहल की ओर ध्यान दिए बगैर वह वापस जिस कार से आया था, उसी में जाकर पिछली सीट पर बैठ गया।

उसके पिता बंद गाड़ी में पहले से बैठे थे, वह उनसे मुखातिब होते हुए बोला- अच्छा किए पिताजी, आप मंच पर नहीं जाकर।

अरे बेटा; सच में मैं आज स्वयं को अस्वस्थ महसूस कर रहा हूं।

जो भी हो, चैरिटेबल संस्था के नाम पर आपको लूटने वाले भिखारियों की वहां जमात बैठी थी।

- आरती रॉय

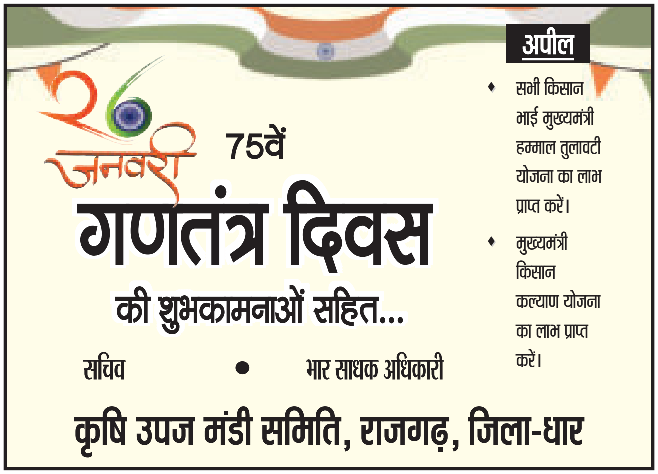

हमारे देश में क्रिकेट एक ऐसा खेल बन गया है जिसे खेल प्रेमी सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। इनका यह प्रेम तब और बढ़ गया जब वर्ष 2007 में इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल की शुरुआत हुई। यह लीग खेलों में सबसे महंगी लीग के साथ ही अब दुनिया की सबसे लोकप्रिय लीग भी बन गई है। इस लीग से कई ऐसे खिलाड़ी उभरकर आए हैं जो अब देश का नाम रौशन कर रहे हैं। इस बीच खबर है कि आईपीएल का 17वां संस्करण 22 मार्च से खेला जा सकता है। ऐसे में इसकी तैयारी में तेजी आ गई है। इसी के तहत पिछले महीने आईपीएल नीलामी 2024 के लिए खिलाड़ियों की बोली लग चुकी है, जहां ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज और गेंदबाज पर जमकर पैसा बरसा। ये खिलाड़ी इतने महंगे बिके कि आईपीएल इतिहास के सभी रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए। दूसरी ओर इस आईपीएल से पहले सबसे ज्यादा चर्चा मुंबई इंडियंस फ्रेंचाइजी के उस फैसले की हो रही है जिसमें पांच बार आईपीएल चैंपियन मुंबई इंडियंस की कप्तानी से रोहित शर्मा को हटा दिया गया और हार्दिक पांड्या को बिना देर किए कप्तान भी घोषित कर दिया गया। लेकिन हार्दिक पांड्या पिछले साल के अंत में खेले गए एक दिवसीय आईसीसी वर्ल्डकप से ही चोटिल चल रहे हैं।

टीम इंडिया में हुई पोस्टर वॉर की एंट्री

कयास लगाए जा रहे थे कि वे वर्तमान में अफगानिस्तान के खिलाफ खेली जा रही तीन मैचों की टी-20 सीरीज टीम में वापसी कर सकते हैं, मगर उन्हें टीम में जगह नहीं मिलने से चोटिल माना जा रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि मुंबई इंडियंस का अगला कप्तान कौन होगा? क्या रोहित शर्मा को फिर से टीम की कमान दी जाएगी? क्या वे इस जिम्मेदारी को स्वीकार करेंगे? या फिर किसी अन्य खिलाड़ी को टीम की कमान सौंपी जाएगी? इस बीच जबसे इंग्लैंड के खिलाफ पांच मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले दो मैचों के लिए टीम इंडिया ऐलान हुआ है तब से कहा जा रहा है कि मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस दोनों फ्रेंचाइजियों में पोस्टर वॉर की एंट्री भी हो गई है। मुंबई इंडियंस ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट्स एक्स से भारतीय टीम को साझा किया तो पोस्टर से रोहित की तस्वीर ही गायब कर दी। पोस्टर में केएल राहुल, जसप्रीत बुमराह और श्रेयस अय्यर की तस्वीर साझा की गई। ऐसा करते ही एक बार फिर सोशल मीडिया पर रोहित के फैंस सक्रिय हो गए हैं। कहा जा रहा है कि मुंबई इंडियंस द्वारा भारतीय टीम के कप्तान रोहित की तस्वीर पोस्टर पर नहीं लगाना बहुत कुछ कह गया है। भले ही दोनों में से कोई भी खुलकर कुछ भी नहीं कह रहा है लेकिन रोहित और मुंबई इंडियंस के बीच सब कुछ ठीक नहीं होने की पुष्टि होती दिख रही है। इसका अंदाजा हाल ही में गुजरात टाइटंस के पोस्टर से भी समझा जा सकता है। जिस तरह गुजरात ने अपने पोस्ट में रोहित शर्मा और शुभमन गिल की तस्वीर लगाई इससे भी यही समझ में आया कि गुजरात की टीम रोहित को रिझाने में जुटी है। यहां तक कहा जा रहा है कि आईपीएल की ट्रेड विंडो नीलामी के बाद से खुली है अगर विवाद बढ़ा तो रोहित के मुंबई से गुजरात जाना महज औपचारिकता रह जाएगी। खेल विश्लेषकों का कहना है कि एक कहावत है, जहां आग लगती है वहीं धुआं उठता है। वर्तमान में यह कहावत मुंबई इंडियंस पर सटीक साबित होती दिख रही है। हार्दिक पांड्या के गुजरात से मुंबई में वापसी के बाद से पांच बार की चैंपियन मुंबई के टीम में जाने से हलचल स्वाभाविक है। क्योंकि हार्दिक की मुंबई इंडियंस में वापसी होते ही रोहित शर्मा की कप्तानी से छुट्टी हो गई।

● आशीष नेमा

रेखा पर जान देते थे अमिताभ... तो इस सुपरस्टार के लिए धड़कता था जया बच्चन का दिल

अमिताभ बच्चन की पर्सनल लाइफ पर हमेशा ही उनके फैंस की नजर रही है। उनसे जुड़ी हर बात के बारे में शंहशाह के फैंस जानना चाहते हैं। एक दौर था जब बी-टाउन में बॉलीवुड अभिनेत्री रेखा से उनके अफेयर के चर्चे जोरों पर थे। हर तरफ यही चर्चा थी कि अमिताभ बच्चन रेखा पर जान देते हैं। दोनों की ऑनस्क्रीन केमेस्ट्री भी दर्शकों के बीच खूब पसंद की जाती थी। अमिताभ बच्चन और रेखा से जुड़े चर्चों के बारे में तो सभी को जानकारी है। लेकिन, अमिताभ बच्चन से पहले जया बच्चन के दिल में कौन बसता था, क्या आपको इस बात की जानकारी है? जी हां, अमिताभ बच्चन से पहले जया बच्चन को बॉलीवुड के किसी और ही सुपरस्टार पर क्रश था।

जया बच्चन ने इस सुपरस्टार को लेकर अपनी पसंदगी का खुलासा भी खुद ही किया था। वैसे तो अभिनेत्री अपने तेज तर्रार अंदाज के लिए जानी जाती हैं। अभिनेत्री को अक्सर पैप्स पर नाराज होते देखा गया है। ऐसे में शायद ही किसी की उनसे सवाल करने की हिम्मत हो। लेकिन, अभिनेत्री ने खुद ही एक बार खुलासा किया था कि वह बॉलीवुड के एक स्टार पर फिदा थीं।

दिग्गज अभिनेत्री जिस सुपरस्टार पर फिदा थीं वह कोई और नहीं रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में नजर आए धर्मेंद्र थे। जया बच्चन ने इस फिल्म में धर्मेंद्र के साथ काम किया और एक घमंडी महिला का किरदार निभाया था। जया बच्चन ने धर्मेंद्र के साथ गुड्डी फिल्म में भी काम किया था, जो 1971 में रिलीज हुई थी।

10 साल तक किया स्ट्रगल, 1 मूवी ने चमकाई किस्मत, फिर तरक्की देख देव आनंद बोले- मुझे भी फिल्में दिलवाओ

पुरानी हिंदी फिल्मों में अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना, मिथुन चक्रवर्ती जैसे सितारों के हमशक्ल अक्सर हीरो की एक्टिंग करते हुए दिख जाते हैं। एक ऐसे डुप्लीकेट हैं, जिन्होंने मशहूर सुपरस्टार की एक्टिंग कर बॉलीवुड में बड़ी पहचान बनाई है। उनका नाम है किशोर भानूशाली। दिलचस्प बात ये है कि एक बार खुद सुपरस्टार ने किशोर को अपने ऑफिस बुलाकर काम मांगा था।

किशोर भानूशाली बॉलीवुड के मशहूर सुपरस्टार्स में से एक देव आनंद के डुप्लीकेट हैं। देव आनंद इस दुनिया में तो नहीं हैं, लेकिन किशोर उन्हें अपना आदर्श मानते हैं और उन्होंने फिल्मों में देव आनंद की एक्टिंग कर खूब सुर्खियां बटोरी हैं। उन्होंने दिल, करण अर्जुन और सबसे बड़ा खिलाड़ी जैसी फिल्मों में काम किया है।

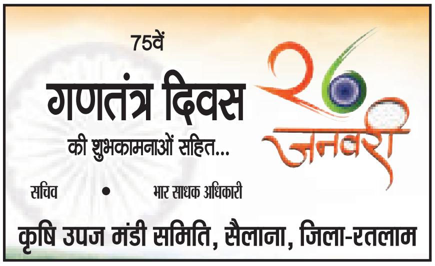

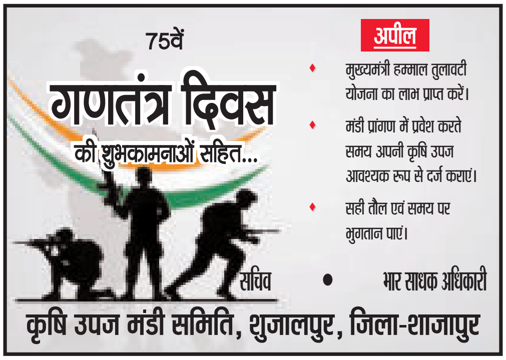

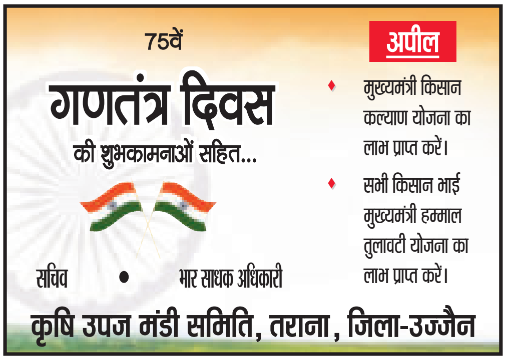

सदी का चौथा बंदर...

ऐसे तो बहुतेरे दुनिया जगत में हर तरफ बंदर है लेकिन दुर्भाग्यवश अपने आप को इंसान समझते हैं। लेकिन गांधी जी के बंदरों की बात ही कुछ और है। जितनी ख्याति गांधीजी के बंदरों को प्राप्त है। उतनी अगर किसी इंसान को मिल जाए तो उसका तो बैठे बिठाए दिमाग ही खराब हो जाए। इंसान की तो बात ही अलग है उसे तो बीमारी है हर छोटी-छोटी बात पर अहंकार में भर जाने की। लेकिन गांधीजी के बंदर इंसान थोड़ी ना है वह जानते हैं जब तक वह कुछ देख-सुन नहीं रहे...बोल नहीं रहे हैं, तभी तक उनकी जय जयकार है। देखना, सुनना, बोलना चालू कर दिए तो लोगों के द्वारा नकार दिए जाएंगे और उनकी जगह पर कोई तुरंत दूसरा आकर काबिज हो जाएगा। इसीलिए गांधीजी के बंदर सोची-समझी रणनीति के तहत ना कुछ बोलते हैं, ना सुनते हैं, ना देखते हैं। अपने देश में ऐसे बंदरों की बहुतायत है।

गांधीजी का पहला बंदर कहता है बुरा मत देखो...अब बताइए भला यह भी कोई मानने वाली बात है। आप कहीं पर सत्यनारायण की कथा कहवा दीजिए देखिए उसमें कितने लोग बिना बुलाए आते हैं और कुछ तो इतने बंदर होते हैं कि बुलाने पर भी नहीं आते हैं। लेकिन वही कहीं पर मारपीट हो रही है तो वहां पर लोगों की संख्या देख लीजिए... और सारे बिना बुलाए आते हैं। उसके बाद भी यह कहना कि बुरा मत देखो काफी असंगत बात है। तो गांधीजी का पहला बंदर तो इस दुनिया के लिए किसी काम का नहीं है। गांधीजी का दूसरा बंदर कहता है बुरा मत सुनो... सुनना बहुत ही उच्च कोटि का कार्य है और आज की पीढ़ी इतने उच्च कार्य नहीं करती है कि वह किसी की सुनने जाए... अरे वह तो अपने आप की भी नहीं सुनती है उसका दिमाग कहता रहता है कि पढ़ोगे-लिखोगे तो बनोगे नवाब और रील बनाओगे तो जिंदगी हो जाएगी खराब... लेकिन उसके बावजूद आज की पीढ़ी रील बनाने पर ही लगी हुई है। जब वह अपने आप की नहीं सुनती तो दूसरे की क्या खाक सुनेगी।

तीसरा बंदर कहता है बुरा मत बोलो... आजकल बोलने कहां दिया जाता है कि लोग बोलें... हर कोई बड़ा सोच समझकर ही आजकल के जमाने में बोलता है। क्योंकि रिकॉर्डिंग का जमाना है... आप इधर कुछ अर्थ बोले और उधर कुछ उसमें अनर्थ जोड़कर आपकी खटिया खड़ी कर दी जाएगी। इसीलिए जिसको बोलना है वह भी चुप है और जो सुनकर पक चुका है वह भी चुप है। आजकल सबसे खतरनाक कम बोलना ही है बोलने के लिए मुंह में जुबान नहीं कलेजे में दम चाहिए। और इस जमाने में आपका दम निकालने के लिए हजारों तरीके हैं इसीलिए बोलने की बात भूल जाइए। अगर आपकी जुबान में ज्यादा ही खुजली हो रही है तो अपने आप को ही सुना लीजिए औरों को सुनाने की बात छोड़ दीजिए।

गांधीजी के तीन बंदरों के अलावा इस सदी को एक चौथा बंदर भी मिल गया है। जो सिर्फ अपने मोबाइल में व्यस्त रहता है... वह ना बुरा देखता है... ना बुरा सुनता है... और ना बुरा कहता है। यह चौथा बंदर तो ऐसा है जो ना इधर देखता है ना उधर देखता है, ना सुनता है ना बोलता है, बस अपने आप में मगन रहता है।

● **रेखा शाह आरबी**

75वें
गणतंत्र दिवस
की शुभकामनाओं सहित...
सचिव ● भार साधक अधिकारी
कृषि उपज मंडी समिति खातेगांव, जिला-देवास
अपील
- सही तौल एवं समय पर भुगतान पाएं।
- किसान भाई अपनी फसल का क्रय-विक्रय मंडी प्रांगण में ही करें।
- नीलामी के समय किसान भाई अपने ढेर पर उपस्थित रहें।

75वें
गणतंत्र दिवस
की शुभकामनाओं सहित...
सचिव ● भार साधक अधिकारी
कृषि उपज मंडी समिति, नीमच
अपील
- किसान भाई अपनी फसल का क्रय-विक्रय मंडी प्रांगण में ही करें।
- नीलामी के समय किसान भाई अपने ढेर पर उपस्थित रहें।
- मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का लाभ प्राप्त करें।

75वें
गणतंत्र दिवस
की शुभकामनाओं सहित...
सचिव ● भार साधक अधिकारी
कृषि उपज मंडी समिति, मंदसौर
अपील
- मुख्यमंत्री हम्माल तुलावटी योजना का लाभ प्राप्त करें।
- मंडी प्रांगण में प्रवेश करते समय अपनी कृषि उपज आवश्यक रूप से दर्ज कराएं।
- सही तौल एवं समय पर भुगतान पाएं।

75वें
गणतंत्र दिवस
की शुभकामनाओं सहित...
सचिव ● भार साधक अधिकारी
कृषि उपज मंडी समिति, महिदपुर, जिला-उज्जैन
अपील
- सही तौल एवं समय पर भुगतान पाएं।
- मंडी प्रांगण में प्रवेश करते समय अपनी कृषि उपज आवश्यक रूप से दर्ज कराएं।

75वें
गणतंत्र दिवस
की शुभकामनाओं सहित...
सचिव ● भार साधक अधिकारी
कृषि उपज मंडी समिति, बड़नगर, जिला-उज्जैन
अपील
- मुख्यमंत्री हम्माल तुलावटी योजना का लाभ प्राप्त करें।
- मंडी प्रांगण में प्रवेश करते समय अपनी कृषि उपज आवश्यक रूप से दर्ज कराएं।
- सही तौल एवं समय पर भुगतान पाएं।

मोदी की गारंटी
यानी गारंटी पूरी होने की गारंटी
मध्यप्रदेश का उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा कदम
पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस
मध्यप्रदेश में हर जिला मुख्यालय पर चिन्हित एक शासकीय महाविद्यालय का पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के रूप में उन्नयन, इसके लिए ₹ 460 करोड़ का प्रावधान
महाविद्यालयों में सभी प्रकार के पाठ्यक्रम होंगे उपलब्ध
अब 'डीजी लॉकर' से डिग्री और मार्कशीट की उपलब्धता सुलभ
"युवाओं में क्षमताओं का निर्माण कर, उन्हें कौशलवान और रोज़गार सक्षम बनाने में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस अहम भूमिका निभाएंगे।
डॉ. मोहन यादव
मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश

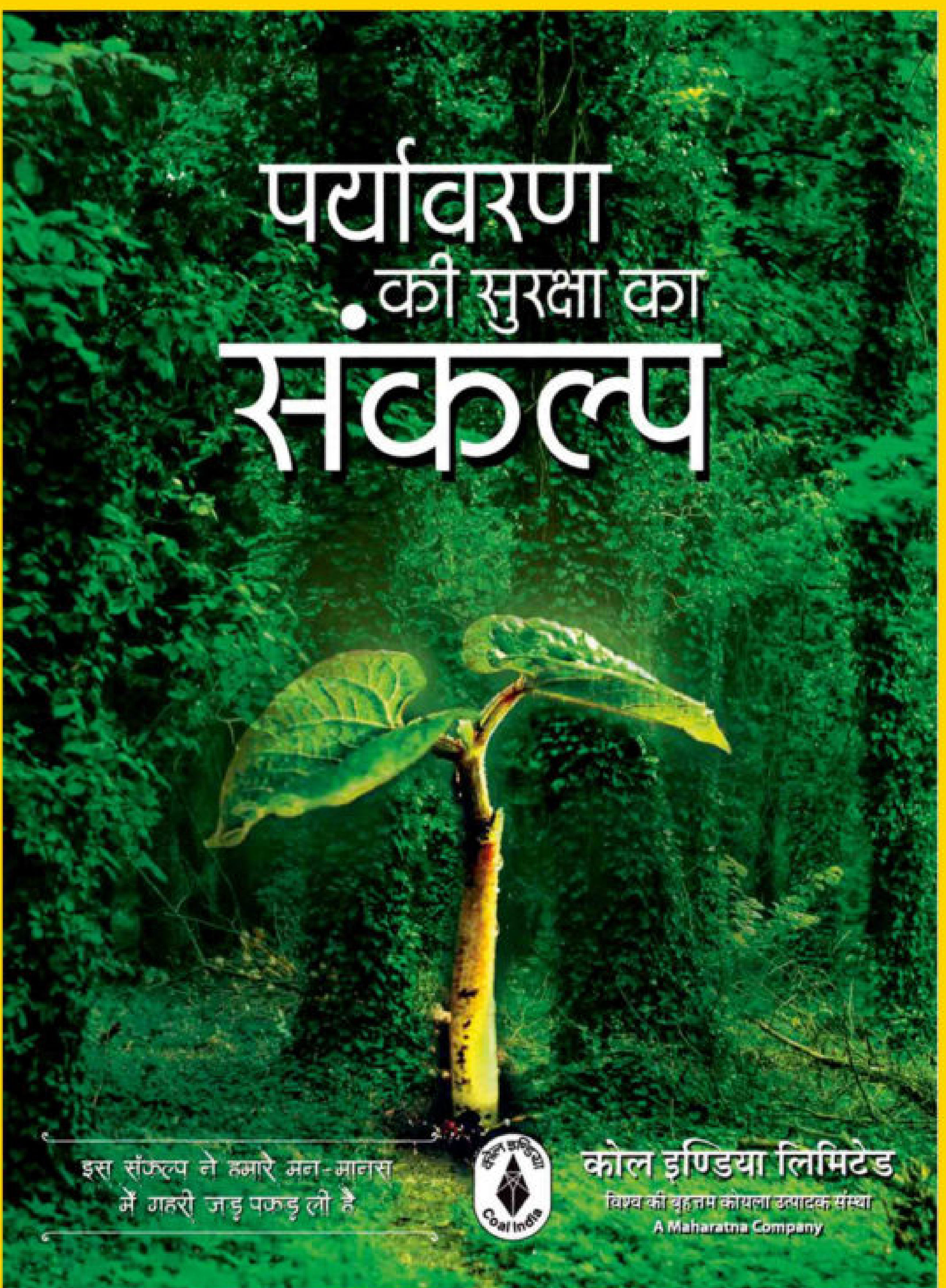
पर्यावरण
की सुरक्षा का
संकल्प
इस संकल्प ने हमारे मन-मानस
में गहरी जड़ पकड़ ली है
Coal India
कोल इण्डिया लिमिटेड
विश्व की वृहत्तम कोयला उत्पादक संस्था
A Maharatna Company
प्रकृति के अस्तित्व में ही हमारा अस्तित्व है